

• आत्मनिर्भर मप्र का रोडमैप • कोरोना में बदल गई मप्र पुलिस

पाक्षिक
अक्ष

In Pursuit of Truth

www.akshnews.com



‘अफसाना-ए-राहत’

वर्ष 18, अंक-22

16 से 31 अगस्त 2020

पृष्ठ-48

मूल्य 25 रुपये

R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/2018-20

अमीदों
का
नया भारत

Anu Sales Corporation

*We Deal in Pathology &
Medical Equipments*



**Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023**

☎ M. : 9329556524, 9329556530, ✉ E-mail : ascbhopal@gmail.com

● इस अंक में

प्रशासनिक

9 | 20-50 का फॉर्मूला

शिवराज सरकार 20-50 के फॉर्मूले पर अमल करने जा रही है। वो 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस चेक करने जा रही है। सरकार सख्ती के मूड में है।

राजपथ

10-11 | वोटकटवा का डर

मप्र में 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। प्रदेश के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा उपचुनाव होगा। इस उपचुनाव से प्रदेश सरकार का भविष्य तय होना है। उपचुनाव में बाजी मारने के लिए दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं।

सम्मान

15 | ये हैं मप्र के श्रेष्ठ विधायक

देश की 31 विधानसभाओं में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 50 विधायकों का चयन हुआ है, जिसमें मध्यप्रदेश के भी चार विधायकों ने जगह बनाई है। इससे पहले जनवरी में प्रदेश के दो आईएएस अफसरों को भी सर्वश्रेष्ठ अफसरों की सूची में स्थान मिल चुका है।

नीति

18 | अब अटल प्रोग्रेस-वे

मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके ग्वालियर और चंबल की तस्वीर को बदलने के लिए बनाए जा रहे अटल प्रोग्रेस-वे (चंबल प्रोग्रेस-वे) के भूमिपूजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। अटल प्रोग्रेस-वे के भूमिपूजन का न्यौता देने के लिए..

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28



देश की आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीदों के नए भारत की तस्वीर दुनिया के सामने रखी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भारत कई मामलों में विश्व का सिरमौर बनेगा। साथ ही उन्होंने भविष्य की दिशा और दशा का भी खाका खींचा। इससे उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में हमारे देश में उम्मीदों का उदय होगा। जिससे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।

13



17



38



41



सियासत

30-31

राम बनाम बाकी सब

राम मंदिर के भूमिपूजन के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि राम मंदिर का मुद्दा राजनीति से गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि भाजपा अभी इसे अपना एजेंडा बताने से लगातार बच रही है, जबकि हकीकत ये है कि राम मंदिर पर सियासत रोकी नहीं जा सकती।

महाराष्ट्र

36

आत्मविश्वास या डर?

26 जुलाई को यानी अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में आए। शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा- 'जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी हो वो आज ही गिराए, अभी इसी दौरान..'

उग्र

37

परशुराम पर राजनीति

उत्तर प्रदेश में इन दिनों हर राजनीतिक दल को ब्राह्मणों की चिंता खूब सता रही है। खासतौर से विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस आए दिन ब्राह्मणों को लेकर कई तरह के वादे करते दिख रहे हैं तो वहीं सत्तादल भाजपा भी अपने इस कोर वोट बैंक को खोना..

6-7

अंदर की बात

40

विदेश

41

महिला जगत

42

अध्यात्म

43

कहानी

45

खेल

46

व्यंग्य



बिकाऊ लोक है और बिकाऊ ही तंत्र है...

वीर रस के कवि वेदव्रत वाजपेयी की ये पक्तियां तो आपने सुनी ही होंगी...

युद्धों में कभी नहीं हारें, हम उरते हैं छलचंदों से।

हर बार पराजय पाई है, अपने घर के जयचंदों से।।

कवि ने ये पक्तियां भारतीय इतिहास की विभंगतियों पर लिखी हैं, लेकिन अब ये हमारे देश की राजनीति पर भी सटीक बैठ रही हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सत्ता के लिए अब सबकुछ बिक रहा है। पिछले कुछ सालों में तो स्थिति यह हो गई है कि सिद्धांतों और सेवा की राजनीति करने वाले माननीयों पर सत्ताभूख इस कदर हावी हुआ है कि वे पाला बदलने में तनिक भी देर नहीं करते हैं। माननीयों की स्थिति का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि उन पर उनकी पार्टी को ही विश्वास नहीं रहता है। राजनीति के बाजार में उन्हें बिकने से बचाने के लिए पिछले कुछ सालों से उन पर अघोषित पहरा बैठाया जा रहा है। लोग तो अब यह कहने लगे हैं कि हमारे देश में दाल, चावल, आटा-मैदा, आलू तो बिकता ही है, हमारे देश के सांसद, विधायक भी इस लोकतंत्र के बाजार में खुलेआम बेचे और खरीदें जाते हैं। बस खरीदार थोड़ा ठीक-ठाक होना चाहिए। माननीय अपने आपको बेचने की खुशी में होटलों के कमरों में बंद हो जाते हैं और उनको इस कलयुग की हर व्यवस्था से पूर्ण कर दिया जाता है। भारतीय राजनीति में खरीदी-बिक्री की यह परंपरा नाबूझ की तरह बढ़ती जा रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के पतन का परिचायक भी है। क्योंकि एक माननीय का बिकना कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि उनके साथ उनकी पार्टी के सिद्धांत और लक्ष्यों मतदाताओं का वोट भी बिकता है। एक माननीय के बिकने पर उस मजदूर, युवा, बेरोजगार और गरीब के आंसू भी बिक जाते हैं जिन्होंने माननीय को यह सौचकर वोट दिया था कि आज के बाद मेरे बच्चे को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, मुझे रोजगार मिलेगा, मेरी समस्याओं का समाधान होगा। माननीय के बिकने के साथ उस अन्नदाता किसान की खुशियां भी बिक जाती हैं, जिन्होंने उनको अपना एक वोट देकर यह सौचकर जितया था कि अब हमारी कर्ज में ढबकर मौत नहीं होगी। चुनाव के दौरान बड़ी-बड़ी बातें करने वाले माननीय जीतने के बाद मदार की बंदर और बंदरिया बन जाते हैं जो उसके उमर के उम-उम और छम-छम की आवाज के साथ नाचने को तैयार हो जाते हैं। यानी वे अपने सिद्धांतों और सेवा की राजनीति को इस कदर भूल जाते हैं कि वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। माननीयों को कौन समझाए कि जनादेश का सम्मान करना लोकतंत्र का प्राण है। जहां जनादेश का सम्मान करने की भावना समाप्त हो जाती है, वहां समझना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि अब पार्टियों को अपने विधायकों और सांसदों पर भी विश्वास नहीं रह गया है। यही कारण है कि अपने लोगों को बिकने से बचाने के लिए पार्टियां उन्हें अपने प्रदेश की बजाय अपनी ही पार्टी द्वारा शासित दूसरे प्रदेशों में कैद (होटल, रिपोर्ट) करके रखती हैं। यह भारतीय राजनीति के पतन की पराकाष्ठा को दर्शाता है। इस कुव्यवस्था का परिणाम आज घातक रूप में हमारे सामने मौजूद है। आज पार्टी कार्यकर्ताओं में से विधायक और सांसद बनने, बनाने को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, अपितु थैली शाह ऊपर से ऊपर ही पार्टी टिकट खरीद लेते हैं। जिस दल के अधिक वोट होते हैं उस दल के प्रत्याशी का मूल्य उतना ही अधिक होता है। अर्थात् 'हर माल मिलेगा ढाई आने' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। नीचे से ऊपर तक सारे गधे-घोड़े बिकाऊ हैं। मतदाता भी मिटाई, शराब, दावत आदि लेकर ईमान बेच डालता है। बिकाऊ लोकतंत्र है अर्थात् बिकाऊ लोक है और बिकाऊ ही तंत्र है।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक
अक्षर

वर्ष 18, अंक 22, पृष्ठ-48, 16 से 31 अगस्त, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जॉन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफैक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718 MPEPL/642/2018-20

बूरो

मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, कोलकाता:- इंद्रकुमार,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, छत्तीसगढ़:- संजय

शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह,

लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संपादकता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथुरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत

098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

देशीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इन्डोलेव मायापुरी-

फोन : 011 25495021, 011 25494676

मुंबई : बी-1, 41 शिव पार्वती चेंबर प्लॉट नंबर 106-110 सेक्टर-21

नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411

कोलकाता : 70/2 हजर रोड कोलकाता

फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446

जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)

फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331

रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,

मोबाइल 094241 08015

इंदौर : 39 बुद्धि सिल्टर निगानिया, इंदौर

मोबाइल - 094251 25096

स्वाधिकाारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 150, जॉन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



आत्मनिर्भर होगा मप्र

केंद्र की मोदी सरकार की ओर से शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप शिवराज सरकार तैयार कर रही है। इसके तहत उन क्षेत्रों की पहचान की जा रही है, जिनमें मध्य प्रदेश लीडर की तरह उभर सकता है।

● रोहित राजपूत, भोपाल (म.प्र.)



किसान हो रहे परेशान

मध्य प्रदेश में हर साल लाखों किसान फसल बीमा कराते हैं वह समय पर प्रीमियम भी भरते हैं। बावजूद इसके उनको बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है और सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी किसान बढहाल और परेशान है। किसानों के कल्याण के नाम पर सरकार तरह-तरह के वादे और दावे करती रही है। उन्हीं में से एक है फसल बीमा योजना लेकिन मध्य प्रदेश में बीमा प्रीमियम भरने के बावजूद हजारों किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में आमदनी दोगुनी कैसे हो पाएगी, यह सवाल किसान पूछ रहे हैं। प्रदेश के कई किसान इससे परेशान हैं।

● आबंद पाठक, सीहोर (म.प्र.)

गरीबों के बारे में सोचे सरकार

कोरोनाविरुद्ध के कारण लगे लॉकडाउन के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कम से कम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कई गंभीर सवालों से आमना हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब किसी विपदा के वक्त पौरी राहत के तौर पर जैसे-तैसे की गई पेट भरने की जुगत से ही गरीबों का कल्याण हुआ मान लिया जाएगा? सरकार को गरीबों के लिए सोचना होगा।

● माधवी शर्मा, नई दिल्ली

बीहड़ में खेती अच्छी पहल

चंबल के बीहड़ में मोदी सरकार ने खेती करवाने की योजना बनाई है। यह एक अच्छी पहल है। सरकार की इस योजना में विश्व बैंक मदद करेगा। सरकार का दावा है कि इस क्षेत्र में खेती-किसानी व पर्यावरण में सुधार होगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा।

● विपुल सिंह, मुरैना (म.प्र.)

छाएगा कर्जमाफी मुद्दा

आने वाले उपचुनाव में किसान कर्जमाफी का मुद्दा भाजपा और कांग्रेस के लिए अहम होगा। कांग्रेस किसानों को दिए अपने वादों के नाम पर वोट मांगेगी, तो वहीं भाजपा भी इस मामले में कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है। उपचुनाव में यह मुद्दा छाया रहेगा।

● अविनाश साद, ग्वालियर (म.प्र.)



मजबूती जरूरी

भाजपा और कांग्रेस प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अपनी-अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। मप्र में ज्योतिरद्वितीय बिधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर जबसे भाजपा में आए हैं, उसके बाद से कई कांग्रेसी विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं और कई नेताओं ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दोनों पार्टियां अपनी-अपनी साख बचाने के लिए विधायकों को लुभाने में लगी हुई हैं।

● राजेन्द्र चौहान, इंदौर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



प्राण जाए पर राजनीति न छूटे

भारत में नेताओं का मूल मंत्र है कि प्राण जाए पर राजनीति न छूटे। चाहे कुछ भी हो जाए राजनीति नहीं रुकनी चाहिए। तभी कोरोनावायरस के संकट, आर्थिक संकट, बाढ़ के प्रकोप के बीच भी राजनीति जारी है। बिहार में तो अगले दो-तीन महीने में चुनाव होने वाले हैं इसलिए वहां की पार्टियों की राजनीतिक बेचैनी समझ में आती है पर दिल्ली में तो अभी नगर निगम का चुनाव भी दो साल बाद होने हैं पर दो साल पहले ही दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जुट गए हैं। दोनों ने 2022 में होने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। कोरोना वायरस के संकट के बीच पहले भाजपा ने कोई 20 नेताओं की एक कमेटी का ऐलान किया। आधिकारिक रूप से बताया गया कि यह कमेटी 2022 में होने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारी करेगी। इसके अगले ही दिन आम आदमी पार्टी ने निगम चुनाव के लिए लोकसभा सीटों के हिसाब से प्रभारी नियुक्त कर दिए। हर लोकसभा सीट का प्रभारी उसके तहत आने वाली नगर निगम की सीटों के लिए तैयारी करेगा। ध्यान रहे दिल्ली के तीनों नगर निगमों में भाजपा का कब्जा है। वह किसी तरह से इसे बचाए रखना चाह रही है पर इस बार आम आदमी पार्टी से उसे पिछली बार से ज्यादा कड़ी टक्कर मिलने का अनुमान है।

ब्राह्मण चेहरे की दरकार

उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक मजबूत ब्राह्मण चेहरे की दरकार है। पार्टी ने वैसे तो दिनेश शर्मा को राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया है पर वे ब्राह्मण समाज में जोश नहीं भर पा रहे हैं। उनसे वह मैसेज नहीं जा सका, जिसकी जरूरत थी। पहले भाजपा के पास डॉ. मुरली मनोहर जोशी जैसा अखिल भारतीय नेता था और कलराज मिश्र का भी चेहरा था। केसरी नाथ त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे नेता भी थे। पर अब ये सारे नेता या तो घर बैठे हैं या राज्यपाल हो गए हैं। यह भी एक तथ्य है कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार में हिंदी पट्टी का कोई ब्राह्मण नेता कैबिनेट मंत्री नहीं है। ब्राह्मण कैबिनेट मंत्री हैं पर वे महाराष्ट्र के या दक्षिण भारत के हैं। इससे भी भाजपा मैसेज नहीं बनवा पा रही है। तभी कहा जा रहा है कि पार्टी को बड़ा ब्राह्मण चेहरा चाहिए। पर सवाल है कि वह चेहरा कौन हो सकता है? अगर केंद्र सरकार किसी ब्राह्मण नेता को बड़ी जिम्मेदारी दे और उसे आगे बढ़ाए तो अपने आप मैसेज बनेगा। पर ले-देकर चर्चा यह है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मध्यप्रदेश का राज्यपाल बनाया जा सकता है या प्रभात झा को झारखंड का राज्यपाल बनाया जा सकता है। बिहार के संगठन महामंत्री नागेंद्र जी को भी कोई अन्य जिम्मेदारी देने की चर्चा है। वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।



बिहारी कालीदास

चुनाव की घोषणा तो अभी तक नहीं हुई पर बिहार के सभी राजनीतिक दल पूरे चुनावी मूड में दिख रहे हैं। विपक्ष के मुकाबले सत्तारूढ़ राजग अलबत्ता ज्यादा सक्रिय लगता है। पर घटक दलों की तनातनी देख हर कोई हैरान है। जनता दल (एकी) जहां रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को अपना सहयोगी स्वीकार करने को तैयार नहीं वहीं लोजपा के मुखिया सांसद चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना का कोई मौका नहीं चूक रहे। पहला विवाद तो चुनाव कराने को लेकर ही है। चिराग पासवान चाहते हैं कि जब तक कोरोना का संक्रमण पूरी तरह नियंत्रित न हो जाए, सूबे में चुनाव आयोग को चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं करना चाहिए। जद (एकी) को चुनाव की जल्दी है। भाजपा अपने पते नहीं खोल रही है। पर भाजपा की ओर से साफ किया जा चुका है कि चुनाव में गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। इसके उलट चिराग पासवान खुद भी मुख्यमंत्री पद की हसरत पाले हैं। इसी चक्कर में वे अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटें पाने की फिराक में लगे हैं। कह भी चुके हैं कि आलाकमान ने 243 में से लोजपा को 42 सीटें देने का भरोसा दे रखा है। उनके पिता रामविलास पासवान भी कह चुके हैं कि चिराग में मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है। लालू और नीतीश को ही नहीं रामविलास तो खुद को भी बीते जमाने का नेता कह चुके हैं।

उपेक्षा का दंश

उत्तराखंड में कांग्रेस के सूबेदार रहे किशोर उपाध्याय दुखी हैं। पार्टी एक तो वैसे ही विपक्ष में है, ऊपर से मौजूदा सूबेदार प्रीतम सिंह भाव नहीं दे रहे। लेकिन उपेक्षित उपाध्याय ने तनाव में होते हुए भी दार्शनिक अंदाज में मीडिया से साफ कहा कि चाहे जितना अपमान हो पर वे रहेंगे कांग्रेस में ही। तिरंगे से ऐसा मोह है कि दुनिया से विदाई भी तिरंगे में लिपटकर ही लेना चाहेंगे। बेचारे किशोर विधानसभा का चुनाव क्या हारे, पार्टी ने हाशिए पर ही धकेल दिया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो किशोर का बड़ा जलवा था। किशोर ने खुद भी चूक कर दी थी। हरीश रावत को अंधेरे में रख हरिद्वार के जयराम आश्रम के संचालक ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी से हाथ मिला लिया था। ऋषिकेश में राहुल गांधी का 2017 में कार्यकर्ता सम्मेलन करा अपना कद ऊंचा उठाने का खेल खेला था। पर हरीश रावत की तरह किशोर और ब्रह्मचारी दोनों ही विधानसभा चुनाव हार गए। इंदिरा हृद्देश और प्रीतम सिंह तब तो भिन्नाकर रह गए थे। अब उनके दिन फिरे तो किशोर को किनारे लगा दिया।

सियासी शिगूफा

अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए कंपनियां बढ़ा-चढ़ा कर दावे करती हैं ग्राहकों को लुभाने के लिए। कानूनी चक्रव्यूह में न फंसे इसके लिए किसी कोने में लगभग अदृश्य शब्दों में लिख देती हैं- शर्तें लागू। पर शर्तें लागू करने का यह सिलसिला अब राजनीति में भी आम हो रहा है। नवजोत कौर सिद्धू ने भी पिछले दिनों इसी तरह का शिगूफा छोड़ दिया। इसी कारण उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। सिद्धू खुद तो चुप्पी साधे हैं पर पत्नी नवजोत कौर ने कह दिया कि भाजपा अगर अकाली दल से नाता तोड़े तो वे भाजपा में वापसी कर सकते हैं। इस शर्त को भाजपा भला क्यों मानेगी? लगे हाथ सिद्धू की डॉक्टर पत्नी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी कर डाली कि मोहल्ला क्लीनिक का प्रयोग काबिले तारीफ है। नवजोत कौर ने परोक्ष रूप से इसका श्रेय खुद भी ले लिया कि सुझाव उन्होंने ही दिया था केजरीवाल को। मौजूदा परिस्थितियों में तो सिद्धू की दाल कहीं गलती नजर नहीं आ रही।

अकेला चना फोड़ रहा भाड़

अपने यहां प्रचलित कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। लेकिन प्रदेश के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया है। साहब जिस विभाग में हैं उसमें दो अन्य आईपीएस अधिकारी भी पदस्थ हैं। लेकिन दोनों अधिकारियों को दरकिनार कर साहब अकेले माल कूटने में लगे हुए हैं। दरअसल, जब इस मामले की पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि पुलिस विभाग में उच्च पद पर आसीन रहे ये साहब हाईकोर्ट द्वारा हनीट्रैप मामले में गठित एक जांच कमेटी के सर्वेसर्वा बने हुए हैं। साहब के साथ दो अन्य आईपीएस अधिकारी भी पदस्थ हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच करने की जिम्मेदारी इन्हें दी है। लेकिन जो बात निकलकर आ रही है, उसके अनुसार बड़े साहब हनीट्रैप में फंसे अधिकारियों को बुलाकर उनका वीडियो दिखाते हैं और उनके फंसे होने का सबूत को मिटाने की एवज में मोटी रकम वसूल रहे हैं। यही नहीं वे खुद निर्णायक बनकर रिपोर्ट बना रहे हैं। जब यह रिपोर्ट उनके साथ कार्य कर रहे अन्य दो अफसरों के पास पहुंचती है तो वे उसकी खामियां देखकर साइन करने से मना कर देते हैं। क्योंकि वे दोनों बेहद ईमानदार हैं। लेकिन साहब बिना परवाह किए केवल अपना साइन करके काम चला लेते हैं। बताया जा रहा है कि साहब जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। इसलिए वे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ऐसे-तैसे जैसे भी हो अधिक से अधिक लक्ष्मी बटोर लिया जाए।

चल पड़ी दुकान

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक मंत्रीजी की खूब चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि मंत्रीजी का इन दिनों पूरा ध्यान लक्ष्मी पूजा पर लगा हुआ है। आलम यह है कि मंत्रीजी राजधानी आने की बजाय व्यावसायिक राजधानी में ही डेरा डाले रहते हैं और वहीं से अपने पीए के माध्यम से अपनी दलाली की दुकान चला रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रीजी की लक्ष्मी चाह ने ठेकेदारों को परेशानी में डाल दिया है। इसकी वजह यह है कि उन्हें वजह-बेवजह व्यावसायिक राजधानी में बुलाया जाता है और मंत्रीजी की इच्छापूर्ति करने का दबाव बनाया जाता है। गौरतलब है कि मंत्री बनने के बाद माननीय को करीब एक पखवाड़े बाद यह विभाग मिला है। वह पहली बार इस विभाग के मंत्री बने हैं। कहा जा रहा है कि मंत्री पद मिलते ही माननीय जंगलराज पर उतर आए हैं। पिछले वर्षों की खानापूर्ति करने के लिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान लक्ष्मी संग्रह पर लगा दिया है। इसके लिए उन्होंने विभाग के अधिकारियों के माध्यम से प्रदेशभर के बड़े ठेकेदारों की सूची बना ली है और उन्हें बारी-बारी से व्यावसायिक राजधानी बुला रहे हैं। उन ठेकेदारों को उनकी मंशानुसार काम दिया जा रहा है और इसके बदले में मंत्रीजी की इच्छानुसार दाम लिया जा रहा है।



दो की लड़ाई में तीसरा बाजी मार गया

लोक कथाओं में अक्सर हम यह पढ़ते हैं कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है। लेकिन विसंगति यह है कि इस पर पढ़े-लिखे लोग भी अमल नहीं कर पाते हैं। दो की लड़ाई में तीसरे के बाजी मारने का मामला प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में सामने आया है। दरअसल, 1990 बैच के दो अपर मुख्य सचिवों के बीच एक विभाग को लेकर द्वंद चल रहा था। दोनों इस कोशिश में लगे हुए थे कि पानी में पैसा उगाने वाला विभाग उन्हें मिल जाए। इसके लिए दोनों ने न केवल पूरा जोर लगा रखा था, बल्कि जोरदार लॉबींग भी की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इन दोनों की लड़ाई में 1989 बैच के एक अपर मुख्य सचिव को वह विभाग मिल गया। उसके बाद से ये दोनों हाथ मल रहे हैं। दरअसल, जिस विभाग में 1990 बैच के अपर मुख्य सचिव पदस्थ हुए हैं, उस विभाग का कोरोना संक्रमणकाल में काफी महत्व है। माना जा रहा था कि सरकार इस विभाग को अपने सबसे विश्वस्त और चहेते अफसर को यह विभाग देगी। इसलिए 1990 बैच के दोनों अपर मुख्य सचिव इस विभाग में जाने के लिए बेचैन थे। लेकिन गत दिनों अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले में वह विभाग तीसरे को मिल गया। ऐसा भी नहीं है कि 1990 बैच के दोनों अधिकारियों के पास महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। दोनों के पास प्रदेश के जिम्मेदार और कमाऊ विभाग हैं। लेकिन इन विभागों में बिना कुछ किए भी तोहमत लगती रहती है।

नहीं बैठ रही पटरी

15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस 15 महीने में ही सत्ता से बाहर हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेसियों में आपस में पटरी नहीं बैठ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सत्ता जाने के बाद भी पूर्व मंत्रियों में पटरी नहीं बैठ रही है। वे एक-दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं। प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों मालवा और निमाड़ क्षेत्र से आने वाले दो पूर्व मंत्रियों का शीतयुद्ध चर्चा में है। आलम यह है कि वे एक-दूसरे की बुराई करने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। दोनों एक-दूसरे की संपत्तियों का खुलासा करने से भी नहीं चूकते हैं। एक पूर्व मंत्री अपने बड़बोलेपन के कारण हमेशा विवादों में रहते हैं। वहीं एक पूर्व मंत्री अपनी स्टाइल और शाही अंदाज के कारण चर्चा में रहती हैं। यहां बता दें कि शाही अंदाज वाली पूर्व मंत्री इन दिनों अपने सरकारी बंगले को लेकर चर्चा में हैं। इन्हें बंगले का मोह इस कदर है कि राजधानी में उनके कई बंगले होने के बावजूद वे सरकार की तीन-तीन नोटिस के बाद भी बंगला खाली करने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में संपदा विभाग को उनके खिलाफ जबरिया कार्रवाई करनी पड़ी है।

कई और बिकने को तैयार

प्रदेश में अब तक 25 कांग्रेसी विधायक भाजपा का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने इन्हें बड़ी रकम और पद का लालच देकर अपने पाले में किया है। लेकिन कांग्रेस के एक विधायक ही इस बात का खंडन कर रहे हैं कि भाजपा ने किसी को खरीदा नहीं है, बल्कि विधायक अपनी उपेक्षा के कारण ऐसा कर रहे हैं। वह दावा करते हैं कि अभी कई और विधायक बिकने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे हैं। गौरतलब है कि आगामी उपचुनाव को लेकर प्रदेश में विधायकों की खरीद-फरोखा के इल्जाम सत्ता पक्ष पर लगते रहे हैं। कांग्रेस के कई विधायक भाजपा द्वारा टिकट और बड़ी रकम की पेशकश देने की बात कई बार मीडिया में कह चुके हैं। दरअसल, ये वे विधायक हैं जो खुद पार्टी में हाशिए पर हैं। इनदिनों ग्वालियर-चंबल अंचल के एक कांग्रेस विधायक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। दरअसल, उक्त विधायक को उनकी पार्टी महत्व नहीं दे रही है। इसलिए वे अपने को खरीदने की कोशिश का प्रपंच रच रहे हैं, ताकि उनका महत्व बढ़ सके।



संजू हमेशा से ही फाइटर रहे हैं। और इसलिए हमारा परिवार भी लड़ता रहा है। भगवान ने इस चैलेंज को देकर एक बार फिर हमारी परीक्षा ली है। हमें आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। हम जानते हैं हमेशा की तरह इस बार भी हम ही विजेता होंगे।

● मान्यता दत्त



सुशांत को ठाणों-बदमाशों, लालचियों के झुंड ने घेर रखा था। उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। इतने से मन नहीं भरा तो उसके मानसिक बीमारी की कहानी चला उसके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये ना भूलें कि वे भी यहीं हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा ही नहीं होगा?

● केके सिंह



टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन शानदार रहेगा। देश के चैंपियन एथलीट डबल डिजिट में मेडल जीतेंगे। रियो ओलंपिक में हमारी टीम में 19 खिलाड़ी थे। तब हमने दोगुने पदक 2 गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीते थे। 2018 में हमारी टीम में 194 सदस्य थे और हमने 72 पदक जीते थे। अब टोक्यो में भारत डबल डिजिट में मेडल जीतेगा।

● दीपा मलिक



जो बिडेन अमेरिकी लोगों को एकजुट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए लड़ने में बिताई है। राष्ट्रपति के तौर पर वह ऐसा अमेरिका बनाएंगे जो हमारे आदर्शों के मुताबिक होगा। मुझे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है उसके लिए धन्यवाद।

● कमला हैरिश



सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में लाइक्स, शेयर और कमेंट्स निश्चित रूप से दबाव बढ़ा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि युवाओं को हमेशा इस बात की जानकारी रहे कि वास्तव में यही सब कुछ नहीं है। भले ही संख्या या मात्रा के लिहाज से हम इसे पसंद करते हों, बावजूद इसके यह वास्तविक नहीं है। इस देश के युवा तकनीक की लहर पर सवार हैं। एक ओर जहां इसके कई फायदे हैं, तो वहीं कई नुकसान भी हैं। हम वहां के विषाक्त वातावरण से दो-चार तो हो ही रहे हैं। साथ ही वहां नफरत भला माहौल भी है। वहां इस तरह की भावनाओं को भड़काने की जगह गलतियों से सीख हासिल करनी चाहिए। अपनी पहचान बनानी चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रतिदिन थोपी जाने वाली इस नकारात्मकता का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से मजबूत हों, और क्या सही है और क्या गलत, इसके बीच अंतर करने में सक्षम हों।

● मानुषी छिल्लर

वाक्युद्ध



देश में अर्थव्यवस्था का ग्राफ दिन पर दिन गिरता जा रहा है। युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं और सरकार आत्मनिर्भर भारत का गान कर रही है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के पास न तो कोई नीति है और न कोई नियत। क्या सूट-बूट-लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी।

● राहुल गांधी

राहुल गांधी यह सवाल अपनी ही पार्टी से क्यों नहीं पूछते हैं? इस देश में सबसे अधिक शासन कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी दूर करने की दिशा में कार्य किया होता तो आज यह स्थिति नहीं बनती। मोदी सरकार ने देश को आज आत्मनिर्भर बनाया है।

● रविशंकर प्रसाद



शिवराज सरकार 20-50 के फॉर्मूले पर अमल करने जा रही है। वो 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस चेक करने जा रही है। सरकार सख्ती के मूड में है। जिन कर्मचारियों का परफॉर्मेंस ठीक है, उन्हें रखा जाएगा। खराब परफॉर्म करने वाले और मेडिकली अनफिट कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने 20-50 के फॉर्मूले का आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस अब चेक किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है यानी सीआर नंबर 50 से कम है, उन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है। इसी तरह जो कर्मचारी मेडिकली अनफिट हैं और एक बार इलाज के बाद भी अगर बार-बार पड़ रहे हैं तो उनका साल के अंत में चेकअप कराया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के पास 20 साल की नौकरी के बाद खुद रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन रहेगा। अगर कर्मचारी खुद रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो 25 साल की नौकरी पूरी होते ही सरकार मेडिकल चेकअप कराकर कर्मचारियों को बाहर कर देगी। शिवराज सरकार कोरोना महामारी के दौरान बिगड़ी राज्य की वित्तीय व्यवस्था के बाद कर्मचारियों से जुड़े 20-50 के फॉर्मूले पर सख्त दिख रही है। सीआर का नंबर गणित भी विभाग ने बदला है। बदले हुए गणित के हिसाब से कर्मचारी के नौकरी ज्वॉइन करने से लेकर 20 साल तक के उसके सीआर के अंक जोड़कर ही उसके कामकाज यानी परफॉर्मेंस का आंकलन होगा। यदि 50 नंबर से कम आए तो कर्मचारी की नौकरी खतरे में होगी। सीआर में 50 या उससे ऊपर नंबर लाने वाले सभी कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे। अभी तक 3 साल की सीआर को ही परफॉर्मेंस में जोड़ा जाता था। इसे बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है।

शिवराज सरकार के 20-50 फॉर्मूले के आधार पर कर्मचारियों को रिटायर करने का विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारी संगठन उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों को रिटायर करने से पहले सरकार को स्वास्थ्य के आधार पर सांसद, मंत्रियों और विधायकों को रिटायर करना चाहिए। मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने सरकार के उस निर्णय का विरोध किया है, जिसके तहत स्वास्थ्य और काम के आधार पर कर्मचारियों को रिटायर करने का आदेश जारी किया गया है। रमेश राठौर ने कहा- 'सरकार सबसे पहले सांसदों, मंत्रियों, विधायकों का स्वास्थ्य चेक कराए। उनके काम का आंकलन करें। सांसद, विधायक और मंत्री भी सरकार का अंग हैं। यदि उनका स्वास्थ्य खराब



20-50 का फॉर्मूला

फॉर्मूले पर सख्त हुई सरकार

शिवराज सरकार कोरोना महामारी के दौरान बिगड़ी राज्य की वित्तीय व्यवस्था के बाद कर्मचारियों से जुड़े 20-50 के फॉर्मूले पर सख्त नजर आ रही है। सीआर का नंबर गणित भी विभाग ने बदला है। बदले हुए गणित के हिसाब से कर्मचारी के नौकरी ज्वॉइन करने से लेकर 20 साल तक के उसके सीआर के अंक जोड़कर ही उसके कामकाज यानी परफॉर्मेंस का आंकलन होगा। यदि 50 से कम अंक आए तो कर्मचारी की नौकरी खतरे में होगी। सीआर में 50 या उससे ऊपर नंबर लाने वाले सभी कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे। कर्मचारियों के लिए राहत की बात ये है कि अभी तक 3 साल की सीआर के आधार पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाती थी। इसे बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। यानी 20 साल की सीआर के आधार पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

है और सरकारी पैसे से इलाज करा रहे हैं तो वो भी जनप्रतिनिधि बनने के अयोग्य हैं। उन्हें भी तत्काल हटाया जाए। शासकीय कर्मचारी का तो शासकीय कार्य के बोझ से स्वास्थ्य खराब होता है। सरकार नई भर्ती नहीं कर रही है। एक-एक कर्मचारी पर चार-चार लोगों के काम का बोझ डाल रखा है। इसलिए सरकारी कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है।'

संविदा अधिकारी-कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। उसने कहा कि यदि स्वास्थ्य के आधार पर किसी कर्मचारी को हटाया जाए तो फिर उसकी जगह उसके परिवार के किसी आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी सरकार इस फॉर्मूले के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाई। विगत वर्ष नवंबर में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इस फॉर्मूले के तहत आईएएस अफसरों की परफॉर्मेंस का आंकलन कराया था। मध्यप्रदेश में पदस्थ आईएएस अफसर पास हो गए। वो मोदी सरकार के 20-50 के फॉर्मूले में फिट बैठे। कमलनाथ सरकार ने सबको पास कर दिया। सरकार का कहना है कि सभी अधिकारियों का कामकाज बेहतर है। कोई भी अफसर ऐसा नहीं जिसे जबरदस्ती रिटायर किया जाए। हालांकि इस रिपोर्ट से पहले दो-तीन अफसरों को घर भेजा जा चुका है। मध्यप्रदेश के आईएएस अफसर 20-50 के फॉर्मूले पर फिट निकले। 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र के पैमाने पर इन अफसरों के कामकाज का आंकलन किया गया। सभी इसमें पास हो गए। प्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है। इसमें कहा गया कि प्रदेश के सभी आईएएस अफसरों का सेवाकाल में प्रदर्शन बेहतर रहा।

मप्र ने केंद्र सरकार को भेजी रिव्यू रिपोर्ट में लिखा है कि सारे आईएएस अफसरों का कामकाज संतोषजनक रहा। कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसे अनिर्वाय सेवानिवृत्ति दी जाए या जिन्हें काम में कुशल ना होने के कारण हटाया जाए। प्रदेश के ऐसे अधिकारियों का भी रिव्यू किया गया जिनकी सर्विस को अभी महज 15 साल ही हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक और जनवरी से जून तक की रिव्यू रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है।

● सुनील सिंह

6

मप्र में 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं बल्कि यह सत्ता का संग्राम है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां इसके लिए तैयारी में जुटी हुई हैं। लेकिन दोनों पार्टियों को इस बात का डर सबसे अधिक सता रहा है कि उन्हें बसपा, सपा, निर्दलीय सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशी उनकी जीत का गणित बिगाड़ सकते हैं। इसलिए दोनों पार्टियां हर विधानसभा क्षेत्र में हार-जीत के गणित पर मंथन कर रही हैं।

9



मप्र में 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। प्रदेश के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा उपचुनाव होगा। इस उपचुनाव से प्रदेश सरकार का भविष्य तय होना है। उपचुनाव में बाजी मारने के लिए दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रभाव के कारण इस बार के चुनाव में वोटकटवा जीत का गणित बिगाड़ सकते हैं। दरअसल, कोरोना संक्रमण के कारण आशंका जताई जा रही है कि उपचुनाव में 40 से 45 प्रतिशत मतदान बमुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वोटकटवा उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की जीत का गणित बिगाड़ सकते हैं। 2018 में इन 27 सीटों पर वोटकटवा उम्मीदवारों को 3,54,223 वोट मिले थे, अब उपचुनाव में यही वोट जीत-हार तय करेंगे।

गौरतलब है कि मांधाता, नेपानगर, बड़ामलहरा, डबरा, बदवावर, भांडेर, बमौरी, मेहगांव, गोहद, सुरखी, ग्वालियर, मुरैना, दिमनी, ग्वालियर पूर्व, करैरा, हाटपिपल्या, सुमावली, अनूपपुर, सांची, अशोकनगर, पोहरी, अंबाह, सांवेर, मुंगावली, सुवासरा, जौरा, आगर-मालवा आदि 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर

कुल 41,54,099 वोट पड़े थे। जिसमें से 3,54,223 वोट उन उम्मीदवारों को मिले थे, जिन्हें वोटकटवा माना गया था। कई सीटों पर जीत-हार का अंतर इतना कम था कि अगर वोटकटवा उम्मीदवारों का वोट किसी एक प्रत्याशी को मिल जाता तो परिणाम बदल सकते थे। अब उपचुनाव में यही वोट भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं।

पहली बार जीते पूर्व विधायकों की राह उपचुनाव में आसान नहीं

मध्य प्रदेश में विधानसभा की 27 सीटों के उपचुनाव के लिए अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें एक दर्जन ऐसे क्षेत्र हैं जहां के विधायक पहली बार कांग्रेस से जीते। लेकिन, इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। जीतने के महज 15 माह के भीतर ही दल बदलने से उनके सामने कई चुनौतियां हैं। जैसे इन क्षेत्रों में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए राह आसान नहीं होगी। भाजपा ने कमोबेश अपनी गाइडलाइन साफ कर दी है कि इस्तीफा देकर पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस के बागी विधायकों पर ही वह दांव लगाएगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में अंबाह, अशोकनगर, करैरा, ग्वालियर पूर्व, दिमनी, पोहरी, भांडेर, मुरैना, मेहगांव, बड़ामलहरा, नेपानगर, मांधाता और हाटपिपल्या में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार जीते विधायक अब भाजपा में हैं। इन 13 क्षेत्रों में ज्यादातर सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर रही है। कांग्रेस के बागियों के आने से 2018 के भाजपा उम्मीदवार अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। उन्हें इस बात का डर है कि पार्टी बदलने के बाद मतदाता स्वीकार करेगा कि नहीं। इसके लिए वे अब पूरी तरह भाजपा पर आश्रित हैं।

27 सीटों पर मुख्य मुकाबला कैसे तो भाजपा और कांग्रेस के बीच होना है, लेकिन कुछ सीटों पर बसपा भी अपना दम दिखाएगी। लेकिन वोटकटवा उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत का गणित बिगाड़ेंगे। इसको देखते हुए राजनीतिक पार्टियां जातिगत आंकड़ों के हिसाब से वोटकटवा उम्मीदवार खड़ा करेंगी, ताकि उनके प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो सके। उन्हें धन और बल देकर विपक्षी के खिलाफ उनका उपयोग किया जाएगा। इस कारण उपचुनाव में वोटकटवा उम्मीदवारों की भरमार रहेगी।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2018 के विधानसभा चुनाव में उपचुनाव वाली 27 विधानसभा सीटों पर कुल 390 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से 324 प्रत्याशी वोटकटवा साबित हुए थे।

यानी केवल 66 प्रत्याशी ही अच्छ प्रदर्शन कर पाए। अब उपचुनाव में भी वोटकटवा प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत का गणित बिगाड़ेंगे। कांग्रेस के एक पदाधिकारी कहते हैं कि जिन कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी को धोखा देकर भाजपा का दामन थामा है, उन्हें हराने के लिए हम कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। वह कहते हैं कि कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए पार्टी का पूरा फोकस बागियों को हराने पर है।

प्रदेश में अब तक के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला होते रहता है। लेकिन बसपा, सपा, निर्दलीय और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी कांग्रेस-भाजपा की जीत के गणित को बिगाड़ते रहते हैं। अतः इस बार के उपचुनाव में दोनों पार्टियों की नजर वोटकटवा उम्मीदवारों पर रहेगी। सूत्र बताते हैं कि दोनों पार्टियों ने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। साथ ही चुनावी मैदान में उनके उतरने के प्रभाव का आंकलन किया जा रहा है।

दरअसल, 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव शिवराज सरकार के स्थायित्व और कांग्रेस की नई उम्मीदों से जुड़ा है। यही वजह है कि एक-एक सीट पर जीत मुनिश्चित करने के लिए दोनों दल बिसात बिछा रहे हैं। इसमें दाल किसकी गलेगी अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन टिकट के दावेदारों की रस्साकसी देखकर संकेत मिलने लगा है कि बगावत दोनों तरफ होगी। अगर ऐसी स्थिति में कुछ सीटों पर बागी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतर गए तो किसी एक का खेल बिगड़ सकता है। टिकट न मिलने पर दल से बगावत कर चुनाव लड़ने का चलन बहुत पुराना है। इस बार होने वाले उपचुनाव भी इस घमासान से अछूते नहीं रहेंगे। भाजपा ने तो तय कर दिया है कि जो विधानसभा सदस्यता और कांग्रेस से इस्तीफा देकर पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्हें ही टिकट मिलेगा। इसमें एक-दो फेरबदल भले हो जाएं, लेकिन ज्यादातर सीटों के उम्मीदवार तय हैं। वहीं कांग्रेस असंतुष्ट भाजपा नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रही है। ऐसे में वहां भी बहुत से दावेदारों की उम्मीद



टूटनी तय है। अब चुनाव लड़ने की आस में अपनी-अपनी जमीन तैयार कर रहे दोनों दलों के नेता टिकट न मिलने पर निर्दलीय भी आ सकते हैं। कई दावेदारों ने अपने समर्थकों को तैयारी में लगा दिया है। प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर कोरोना का इफेक्ट देखने को मिलेगा। खासकर मतदान पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। सूर्य की तपिश व शीतलहर में मतदाता अपने मत का उपयोग करने से हिचकिचाता है।

अब सवाल है कि कोरोना खौफ के बीच वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक जाने की हिम्मत कैसे जुटा पाएगा? इस सवाल ने सियासी दलों के साथ चुनाव आयोग व जिला प्रशासन को भी चिंता में डाल दिया है। संक्रमण के चलते देश की आधी आबादी महिलाएं व वृद्धजन पिछले तीन-चार माह से घरों के अंदर हैं। युवा भी संक्रमण से डरा हुआ है। एक अनुमान के तहत उपचुनाव में वोटिंग बमुश्किल 40 से 45 प्रतिशत ही हो पाएगी। ऐसे में भाजपा व कांग्रेस के सामने मतदाता को वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक ले जाना बड़ी चुनौती होगी। इसी कारण दोनों प्रमुख दलों के रणनीतिकार मतदान केंद्र के कार्यकर्ता पर फोकस कर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। दोनों दल अभी से कम वोटिंग प्रतिशत में अपने नफा-नुकसान का गणित लगा रहे हैं।

भाजपा व कांग्रेस कोरोना के संक्रमणकाल को ध्यान में रखते हुए अपने चुनाव-प्रचार की रणनीति बना रहे हैं। इसलिए दोनों दलों ने मतदान केंद्र पर फोकस कर रखा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि काफी हद तक कोरोना संकट के बादल छंटने पर चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि संक्रमण का डर तो लोगों में फिर भी रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर पार्टी ने चुनाव की रणनीति बनाई है। मतदान केंद्र पर भाजपा का 10 प्लस 1 कार्यकर्ता की तैनाती रहेगी। वहीं महिला मोर्चा 5 प्लस 2, युवा मोर्चा 5 प्लस 1 व अन्य प्रकोष्ठ भी इसी तरह से मतदान केंद्र पर काम करेंगे।

वहीं कांग्रेस भी संक्रमण को ध्यान में रखते हुए चुनाव की रणनीति बना रही है। पार्टी की जिले से लेकर पचास प्रभारी तक मजबूत कड़ी है। जिले के बाद ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर व उसके बाद पचास प्रभारी बनाए गए हैं। जो कांग्रेस के वोटर को मतदान केंद्र तक लाने का पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस के नेता केंद्र स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता से संवाद कर उसे मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एक-एक वोट से सरकार का भविष्य तय होना है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा ने जिस खरीद-फरोख्त का सहारा लेकर सरकार गिराई है। इससे लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है।

● कुमार राजेन्द्र

कोरोना के कारण इस बार महंगे पड़ेंगे उपचुनाव

प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इस बार सामान्य चुनाव से दोगुना खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि कोरोनाकाल में दोगुने से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसमें से 50 फीसदी कर्मचारी रिजर्व भी रखे जाएंगे। सामान्य चुनाव में एक मतदान केंद्र पर चार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। अब छह कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। यह अतिरिक्त व्यवस्था कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखकर की जा रही है। इससे प्रत्येक उपचुनाव का खर्च करीब एक करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस विधानसभा उपचुनाव में कई ऐसे खर्च होंगे, जो सामान्य चुनाव में नहीं होते हैं। सैनेटाइजर, मास्क, मतदान सामग्री का सैनेटाइजेशन और अतिरिक्त मानव संसाधन का इंतजाम भी रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते वाहनों की संख्या भी दो से तीन गुना बढ़ाना पड़ेगी। इसमें पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए बड़े वाहनों का उपयोग किया जाएगा। मतदान कक्ष छोटे कमरों में बनाने के बजाय बड़े कमरों में बनाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। इससे जहां एक विधानसभा चुनाव 50 से 75 लाख रुपए में होता रहा है, वहां अब एक करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है। उपचुनाव के लिए ईवीएम की प्रथम चरण की जांच पूरी हो गई है। चुनाव की घोषणा के बाद दूसरे चरण की जांच की जाएगी। इसमें 10 से 11 हजार मशीन उपयोग में लाई जाएंगी और 10 हजार मशीन रिजर्व रहेंगी।

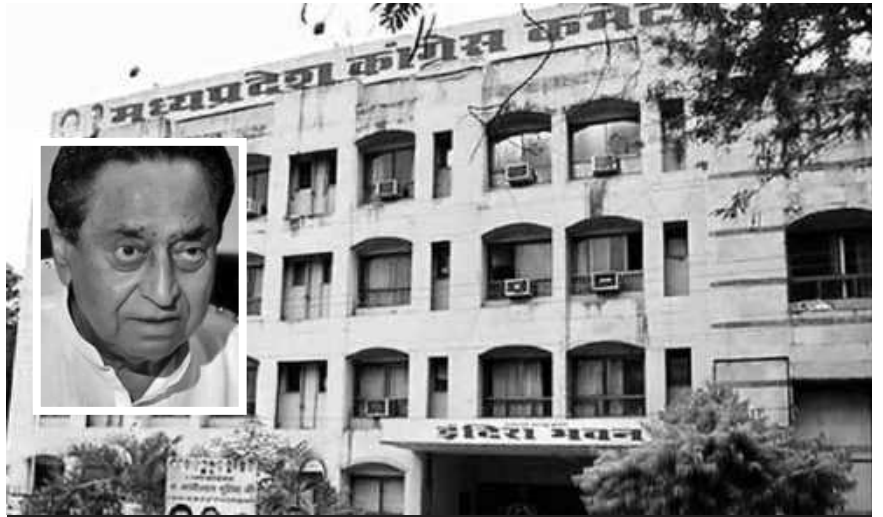
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा को उसी के फॉर्मूले से मात देने की रणनीति बनाई है। भाजपा के पन्ना प्रमुख की तर्ज पर कांग्रेस ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मतदाता इंचार्ज बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत पार्टी अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस ने इसे पन्ना प्रभारी का नाम दिया है। उपचुनाव में कांग्रेस एक बूथ पर 25 पन्ना प्रभारी बना रही है। देखना है कि कांग्रेस इस फॉर्मूले के जरिए क्या सत्ता में वापसी का रास्ता तय कर पाएगी ?

मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि उपचुनाव को देखते हुए हमने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम शुरू किया है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में संगठन स्तर पर हम कई तरह के काम कर रहे हैं, जिनमें से सबसे अहम पन्ना प्रभारी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। एक बूथ पर 25 पन्ना इंचार्ज बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से हर विधानसभा सीट पर तकरीबन साढ़े छह हजार से लेकर सात हजार पन्ना प्रभारी होंगे।

विधानसभा क्षेत्र में 250 से 300 बूथ होते हैं जबकि एक बूथ पर 800 से लेकर 1000 मतदाता होते हैं। मतदाता लिस्ट के एक पन्ने पर 50 मतदाता होते हैं। कांग्रेस ने मतदाता लिस्ट के एक पन्ने की जिम्मेदारी कहीं एक तो कहीं दो कार्यकर्ताओं को सौंपी है। कांग्रेस के पन्ना प्रभारी का काम मतदाता सूची पर ध्यान रखने के साथ ही उसके पन्ने में कहीं कोई गड़बड़ी दिखती है तो उसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने और उसे ठीक करवाने का होगा। इसके अलावा मतदाताओं से संपर्क भी स्थापित करने और उन्हें वोटिंग के दिन बूथ स्तर तक ले जाने का जिम्मा भी सौंपा गया है।

दरअसल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 25 कांग्रेस विधायकों के भाजपा में चले जाने के बाद कांग्रेस के संगठन को नए स्तर से तैयार करने की एक बड़ी चुनौती है। कई सीटों पर विधायकों के साथ-साथ पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी पार्टी का साथ छोड़ गए हैं। इसीलिए कांग्रेस का मानना है कि पार्टी संगठन में बूथ लेवल पर कुछ कमियां थीं, जिन्हें दूर करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश में जिन 27 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, उनमें तकरीबन 58 लाख मतदाता हैं। इन सभी मतदाताओं को संपर्क स्थापित करने के लिए कांग्रेस के करीब पौने दो लाख कार्यकर्ता मैदान में रहेंगे। इन सभी के कंधों पर उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत करने से लेकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की भी जिम्मेदारी होगी।

जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र में कमेटी बनाई है। सेक्टर मंडलम बने हैं। वोटिंग के लिए वे जनता को



कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट

कांग्रेस का पन्ना प्रभारी फॉर्मूला

विधानसभा के एक बूथ पर 800 से लेकर 1000 वोटर होते हैं, इनमें 50 मतदाता वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक विधानसभा में 250 से 300 बूथ होते हैं। इसलिए एक कार्यकर्ता को कम से कम 50 मतदाताओं को साधने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए कांग्रेस संगठन द्वारा बूथ प्रभारी, सेक्टर इंचार्ज, मंडलम, ब्लॉक और जिला पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक कमेटी बनाई है। 90 दशक के बाद पहली बार संगठन चुनाव लड़ने जा रहा है। अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी निजी सेनाओं के दम पर चुनाव लड़ते रहे और जीतते आ रहे थे। उम्मीदवारों के नामों की मंथन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संभावित प्रत्याशियों को यह बता दिया है कि चुनाव मैदान की कमान संगठन के लोग संभालेंगे। संभावित प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रहे कमलनाथ ने दावेदारों को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वे अपने निजी सेनाओं को चुनाव में संगठन की व्यवस्था के अनुरूप तैनात करें। कांग्रेस, खासकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के लिए उपचुनाव 20-20 क्रिकेट से कम नहीं है।

जागरूक करेंगे। साथ ही वोटिंग के दिन सक्रियता से काम करेंगे। कांग्रेस उपचुनाव वाले क्षेत्रों में इंचार्ज बनाने के लिए आनुषांगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की मदद ले रही है, जिनमें युवा कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं, किसान कांग्रेस, सेवादल से जुड़े सेवकों की भूमिका प्रमुख होगी। जीतू पटवारी का कहना है कि हम संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इसके नतीजे उपचुनावों में सामने आएंगे और निश्चित रूप से हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि आखिरकार हमारी 15 महीने की उपलब्धियां जनता के सामने हैं, जनता ने पिछली भाजपा सरकार का 15 साल और वर्तमान कार्यकाल भी देखा है।

राज्य में 27 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की दोबारा ताजपोशी के लिए पूरी ताकत और एकजुटता से चुनाव लड़ने का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में 3000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और 2700 आईटी एक्सपर्ट की फौज की तैनाती की जा रही है। यानी सोशल मीडिया पर भाजपा के दुष्प्रचार और हमला करने के लिए कांग्रेस ने हर विधानसभा क्षेत्र में 100-100 आईटी एक्सपर्ट की सेवाएं ली हैं। कांग्रेस 27 विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए और उपचुनाव में पता हासिल करने के लिए पुरानी कमियों को दूर कर रही है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने माना कि हम अंतिम 2 दिनों में चुनाव हार जाते हैं, यानी पार्टी बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाती है। यही वजह है कि 27 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है।

● अरविंद नारद

महाराज संभालेंगे मोर्चा

राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की आने वाले दिनों में ग्वालियर-चंबल संभाग में कांग्रेस के लिए किस तरह की चुनौती होगी, इसे लेकर अभी कांग्रेस नेता पूरी तरह मुखर नहीं हैं। जिन कांग्रेस नेताओं ने अब तक सिंधिया के साथ काम किया था और अब भले ही वे कांग्रेस में रहकर उनके विरोधी हैं, किंतु फिर भी वह उनके खिलाफ सीधे तौर पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त को मालवा के दौरे पर आ रहे हैं। फोकस मालवा की उन 7 सीटों पर है, जहां अब उपचुनाव होने हैं। इसमें भी सांवेर सीट अहम है, जहां से उनके खासमखास तुलसीराम सिलावट दल बदलने के बाद अब भाजपा के संभावित उम्मीदवार हैं। सिंधिया का इंदौर और उज्जैन के एक दिन के तूफानी दौरे में यहां पार्टी के सभी धुरंधर और धाकड़ नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त को इंदौर-उज्जैन के दौरे पर आ रहे हैं। मध्यप्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए सिंधिया का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपने प्रवास के दौरान वह इंदौर और उज्जैन में कई भाजपा नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात करेंगे। इंदौर में सुमित्रा महाजन यानी ताई और कैलाश विजयवर्गीय यानी भाई के घर जाने का भी प्रोग्राम है। इसके अलावा वह इंदौर में तीसरी ताकत बने सांसद शंकर लालवानी यानी साईं के घर भी जाएंगे। मालवा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इन तीनों नेताओं की अहम भूमिका होगी। यानी भाजपा को ताई-भाई और साईं को साधने के अलावा इनको एकसाथ रखना भी जरूरी है, जिससे आने वाले उपचुनाव में एक सही मैसेज जनता में जाए।

तय कार्यक्रम के मुताबिक, सिंधिया 17 अगस्त को सुबह 11 बजकर 40 मिनट पर दिल्ली से उड़ान भरकर दोपहर 1 बजकर 5 मिनट पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वह सीधे महु से भाजपा विधायक और पर्यटन और आध्यात्म मंत्री ऊषा ठाकुर के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह सड़क मार्ग से उज्जैन जाएंगे। उज्जैन में भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया से उनके घर जाकर मिलेंगे। इसके बाद सिंधिया उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के घर जाएंगे। अपने उज्जैन प्रवास के दौरान सिंधिया भाजपा विधायक पारस जैन और शिवा कोटवाणी से भी उनके घर पर मुलाकात करेंगे। दिन का आखिरी कार्यक्रम महाकाल की सवारी का रहेगा। सिंधिया शाम को रामघाट पर महाकाल की शाही सवारी का पूजन करने के बाद इंदौर लौट आएंगे।

इंदौर में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वह भाजपा महासचिव कैलाश



जनता देगी चुनौती

सिंधिया की आने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को चुनौती को लेकर जब उनसे जुड़े रहे कांग्रेस नेताओं से चर्चा की गई तो सीधे तौर पर किसी ने उनकी खिलाफत में कुछ नहीं कहा। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत सिर्फ यही बोले कि चुनौती हम नहीं जनता देगी। वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन नागोरी ने कहा कि चुनौती किस बात की, देखते जाइए परिणाम बताएंगे। उन्होंने कहा कि जिनका कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास नहीं है, उनके जाने से कांग्रेस पूरी तरह पवित्र हो रही है। हम भले ही कम हो जाएंगे, लेकिन मजबूती के साथ डटे तो हैं। असली का हमेशा मान-सम्मान होता है, ऐसे लोग चले जाए उसमें ही भलाई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री रश्मि पवार शर्मा का कहना है कि अभी तो सिंधिया ग्वालियर आए ही नहीं हैं, इसलिए उनकी चुनौती की बात क्या करें। जब यहां आएंगे, तब देखेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ हैं। जितने लोग सिंधिया के साथ गए हैं, वह मौका परस्त हैं। प्रद्युम्न, मुन्ना और इमरती ने अपनी पार्टी ही बदल डाली तो इनके बारे में क्या कहें।

विजयवर्गीय और सांवेर के प्रभारी इंदौर-2 से विधायक रमेश मेंदोला के घर जाकर उनसे मिलेंगे। सांवेर में उनकी ज्यादा जरूरत है। सिंधिया अपने दौरे के दौरान मालवा की राजनीति के सारे धुरंधरों और धुरी से मिलेंगे। उनका पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन

और वर्तमान इंदौर सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। उसके बाद रात में होटल मैरियट में भी उनकी कई लोगों से मुलाकात रखी गई है। होटल में रात रुकने के बाद वो अगले दिन 18 अगस्त को सुबह दिल्ली लौट जाएंगे।

इंदौर जिले की सांवेर सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास सिपहसालार मंत्री तुलसीराम सिलावट भाजपा के संभावित उम्मीदवार हैं। यही कारण है कि सांवेर चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं से वे सीधे संपर्क में हैं। सिंधिया खुद सभी नेताओं को फोन लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुलसी आपको सौंप दिया है, उनकी मदद करें। चुनाव संचालन से जुड़े नेताओं की सूची के क्रम से सभी को दिल्ली से फोन आ रहे हैं। सिंधिया बोल रहे हैं कि चुनाव में तुलसी भाई को अब आपको सौंप दिया है चुनाव में उनकी पूरी मदद करना है। कोई भी बात हो तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे बात करेंगे तो अच्छा लगेगा।

उल्लेखनीय है कि सिंधिया के भाजपा में चले जाने के बाद तमाम कांग्रेस नेता ऐसे हैं, जो अभी कांग्रेस में ही हैं। वे सिंधिया के साथ नहीं गए हैं। विरोधी दल में रहकर यह लोग सीधे तौर पर सिंधिया की खिलाफत करने में बच रहे हैं। जबकि पहले से ही सिंधिया विरोधी खेमे के माने जाने वाले वरिष्ठ नेता डॉ. गोविंद सिंह सहित कुछ गिने-चुने नेता ही ऐसे हैं, जो आज भी खुलकर उनके खिलाफ बयान देने में नहीं कतरा रहे। इसी तरह वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी केके मिश्रा भी उपचुनाव को लेकर पिछले डेढ़ माह से ग्वालियर में ही हैं। उन्होंने इतने दिनों में ही सिंधिया के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल लिया है। जमीन का मामला हो या फिर अशोकनगर में 50 लाख रुपए लेने के ऑडियो वायरल होने का, उसे लेकर उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन भी दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि वे उपचुनाव के दौरान सिंधिया के कई कारनामों का भंडाफोड़ करेंगे।

इधर सिंधिया पिछले लगभग चार माह से ग्वालियर नहीं आए हैं। प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत ने तो उनके लापता होने के पोस्टर भी चिपकवा दिए थे। जिस पर उनके खिलाफ प्रार्थमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनके प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम भी बने, किंतु वह बार-बार स्थगित हो गए।

● रजनीकांत पारे

हिन्दुस्तान ही नहीं वर्तमान दौर में सारी दुनिया के श्रेष्ठतम शायरों में शुमार राहत इंदौरी का यूँ अचानक चले जाना हिन्दी-उर्दू की साझा विरासत के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। खासतौर पर ऐसे समय में जब वो बुलंदियों के शिखर पर थे और उनकी तमाम शायरी न केवल हर पीढ़ी की ज़बान पर थी वरन् पूरी दुनिया और सरहदों के पार भी दूसरे मुल्कों में उनकी लोकप्रियता का वही मुकाम था जो उन्हें हिन्दुस्तान में हासिल था।

मेरी इस जादुई शायरी वाले असीम फनकार डॉ. राहत इंदौरी से पहली मुलाकात करीब 40 साल पहले राजस्थान में मेरी जन्मस्थली राजाखेड़ा गांव में एक छोटे से मेले के कवि सम्मेलन में हुई। राहत साहब उस कवि सम्मेलन के मुख्य आकर्षण थे और नवोदित कवि के रूप में मुझे भी अपनी एक-दो रचनाएं सुनाने का मौका उस मंच पर मिला था। खैर लोग तो वहां राहत साहब को ही सुनने आए थे और उन्होंने लोगों की फरमाइश पर पूरे एक घंटे तक अपनी शायरी से महफिल को नई ऊंचाइयों दी थीं। कार्यक्रम के बाद जब मैंने उनसे हाथ मिलाना चाहा, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बच्चे इसी तरह पढ़ते-लिखते रहो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। मंच पर इस छोटी-सी मुलाकात के बाद कुछ सालों बाद मेरा चयन भारतीय पुलिस सेवा में हुआ और मुझे मध्यप्रदेश कैडर मिला। फिर 15 साल बाद उनसे मेरी दूसरी मुलाकात ग्वालियर मेले के कवि सम्मेलन में हुई तो मैंने उनको बचपन की अपनी यादों का स्मरण कराया। इस बार मंच पर मेरे कविता पाठ के दौरान उन्होंने पुरजोर हौसला आफजाई की। फिर तो विगत 25 सालों में मैंने उनके साथ मग्न और मग्न से बाहर पचासों मंच साझे किए होंगे, हालांकि ज्यादातर हमारी मुलाकात भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सूरत और हैदराबाद के मंचों पर ही हुई।

मध्यप्रदेश के संस्कृति विभाग एवं भारत भवन में मेरी पदस्थापना के दौरान उनसे मेरी निकटता और बढ़ी और फिर उन्होंने अपनेपन से मुझे पवन भाई कहना शुरू कर दिया था। मंच पर मुझे उनका फक्कड़ और सूफीयाना अंदाज बहुत भाता था। चाहे मुशायरे का मंच हो या कवि सम्मेलन का, राहत इंदौरी के मंच पर आते ही पूरे माहौल और भीड़ में एक नया उल्लास छा जाता था। वो हमेशा कहते थे कि मुझे जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरा पता नहीं है कब मैं कोई अच्छा शेर पढ़ दूँ। मेरी उज्जैन में आईजी के रूप में पदस्थापना के दौरान वहां उनका आना-जाना बहुत होता था और जब किसी मंच पर मैं अतिथि या कवि के रूप में उपस्थित होता था तो वो हमेशा ये बात कहते थे कि पवन साहब आईजी होंगे आपके लिए, पर हैं तो हमारे ही कुनबे के।

‘अफसाना-ए-राहत’



यूँ तो मंच एवं मंच से परे उनके साथ बिताए गए पलों के सैंकड़ों किस्से हैं, पर कुछ संस्मरण ऐसे हैं जो यकीनन मेरे साथ ताउम्र रहेंगे। वे संस्मरण केवल उनकी जिंदादिल शायरी के नहीं, वरन् उनके बड़प्पन और इंसानियत के हैं।

राहत भाई हिन्दुस्तान में कहीं भी जाते थे और पुलिस से उनको कोई भी दिक्कत आती थी तो तुरंत मुझे फोन लगाते थे। अभी 2018 के विधानसभा चुनाव में ऐसे ही इनका अचानक फोन आया कि पवन भाई भोपाल में आपकी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है और मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मेरा परिचय पूछ रहे हैं। तो उन्होंने फोन वहां के थाना प्रभारी को थमा दिया, जब मैंने उनसे बात की तो माजरा ये समझ में आया कि राहत भाई कहीं से 2-3 आयोजन करके लौटे थे और उन्हें आयोजन से जो नगद राशि मिली थी वो चुनाव आयोग की आचार संहिता की तुलना में कहीं ज्यादा थी तो पुलिस वाले उनसे उस राशि का सोर्स पूछ रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि ये भारत के बड़े शायर हैं और आमतौर पर मुशायरों और कवि सम्मेलनों में इनको बड़े लिफाफे मिलते हैं, तो इनके पास इतनी नगदी का होना स्वाभाविक है। जहां तक बात है आचार संहिता के उल्लंघन की, तो आपको कार्यक्रम के आयोजकों से असलियत पता करनी होगी कि उन्होंने ही इनको ये राशि दी है, या फिर आप चाहें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर दें ताकि वो इनसे जानकारी प्राप्त कर लेंगे। खैर पुलिस ने उन्हें तुरंत जाने दिया। ऐसे बहुत से किस्से हैं जब भी वो किसी पुलिस चैकिंग में या एयरपोर्ट पर कहीं कोई दिक्कत आती थी, तो मुझे यदाकदा पूरे अधिकार से फोन कर लेते थे और मुझे भी हमेशा उनकी मदद करके एक संतुष्टि मिलती थी।

इंदौर के लोगों में राहत भाई के प्रति जो सम्मान, जो मोहब्बत, जो श्रद्धा थी, उसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। हिन्दुस्तान में शायद ही किसी शायर या कवि को उसके शहर में लोग इतनी मोहब्बत करते होंगे और इसका यही प्रमाण है कि जब इस साल जनवरी में उनके 70 साल पूरे होने पर जश्न-ए-राहत कार्यक्रम हुआ तो उसमें देश के सभी बड़े नामचीन शायर मुनव्वर राणा, जावेद अख्तर, वसीम बरेलवी ही

नहीं, कुमार विश्वास जैसे देश के श्रेष्ठतम कवि भी उस जलसे में पहुंचे थे और जिस सभागार में मात्र 5-7 हजार लोग ही समा सकते थे, वहां पूरे 10-12 हजार लोग प्रांगण के बाहर सड़कों तक मौजूद थे। वैसे तो राहत भाई का फलसफा जिंदादिली और पॉजिटिविटी का ही था। उनकी शायरी भी सूफियाना, कलंदर और वतन परस्ती की है। अपनी बात को बेबाकी से बेखौफ कहने का उनका अंदाज दूसरे शायर और कवियों से उन्हें अलग करता था। लेकिन कोरोना काल में वो बड़े व्यथित हो गए थे। विशेषकर जब उनकी अपनी मिट्टी के शहर इंदौर में जब पुलिस और स्वास्थ्यकर्मियों पर कुछ उपद्रवियों ने हमला किया तो उन्होंने न केवल उन उपद्रवियों को फटकार लगाई वरन् अपने ट्वीट और वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया में लोगों से डॉक्टर, पुलिस और प्रशासन के लोगों का सम्मान करने और उनकी बात मानने की सलाह भी दी। मैंने इस दौर में कई बार उनसे बात की वो हालात से थोड़े चिंतित और परेशान नजर आते थे। मैंने वहां के स्थानीय पुलिस अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के उनको नंबर भी दिए और पुलिस अधिकारियों को अवगत भी कराया कि कभी भी उन्हें कोई जरूरत हो, शहर में लॉकडाउन हो या किसी अन्य कारण से उनको तकलीफ ना हो। हालांकि, मेरे बात करने से उनको एक दिलासा तो मिलता था लेकिन वो ये हमेशा कहते थे कि मैं एक कैदी की तरह रह रहा हूँ पता नहीं कब इस कैद से बाहर निकलूंगा।

अब वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी शायरी, उनके नाम में उनकी गजलें, उनके किस्से हमारे बीच हैं और रहेंगे। उनकी शायरी यकीनन कालजयी है जो सदियों तक उनको जिंदा रखेगी। और हम जैसे लोग ये फख्र कर पाएंगे कि हमने उनको बहुत करीब से देखा था।

आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हमअसरां
जब उनको मालूम चलेंगा तुमने राहत को देखा था।

● पवन जैन
(लेखक- भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और वरिष्ठ कवि हैं।)





देश की 31 विधानसभाओं में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 50 विधायकों का चयन हुआ है, जिसमें मध्यप्रदेश के भी चार विधायकों ने जगह बनाई है। इससे पहले जनवरी में प्रदेश के दो आईएएस अफसरों को भी सर्वश्रेष्ठ अफसरों की सूची में स्थान मिल चुका है। देशभर से जिन 50 विधायकों में मध्यप्रदेश के चार विधायकों का चयन हुआ है उनमें भाजपा के तीन और कांग्रेस की एक विधायक शामिल हैं। इनमें लांजी विधानसभा की हिना लखीराम कांवरे को दक्ष बताया है। वहीं भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक कृष्णा गौर को शानदार बताया है। इनके अलावा मनासा से विधायक अनिरुद्ध माधव मारू को जिम्मेदार विधायक और इंदौर-2 विधानसभा से भाजपा के विधायक रमेश मेंदोला का विकासशील बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर सभी विधायकों को बधाई दी है। वहीं भोपाल की गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौर ने भी खुशी जाहिर की है।

सर्वे करने वाली एजेंसी फेम इंडिया-एशिया पोस्ट ने देश की 31 विधानसभाओं के विधायकों का सर्वे किया था। देशभर के कुल 4123 विधायकों की क्षमता का आंकलन किया गया। एक प्रदेश की विधानसभा भंग है। 165 विधायकों की सीटें रिक्त हैं। इस प्रकार 3958 विधायकों पर सर्वे किया गया। सर्वे में 50 श्रेणियों में विधायकों को बांटा गया था। जानकारी के अनुसार श्रेष्ठ विधायकों का चयन करने के लिए तीन तरीके से सर्वे हुआ, जिसमें स्टेक होल्ड, ऑनलाइन और डाटा एनालिसिस प्रमुख हैं। ऑनलाइन सर्वे में कुल 1500 विधायकों का नाम सामने आया। इन नामों को स्टेक होल्ड सर्वे में डाला गया तो ऊपर के कुल 150 विधायकों को आखिरी राउंड के लिए चुना गया। इन सभी नामों को डाटा एनालिसिस के जरिए एक लिस्ट में डाला गया जहां उनके कार्यों का लेखा-जोखा, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों, विधेयकों और उनकी बहस में भागीदारी आदि

15वीं विधानसभा में सदन का सत्र भले ही कम आयोजित हुए हैं, लेकिन विधायकों ने अपनी श्रेष्ठता का भरपूर प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि फेम इंडिया द्वारा चयनित देश के 50 श्रेष्ठ विधायकों में मप्र के 4 विधायक शामिल किए गए हैं।

ये हैं मप्र के श्रेष्ठ विधायक

बेहतर का सम्मान

सर्वे करने वाली एजेंसी फेम इंडिया-एशिया पोस्ट ने 50 उम्दा विधायक सर्वे 2020 किया था, जिसमें 50 विधायकों का चयन हुआ है। एजेंसी के मुताबिक समाज के लिए बेहतर करने वालों को सामने लाने और उनके प्रोत्साहन करने वाली इस संस्था का मानना है कि इससे हौंसला जागता है और दायित्वबोध बढ़ता है। उनके कार्यों से जनसाधारण को समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि विधायक अपने-अपने राज्यों में लोकतंत्र की सबसे अहम संस्था के प्रतिनिधि होते हैं। गौरतलब है कि 50 श्रेष्ठ विधायकों में गुजरात से 2, बिहार के 7, उत्तरप्रदेश के 7, महाराष्ट्र के 3, मध्यप्रदेश के 4, पंजाब के 2, छत्तीसगढ़ के 2, असम से 2, उड़ीसा से 2, हिमाचल से 3, उत्तराखंड से 1, अरुणाचल प्रदेश से 1, सिक्किम से 1, झारखंड से 3, हरियाणा से 3, केरल से 1, राजस्थान से वर्तमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया आदि का समावेश है। ताज्जुब ये है कि दिल्ली से 1 विधायक इस कसौटी पर खरा उतरा है और वो भी भाजपा के विजेन्द्र गुप्ता। जबकि आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक इस पैमाने पर खरा नहीं उतरा है।

का गहन अध्ययन किया गया। इसके पश्चात 50 श्रेष्ठ विधायकों की सूची तैयार की गई। उल्लेखनीय है कि फेम इंडिया ने देशभर के

विधायकों के बारे में सर्वे करवाया और उम्दा 50 विधायकों को प्रकाशित करने का फैसला किया है। फेम इंडिया का लक्ष्य समाज के लिए बेहतर करने वालों को सामने लाना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। विधानसभा से उपलब्ध डाटा, लोगों की राय, मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया एक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोगों की राय के आधार पर 50 उम्दा विधायकों का चयन किया गया है। फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के देशभर के उम्दा 50 विधायकों के स्टेक होल्ड सर्वे में विधायकों का चयन उनकी लोकप्रियता, कार्यशैली, प्रतिबद्धता, सामाजिक सरोकार, प्रभाव, जनता से जुड़ाव, जनहित के कार्य, छवि के साथ ही शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रस्तुत विधेयक, बहस, विधानसभा में उपस्थिति, विधायक निधि के खर्च आदि के विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के परिणामों को शामिल कर किया गया है।

इस सर्वे में विधायकों का चयन उनकी लोकप्रियता, प्रभाव, प्रतिबद्धता, कार्यशैली, जनहित के कार्य, सामाजिक सरोकार, जनता से जुड़ाव, छवि के साथ ही विधानसभा में उपस्थिति, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रस्तुत विधेयक, बहस, विधायक निधि के खर्च आदि के विश्लेषणात्मक रिपोर्ट को शामिल कर किया गया था। विधानसभा से उपलब्ध डाटा, लोगों की राय, मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया एक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोगों की राय को उपरोक्त सर्वे में शामिल किया गया।

● जितेंद्र तिवारी

20 अगस्त को स्वच्छता सर्वेक्षण लीग-2020 का परिणाम आने वाला है। इस बार भी इसमें मद्रास का दबदबा रहेगा। प्रारंभिक संकेतों के अनुसार इंदौर एक बार फिर से देश का नंबर-1 स्वच्छ शहर बनेगा। वहीं भोपाल दूसरे नंबर पर आ सकता है। इसके अलावा प्रदेश के करीब 7 शहर और हैं जो विभिन्न कैटेगिरी में अपनी स्वच्छता का लोहा मनवाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण परिणाम का लोगों को बेसब्री से इंतजार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, उसका असर यह हो रहा है कि देश के शहरों में स्वच्छता के लिए होड़ मची हुई है। हर शहर दूसरे शहर से स्वच्छ बनने के लिए प्रयासरत है। लेकिन इस अभियान में मद्रास का दबदबा शुरू से कायम है। प्रदेश की सरकार, जिला प्रशासन, नगरीय निकायों और आम जनता ने जिस तरह स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत अपने शहर को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया है, उसके परिणाम लगातार सुखद आते रहे हैं।

स्वच्छता सर्वेक्षण लीग-2020 मध्यप्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में एक बार फिर आगे है। बता दें कि देश के सबसे स्वच्छ शहरों की रैंकिंग 20 अगस्त को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से जारी की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अवॉर्ड कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। खुशी की बात ये है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार इंदौर ने प्रदेश का नाम रौशन किया है। इस अवॉर्ड के लिए राजधानी भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 9 निकायों को बुलावा आया है। गौरतलब है कि हर बार मद्रास के कई शहर और निकाय स्वच्छता में अपना लोहा मनवाते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे उस समय भी निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने शहरों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया। अब इसके परिणाम सुखद होने वाले हैं।

बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर का नाम पहले नंबर पर है, जबकि राजधानी भोपाल को दूसरे नंबर पर रखा गया है। सबसे अच्छी बात ये है कि देश के कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में से अकेला इंदौर का महू कैंट एरिया ही इस लिस्ट में शामिल हुआ है। इसके साथ ही जबलपुर, बुरहानपुर, रतलाम, सीहोर, भोपाल, शाहगंज, कांटाफोड़ को भी ऑनलाइन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण लीग-2020 के मुकाबले का फाइनल रिजल्ट 20 अगस्त को आ रहा है। इसी दिन दिल्ली में स्वच्छता महोत्सव कार्यक्रम होगा और स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को अवार्ड से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता महोत्सव के दौरान सर्वेक्षण का रिजल्ट घोषित करेंगे। रिजल्ट



अबकी बार फिर सरताज

6 हजार अंकों के लिए सर्वे



स्वच्छता सर्वेक्षण लीग-2020 में इस बार देश के कुल 4226 शहरों के बीच मुकाबला हुआ। इस बार 6000 कुल अंक निर्धारित किए गए हैं। जिसमें 1000 अंक स्टार रेटिंग, 500 अंक ओडीएफ प्लस-प्लस वाटर सेस, 1500 अंक सर्विस लेबल प्रोसेस, 1500 अंक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, 1500 अंक पब्लिक फीडबैक के अंक दिए गए हैं। इसके लिए सभी शहरों ने जोरदार तैयारी की है। इंदौर और भोपाल ने इस बार भी सूची में अव्वल रहने के लिए कई तरह के प्रयोग किए हैं। खासकर इंदौर में तो स्वच्छता के लिए कई मापदंड बनाए गए। यही नहीं वहां की जनता ने भी जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ मिलकर अपने शहर को नंबर-1 बनाने में महती भूमिका निभाई है। जिससे लगातार चौथी बार इंदौर नंबर-1 शहर बनेगा।

को लेकर नगर निगम के अधिकारियों में उत्साह है। निगम को उम्मीद है कि इस बार भोपाल पूर्व की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन करेगा।

अवॉर्ड के लिए राजधानी भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 9 निकायों को बुलावा आया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार भी इंदौर का नाम पहले नंबर पर है, जबकि राजधानी भोपाल को दूसरे नंबर पर रखा गया है। इंदौर जिले के लिए खास बात यह है कि देश के कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में से अकेला इंदौर का महू कैंट एरिया ही इस लिस्ट में शामिल हुआ है। इसके साथ ही जबलपुर, बुरहानपुर, रतलाम, सीहोर, भोपाल, शाहगंज, कांटाफोड़ को भी ऑनलाइन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है।

स्वच्छता सर्वे 2017 और 2018 में भोपाल देश में दूसरे नंबर पर था और 2019 में डाक्यूमेंटेशन में गफलत के कारण भोपाल 19वें नंबर पर आ गया था। इस बार अवार्ड के लिए वर्चुअल रूप से बुलाए जाने पर नगर निगम के अधिकारियों को बेहतर रिजल्ट की उम्मीद बंध गई है। अधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन और नगर निगम ने जिस तरीके से सुबह-सुबह उठकर सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग की, पब्लिक, बाँयोटायलेट, ओडीएफ प्लस-प्लस, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया गया उससे इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में शहर बेहतर प्रदर्शन करेगा।

● लोकेश शर्मा

प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। इसे पूरा करने के लिए तीन साल का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया की आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आयोजित की गई 4 दिवसीय वेबिनार में महत्वपूर्ण सुझाव

प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों को शामिल कर रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश के मंत्रियों के समूह गठित किए जा रहे हैं। मंत्री समूह अपना ड्राफ्ट 25 अगस्त तक प्रस्तुत कर देंगे। इस ड्राफ्ट पर नीति आयोग के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श उपरांत 31 अगस्त तक आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा एक सितंबर से इसे आगामी 3 वर्ष के लक्ष्य के साथ प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत देशी चिकित्सा पद्धति, आयुष, आदिवासी चिकित्सा पद्धति, योग आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं हमारी शिक्षा, संस्कार और रोजगार देने वाली होगी। हमें पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना है। 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया जाएगा। परंपरागत ज्ञान को अभिलेखित किया जाएगा, सर्वसुविधायुक्त स्कूलों को प्रोत्साहित करेंगे। प्रतिभा निखारने के लिए प्रखर योजना चालू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश बम्पर कृषि उत्पादन करता है, परंतु हमारा कृषि निर्यात केवल 0.8 प्रतिशत है। निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करणों को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर प्रभावी अमल किया जाएगा। उद्योगों को स्थापित करने की प्रक्रिया को इतना सरल बना दिया जाएगा कि हम किसी भी उद्यमी से कह सकेंगे कि स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। एमएसएमई को इंटीग्रेट किया जाएगा। मुख्यमंत्री दक्षता सर्वधन योजना पर कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए आउट ऑफ बजट फंड जनरेट करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई जाएगी, जो इस संबंध में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने वेबिनार में शामिल होने के लिए सभी मंत्रियों, विभिन्न विषय-विशेषज्ञों, नीति आयोग के सदस्यों आदि का धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। बफर

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप



रोडमैप तैयार करने के लिए 4 ग्रुप बनाए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के संदर्भ में कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप बनाने चार ग्रुप बनाए गए हैं। हर ग्रुप के लिए एक समन्वयक बना दिया गया है। इसमें समन्वयक मुख्य रूप से बैठक में शामिल होंगे और यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी। 16 अगस्त से इसे शुरू किया जाएगा। इसमें मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल करें और 25 अगस्त तक अपनी सिफारिशें दे दें। यह पूरी जिम्मेदारी मंत्रियों की होगी। अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। सिफारिश मिलने के बाद इसे नीति आयोग को दिया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री को। इसमें 1 महीने से लेकर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 साल की पूरी योजनाएं होंगी। किस समय हम क्या-क्या करेंगे, किस तरह से इसे जुटाया जाएगा और कैसे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इसकी पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी, ताकि 3 साल बाद जब हम जनता के पास जाएं, तो हमें बताने के लिए कुछ हो। लोकार्पण और शिलान्यास की भी सूची बनाई जाए, जहां जैसे संभव होगा वैसे जनता के हित में कार्य किए जाएंगे।

में सफर बहुत अच्छा सुझाव है। धार्मिक पर्यटन के लिए महाकालेश्वर, रामराजा मंदिर, दतिया, मैहर, सलकनपुर आदि का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा। नर्मदा पथ एवं रामवन गमन पथ को विकसित किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले की सर्वश्रेष्ठ पहचान को उजागर करने के लिए कार्य किया जाएगा। लोकल को वोकल बनाया

जाएगा। हर ग्राम-हर नगर आत्मनिर्भर हों, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। लघु-कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

किसानों को उनकी उपज का अधिकाधिक मूल्य दिलाने के लिए वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा पर काम किया जाएगा। मंडी अधिनियम में किए गए संशोधनों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। कृषि उत्पादक संघों को सुदृढ़ किया जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मध्यप्रदेश में क्षमता है कि वह पूरे देश की खाद्य तेल की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इसके लिए खाद्य तेल एवं दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।

एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में ग्लोबल पार्क की स्थापना की जाएगी तथा इनसे छोटे शिल्पियों एवं व्यवसायियों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज ऑफ लिविंग पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। आम आदमी का जीवन सुविधापूर्ण होना चाहिए। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि मध्यप्रदेश की एसजीडीपी में कृषि का 42 प्रतिशत हिस्सा है, परंतु यहां कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों की बहुत कमी है। प्रदेश में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही प्रदेश में पर्यटन उद्योग एवं ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थागत प्रसव, टीकाकरण आदि में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने का कार्य बेहतर करने की आवश्यकता है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा। ये पीपीपी मोड में खोले जा सकते हैं।

● विकास दुबे

मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके ग्वालियर और चंबल की तस्वीर को बदलने के लिए बनाए जा रहे अटल प्रोग्रेस-वे (चंबल प्रोग्रेस-वे) के भूमिपूजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। अटल प्रोग्रेस-वे के भूमिपूजन का न्यौता देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल प्रोग्रेस-वे का भूमिपूजन कर सकते हैं। अटल प्रोग्रेस-वे के लिए जरूरी सर्वे और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले अटल प्रोग्रेस-वे का भूमिपूजन कर दिया जाए। ग्वालियर-चंबल इलाके में आने वाली 16 सीटों पर भाजपा जीत के लिए अटल प्रोग्रेस-वे को अहम मान रही है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने अब अटल प्रोग्रेस-वे को लेकर जरूरी खाका तैयार करना तेज कर दिया है। अटल प्रोग्रेस-वे खतौली से श्योपुर और मुरैना होते हुए भिंड तक कुल 309 किलोमीटर लंबा होगा। इसके लिए 2000 एकड़ जमीन विकसित की जाएगी। इस पर कुल 6193 करोड़ रुपए की लागत आनी है। सरकार ने अटल प्रोग्रेस-वे को इस तरीके से डिजाइन करने का प्लान बनाया है, ताकि इसके आसपास के इलाकों को डेवलप किया जा सके और स्थानीय लोगों को फायदा हो सके।

अटल प्रोग्रेस-वे के आसपास भारी उद्योगों के साथ वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर विकसित होंगे। सरकार ने इसके लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए ढाई सौ करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कर दिया है। वहीं, सरकार ने नर्मदा एक्सप्रेस-वे की फाइल को भी अब गति देना शुरू कर दिया है। अमरकंटक से शुरू होकर अंकलेश्वर गुजरात तक बनने वाले नर्मदा एक्सप्रेस-वे में हरदा खंडवा के 112 किलोमीटर में धार्मिक स्थलों और प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि अटल प्रोग्रेस-वे के निर्माण को लेकर सरकार ने सभी तैयारियों को तेज कर दिया है। नर्मदा एक्सप्रेस-वे को लेकर महाकौशल के सभी सांसद और विधायकों के साथ बैठक कर डिजाइन को फाइनल किया जाएगा।

मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि भूमिपूजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अटल प्रोग्रेस-वे का भूमिपूजन प्रधानमंत्री मोदी से कराया जाएगा। इसकी तारीख जल्द तय कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी को अटल प्रोग्रेस-वे के भूमिपूजन का न्यौता देंगे। दरअसल, अटल प्रोग्रेस-वे को केंद्र सरकार की भारतमाला



अब अटल प्रोग्रेस-वे

सड़क किनारे खिलेगी रोजगार की हरियाली

प्रोग्रेस-वे के दोनों ओर जहां-जहां सरकारी जमीनें हैं वहां-वहां इंडस्ट्री एरिया बनाए जाएंगे। सरकार की मंशा पूरी हुई तो प्रोग्रेस-वे के किनारे मग्न का सबसे बड़ा इंडस्ट्री कॉरिडोर बनेगा। चंबल नदी के किनारे त्रिवेणी संगम, गऊघाट, काऊपुरा घाट आदि कई स्थल हैं जो पर्यटन केंद्र बनेंगे। इतना ही नहीं कृषि उत्पादन केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, अस्पताल, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट से लेकर आधुनिक मनोरंजन पार्क भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा निजी रोजगार व खेती के लिए सरकार किसानों को बीहड़ों में जमीन के पट्टे व लीज तक देगी। इस फोरलेन सड़क के बनने से कई शहरों की दूरी कम हो जाएगी। वर्तमान में श्योपुर से भिंड की दूरी लगभग 275 किलोमीटर है। अटल प्रोग्रेस-वे बनते ही भिंड की दूरी 185 किलोमीटर ही रह जाएगी। यानी श्योपुर और भिंड 90 किोमीटर पास आ जाएंगे। इसी तरह श्योपुर से कोटा, मुरैना से लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर व अन्य शहरों की दूरी भी काफी कम हो जाएगी।

योजना में शामिल किया गया है। इसके जरिए अटल प्रोग्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए राशि देगी और यही कारण है कि अब अटल प्रोग्रेस-वे के जरिए चंबल इलाके की तस्वीर बदलने की तैयारी प्रदेश सरकार ने कर ली है। अटल प्रोग्रेस-वे में तब्दील हुआ फोरलेन मेगा हाईवे का सिर्फ नाम ही नहीं बदला बल्कि इसका स्वरूप भी बदल रहा है। जब इसका नाम चंबल एक्सप्रेस-वे था तब इसकी कुल लंबाई 276 किमी थी जो, चंबल प्रोग्रेस-वे नामकरण होने के साथ 394 किमी की

हो गई है। यानी 118 किमी लंबाई बढ़ाई गई है। खास बात यह है कि पहले यह एक्सप्रेस-वे केवल मग्न में ही बन रहा था लेकिन, अब 85 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान सरकार भी बनाएगी।

अटल प्रोग्रेस-वे का नया और फाइनल माना जा रहा डिजाइन 394 किलोमीटर का है। 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक्सप्रेस-वे का पूरा सर्वे एवं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) ने तैयार की है, लेकिन इसका निर्माण भारत माला परियोजना के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) करेगा। यह एक्सप्रेस-वे राजस्थान के दीगोद कोटा-बारा नेशनल हाईवे से श्योपुर, मुरैना, भिंड होते हुए भिंड-इटावा नेशनल हाईवे-92 से जुड़ेगा। मग्न में इसकी लंबाई 309 किमी की होगी और राजस्थान में 85 किमी का हिस्सा। दोनों को मिलाकर अटल प्रोग्रेस वे 394 किमी का होगा। इस एक्सप्रेस-वे का जो डिजाइन है वह 100 फीट चौड़ा है और इसे इस मापदंड से बनाया जाएगा जिससे इस पर वाहनों की रफ्तार 100 किमी प्रतिघंटे तक की रहेगी। यह एक्सप्रेस-वे सड़क मार्गों को जोड़ने वाला एक अनोखा प्रोजेक्ट है जिससे चंबल अंचल के 150 से ज्यादा गांवों में तरक्की का रास्ता भी खुलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सड़क नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर को ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से जोड़ेगी। मुरैना जिले के गहोरा गांव के पास से गुजरे नेशनल हाईवे नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर का पाईंट है और राजस्थान के दीगोद में कोटा-बारा नेशनल हाईवे के कारण ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर है। यानी यह एक सड़क दोनों कॉरिडोरों को जोड़कर देश की चारों दिशाओं के रास्तों की सुगम कनेक्टिविटी करेगी।

● प्रवीण कुमार

तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद मनरेगा की सार्थकता उसके शुरू होने के 14 साल बाद भी बरकरार है। मप्र में भारी वित्तीय संकट के बीच कोरोना वायरस के वैश्विक संकट के समय रोजी-रोटी के उत्पन्न संकट से निजात दिलाने के लिए मनरेगा संजीवनी बना है। खासकर इस अवधि में मनरेगा उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है, जो रोज मेहनत कर कमाते और खाते हैं। मप्र में पिछले 4 माह के दौरान 58 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला है। यानी मनरेगा आपदा में अवसर बन गया है।

संबल बना मनरेगा



आपदा में मनरेगा ने बनाया सक्षम

लॉकडाउन और कोरोनावायरस के व्यापक असर के बाद भारत के श्रमिक वर्ग का जो थोड़ा बहुत स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता थी, वह भी खत्म हो गई है। करोड़ों की संख्या में अपने घरों से दूर काम करने वाले मजदूरों ने अनुभव किया है कि उनके प्रवासी होने के नाते, उनके काम, रहने, खाने और आवास की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए तीन हफ्ते के पहले वाले लॉकडाउन की घोषणा को सुनते ही, बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक और उनके परिवार रोजगार की जगह से अपने गांव की ओर चल पड़े। सवाल है कि ये अपना घर और गुजारा कैसे चलाएंगे? जिन्होंने रोजगार की तलाश में गांव छोड़ा था, उन्हें अब उसी गांव में इस बेरोजगारी के दौर में क्या रोजगार मिलेगा? हकीकत में आज ग्रामीण भारत में कोई रोजगार मिलने की संभावना है, तो वह मनरेगा के तहत ही है। इस कानूनी हक को वर्तमान प्रधानमंत्री सहित, कई अर्थशास्त्रियों ने एक विफलता का प्रतीक बताया था, लेकिन आज मनरेगा योजना एक जीवन रेखा बन गई है। मनरेगा में इस वर्ष 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आने से यह कार्यक्रम रफतार से चलने लगा है। घरों में चूल्हे जलने लगे हैं।

किए जाएं। ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल से जुलाई तक प्रदेश में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को 2213 करोड़ रुपए की राशि मजदूरी के रूप में बांटी गई है, वहीं 665 करोड़ रुपए सामग्री पर खर्च किए गए हैं। जबकि पिछले पूरे साल में 1,366.58 करोड़ रुपए मजदूरी दी गई थी। प्रदेश में करीब 23,000 के आसपास पंचायतें हैं और लगभग सभी पंचायतों में काम चल रहे थे। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण 1253 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य फिलहाल रोक दिए गए हैं। इन गांवों के संक्रमणमुक्त होते ही यहां फिर से काम शुरू कर दिए जाएंगे।

गांवों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कोविड-19 को लेकर जनजागरण अभियान भी चला रहा है। मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए होम-मेड मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं गांव में दीवार लेखन और पोस्टर-बैनर के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं।

देश में 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां थमने के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों ने पलायन किया। ये श्रमिक शहरों से गांवों में पहुंचे। बेरोजगार होकर गांव पहुंचे श्रमिकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में मप्र सरकार ने मनरेगा को माध्यम बनाया और लोगों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना शुरू किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गांवों में पहुंचे श्रमिकों का सर्वे कराकर उनको मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 4 माह में प्रदेश में 57,83,522 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। अब तक 12 करोड़ 30 लाख मानव दिवस कार्य हुए हैं। जबकि पिछले वर्ष पूरे सालभर में 19 करोड़ 50 लाख मानव दिवस कार्य हुए थे। पिछले वर्ष करीब 11 लाख श्रमिकों को ही मनरेगा के तहत प्रतिदिन कार्य मिला था। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कहते हैं कि कोरोना संकट में मनरेगा ग्रामीणों और बाहर से आए श्रमिकों के लिए संबल बना हुआ है। केंद्र सरकार ने मप्र सहित देशभर में जिस तरह से मनरेगा को इस आपदा में अवसर बनाया है, उससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। वह कहते हैं कि हमने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मनरेगा के अंतर्गत अधिक से अधिक स्थाई संपत्तियों का निर्माण किया जाए। मनरेगा अंतर्गत कार्य-स्थलों में श्रमिकों को दी जाने वाली अन्य सुविधाएं जैसे झूलाघर, मेडिकल किट आदि व्यवस्थाओं का सतत निरीक्षण किया जाए। जॉब-कार्ड श्रमिक के पास ही हो यह सुनिश्चित किया जाए। श्रम सिद्धि अभियान अंतर्गत किए जाने वाले सर्वे में सोशल ऑडिट के विलेज सोशल एनीमेटर एवं स्व-सहायता समूह के सदस्यों को संलग्न किया जाए तथा एक पंचायत का सर्वे कार्य दूसरे पंचायत की टीम से कराया जाए। मनरेगा अंतर्गत पंचायत भवनों एवं शाला भवनों में आवश्यकतानुसार एवं प्रावधान अनुसार बाउण्ड्री-वॉल निर्माण तथा पौधरोपण के कार्य

मनरेगा में फिलहाल 13.87 करोड़ जॉबकार्ड हैं। भारत के 55 प्रतिशत परिवार जॉबकार्ड धारी हैं। मध्यप्रदेश में 71.33 लाख परिवारों के पास जॉबकार्ड हैं। इनमें से 7.81 करोड़ (56 प्रतिशत) जॉबकार्ड धारी पिछले तीन सालों में योजना में श्रम करते रहे हैं। अब कोरोना में किए गए लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लेकिन अधिकांश को कागजों पर ही रोजगार मिल रहा है। दरअसल मनरेगा के कुछ प्रावधानों में और बहुत सारी इनके क्रियान्वयन में विसंगतियां हैं। पिछले 20 वर्षों की स्थिति यह रही है कि इन परिवारों को 300 दिन में से अन्य स्रोतों से 75 से 100 दिन का ही रोजगार हासिल हो पाता है, ऐसी अवस्था में उन्हें 200 दिन के रोजगार की जरूरत रही है, लेकिन मनरेगा भी केवल 100 दिन का रोजगार देने के प्रावधान के कारण पूरा विश्वास स्थापित नहीं कर पाया। दूसरी बड़ी विसंगति मनरेगा की मजदूरी भारत की न्यूनतम मजदूरी की दर से वर्ष 2019-20 तक लगभग 18 से 20 प्रतिशत कम रही है। तीसरी बात मजदूरों को 6 से 12 महीनों की देरी से मजदूरी का भुगतान होना है। भ्रष्टाचार, सोशल ऑडिट न होना, मशीनों से काम कराया जाना भी कारक रहे हैं।

● नवीन रघुवंशी

को रोग ने मध्य प्रदेश में पुलिस को बदल दिया है। पुलिस बदली तो बहुत कुछ बदल गया। जनता अब उसे नए रूप में देख रही है। एफआईआर अब घर बैठे दर्ज कराई जा रही है और गाड़ियों की चैकिंग सोशल डिस्टेंसिंग से की जा रही है। आरोपी को लॉकअप में डालने से पहले उसका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना के कारण मध्यप्रदेश पुलिस की वर्किंग स्टाइल में बदलाव हुआ है। फील्ड का मामला हो या फिर ऑफिस का, सभी जगह कामकाज में बदलाव हुआ है। इस बदलाव से जनता को भी फायदा मिला है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस पहले काम करती थी उसने अपने कामकाज के अंदाज को बदला है। थाना स्तर पर और पुलिस के अधिकारी स्तर पर कई बदलाव हुए हैं। इसी बदलाव से पुलिस का प्रारूप भी बदला है। हालांकि कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ, पुलिस पहले की तरह ही कार्रवाई कर रही है। लेकिन वर्किंग स्टाइल बदलने से बहुत कुछ बदल गया है।

मध्यप्रदेश पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और पुलिस मुख्यालय की गाइडलाइन का पालन तो कर रही है, लेकिन इसके साथ कुछ बदलाव ऐसे भी किए गए हैं जिससे उसकी वर्किंग स्टाइल बदल गई है। यानी कोरोना ने पुलिस को बदल दिया है। एडिशनल एसपी संजय साहू ने बताया कि कोरोना का असर पुलिस विभाग पर बहुत गहरा पड़ा है। पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम गाइडलाइन का पालन कर रही है। कोरोना से कई पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में पुलिस ने कई जगह अपने काम करने के तरीके को बदला है।

थाना स्तर पर पुलिस ने शिकायत और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसके साथ ही सुपरविजन करने वाले अधिकारियों और उनके ऑफिस में भी कई बदलाव हुए हैं। इस बदलाव का फायदा जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि यह बदलाव जनता की सुविधा के लिए किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जनता को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। उनकी शिकायतों को सुना जाए, उस पर कार्रवाई हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। थाना स्तर से लेकर चैकिंग में भी बदलाव किया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पुलिस ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। बेवजह थानों में किसी को नहीं बैठाया जाता है। हवालात की व्यवस्था को भी बदला गया है। इन सभी बदलाव से आम जनता को भी फायदा होगा।

पुलिस ने इस कोरोना संक्रमण के दौर में 6 बदलाव किए हैं। पहला बदलाव यह कि फील्ड पर लगाए गए चैकिंग पॉइंट पर पुलिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर रही है। चैकिंग व्यवस्था भी बदली गई है। चैकिंग पॉइंट



कोरोना में बदल गई मप्र पुलिस

सर्विस रिकॉर्ड अपडेट करने में फिसड्डी

मध्यप्रदेश में पुलिस का सर्विस रिकॉर्ड मेंटन नहीं है। ये गड़बड़ी प्रशासन शाखा की ओर से नहीं की गई है बल्कि पुलिस स्टाफ लापरवाह बना हुआ है। वो सर्विस रिकॉर्ड में अपनी और अपने परिवार की जरूरी जानकारी अपडेट नहीं कर रहा है। प्रशासन शाखा की पड़ताल में जब पता चला कि कई पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड अधूरा है, तब सभी पुलिस इकाइयों को मेल भेजकर दस्तावेज मांगे गए हैं। पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा के एडीजी अन्वेष मंगलम ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को सर्विस रिकॉर्ड के संबंध में पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि अनहोनी घटना में पुलिस स्टाफ के कुछ लोगों की मौत के बाद यह जानकारी में आया है कि सर्विस रिकॉर्ड का पहला पेज लेमिनेशन, शादीशुदा कर्मचारी का सपत्नी फोटो, नॉमिनेशन फॉर्म, जन्मतिथि, वर्तमान पता, स्थाई गृह जिला आदि महत्वपूर्ण जानकारी नहीं भरी गई है।

पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। उसी हिसाब से बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। पुलिस ने ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था भी की है। चैकिंग पॉइंट पर अब ज्यादा समय भी नहीं लगता। दूसरा बदलाव थानों में विंडो सिस्टम से शिकायत सुनी जा रही है। थाने में बाहरी व्यक्ति के आने-जाने पर रोक है। थाने के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन आम जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए ड्यूटी ऑफिसर विंडो सिस्टम की सहायता से लोगों की शिकायतों को सुनता है और उन पर एफआईआर भी करता है।

तीसरा बदलाव पुलिस सारा पत्राचार अब ऑनलाइन कर रही है। इसके जरिए पुलिस के मेल आईडी पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। उसके पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा वीडियो कॉलिंग के जरिए भी अपनी समस्या पुलिस को बताई जा सकती है। कुल मिलाकर पुलिस अधिकांश काम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कर रही है। चौथा बदलाव हवालात में आरोपियों की व्यवस्था बदली है। पहले थानों के लॉकअप में कई लोगों को एक साथ बैठाया जाता था। लेकिन अब आरोपी से सख्ती से पूछताछ और पूरा संदेह होने पर ही थाने में बैठाया जाता है। इससे थाने में बेवजह की भीड़ इकट्ठी नहीं होती। साथ ही आरोपी का कोरोना टेस्ट कराया जाता है।

पांचवे बदलाव में घर में एफआईआर की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस के बड़े थानों में कुछ मामलों के तहत घर बैठे एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान भी है। पुलिस घर पर आती है और तमाम जानकारी जुटाने के बाद एफआईआर दर्ज करती है। छठवां बदलाव कोरोना काल ने डायल 100 सिस्टम को बदला है। अब यह सिस्टम मेडिकल इमरजेंसी को प्राथमिकता देता है। कोरोना में क्राइम रेट कम होने की वजह से अब आम जनता से जुड़ी मेडिकल इमरजेंसी में 100 डायल की गाड़ियां सूचना मिलने पर तत्काल मदद करती हैं। इन बदलावों के साथ मप्र पुलिस कोरोना के इस संक्रमणकाल में लोगों को सुरक्षा के साथ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। पुलिस के बदले इस रूप को देखकर लोग भी हर्षित हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस का यह रूप हमेशा बरकरार रहना चाहिए।

● राजेश बोरकर

बा समती चावल के जीआई टैग को लेकर पंजाब और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच खींचतान जारी है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। शिवराज सिंह ने सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राहुल गांधी, कमलनाथ समेत कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और पूछा है कि मध्यप्रदेश के किसान से कांग्रेस को क्या परेशानी है।

दुनियाभर में अपनी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर बासमती चावल इन दिनों अपनी भौगोलिक पहचान को लेकर कानूनी विवाद में उलझा हुआ है। लगभग 12 साल से चल रही यह लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। यह मामला मध्यप्रदेश बनाम सात अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है। जुलाई के पहले सप्ताह में इसी मसले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। उन्होंने बासमती चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिलाने में मदद करने की गुहार लगाई। शिवराज सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में परंपरागत तरीके से बासमती धान की खेती होती है। इसी आधार पर चौहान ने अपने पिछले कार्यकाल में **भौगोलिक संकेतक** के लिए चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री में प्रदेश का आवेदन कराया था। बरसों पुराने प्रमाणित दस्तावेज भी जुटाकर दिए थे। लेकिन, एपीडा (एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी) के विरोध के कारण मान्यता नहीं मिल सकी। एपीडा ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें प्रदेश के पक्ष को खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार ने मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मप्र सरकार के मुताबिक, उनके यहां पैदा की जाने वाली बासमती चावल की गुणवत्ता हरियाणा, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादित चावल से बेहतर है। प्रदेश 59,238 मीट्रिक टन तक बासमती चावल एक्सपोर्ट करता रहा है, लेकिन कभी गुणवत्ता की शिकायत नहीं रही। जीआई टैग को लेकर ऐसे भी अवसर आए जब मप्र के पक्ष में फैसला आया लेकिन एपीडा की अपील और विरोध से मामला अटकता रहा।

मप्र के 13 जिलों में बासमती धान की खेती होती है, लेकिन जीआई टैग नहीं होने की वजह से इसे बासमती के तौर पर मान्यता नहीं है। प्रदेश के लगभग 4 लाख किसान इससे जुड़े हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान का तर्क है कि किसानों के हित और चावल की गुणवत्ता को देखते हुए मध्यप्रदेश की बासमती को जीआई टैग दे दिया

बासमती पर विवाद



मध्यप्रदेश को टैग न देने के पीछे क्या है तर्क ?

एपीडा का कहना है कि यदि मध्यप्रदेश को बासमती उत्पादक राज्य माना गया तो यह फैसला उत्तरी राज्यों में बासमती पैदा करने वाले अन्य किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि मप्र भी बासमती उत्पादक राज्यों में शामिल हुआ तो न सिर्फ आपूर्ति बढ़ जाएगी बल्कि बासमती चावल की कीमतें भी गिर जाएंगी और गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड चेन्नई ने मध्यप्रदेश के दावे को पेंडिंग रखते हुए फरवरी 2016 में आदेश दिया था कि वर्तमान में जिन सात राज्यों को बासमती चावल उत्पादक माना गया है, उन्हें मिलने वाली सुविधाएं दी जाएं। जबकि, दिसंबर 2013 में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार (चेन्नई) ने मप्र के पक्ष में निर्णय दिया था। तब मप्र सरकार ने 1908 व 1913 के ब्रिटिश गजेटियर पेश किए थे, जिसमें बताया था कि गंगा और यमुना के इलाकों के अलावा मध्यप्रदेश के भी कुछ जगहों में भी बासमती पैदा होता रहा है। एपीडा ने इसके खिलाफ आईपीएबी में अपील कर दी थी। तब एपीडा ने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उप्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलावा कहीं भी बासमती चावल का उत्पादन नहीं होता।

जाए। मध्यप्रदेश के जिन 13 जिलों में इसकी खेती होती है उनमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, श्योपुर, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर शामिल हैं। टैग न मिलने की वजह से यहां के बासमती धान को वह कीमत नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। फिलहाल, चौहान के आग्रह पर कृषि मंत्री तोमर ने जीआई टैग के लिए मध्यप्रदेश को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। एपीडा ही नहीं बल्कि जीआई रजिस्ट्री भी मध्यप्रदेश के दावे को खारिज करती रही है। रजिस्ट्री ने अपने आदेश में कहा था कि मध्यप्रदेश जीआई टैग के लिए आवश्यक पारंपरिक बासमती-उत्पादक क्षेत्र संबंधी 'लोकप्रिय धारणा की मौलिक आवश्यकता' को पूरा नहीं करता। बासमती के लिए जीआई टैग गंगा के मैदानी क्षेत्र वाले खास हिस्से के लिए दिया गया है और मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में नहीं आता। इसलिए उसे

जीआई टैग नहीं दिया जा सकता।

दुनियाभर में बासमती की बहुत मांग है। ऐसे में जिस इलाके के बासमती को जीआई टैग मिला हुआ है वहां के चावल को असली माना जाता है। इससे उत्पाद का बाजार सुरक्षित हो जाता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के 77 जिलों को बासमती चावल की अलग-अलग किस्मों का जीआई टैग मिला हुआ है। भारत ने 2018-19 में 44,14,562 मीट्रिक टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था, जिससे 32,804.19 करोड़ रुपए मिले थे। असली लड़ाई इसी एक्सपोर्ट की है। जिससे राज्य को पैसा मिलता है। भारत से ईरान, सऊदी अरब, इराक, यूएई, यमन, कुवैत, यूएसए, यूके, ओमान और कतर आदि में भारत से यह चावल एक्सपोर्ट होता है।

● श्याम सिंह सिकरवार

दा वा किया जा रहा है कि बाघों के संरक्षण के लिए देश में काम हुआ है, उसका असर देखने को मिला और देश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ी है। लेकिन सवाल उठता है कि संरक्षण के दावों के बाद भी जंगल में बाघों की मौत कैसे हो रही हैं।

मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में 7 अगस्त को बाघिन को लेकर दो नर बाघों के बीच हुए भीषण संघर्ष में 8 वर्ष के युवा बाघ की मौत हो गई। वन विभाग इससे संतुष्ट है कि बाघ का शिकार नहीं हुआ। लेकिन वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी यक भूल जाते हैं कि इस देश या मप्र में बाघों की सर्वाधिक मौत शिकार से होती है।

अगर मप्र की बात करें तो बाघों के मामले में दो बातों ने इस साल रिकार्ड तोड़ा। पहला तो यह कि मप्र में जनवरी से मार्च तक एक भी बाघ की मौत की खबर नहीं थी, लेकिन अप्रैल के एक महीने में ही बाघों की सबसे ज्यादा मौतें होने का रिकार्ड भी मप्र ने ही तोड़ा। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 8 और 2 मई को एक और बाघ शावक यानी कुल 9 बाघों की मौत की खबर ने सबको हैरान करके रख दिया। इतनी बड़ी संख्या में मौतें देश के किसी भी अन्य राज्य में नहीं हुईं। 1 अप्रैल को कान्हा में, 3 को पेंच, 9 को बांधवगढ़, 11 को बुरहानपुर, 13 को कान्हा, 17 को चित्रकूट और 22 अप्रैल को बांधवगढ़, मुकुंदपुर जू सतना में यह मौतें हुईं। 2 मई को बांधवगढ़ से एक बाघ मारे जाने की खबर आई। हैरान करने वाली एक और बात यह है कि सभी बाघों के शव सड़ी-गली हालत में मिले और सभी की उम्र 10 साल से कम थी। इसके अलावा जून, जुलाई में भी बाघों के मौत की घटनाएं हुई हैं।

एनटीसीए के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 8 साल में मध्यप्रदेश में सर्वाधिक 173 बाघों की मौत हुई। इसमें से 38 बाघों की मौत शिकार की वजह से, 94 की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। 19 बाघों की मौत का मामला अभी जांच के दायरे में है। 6 बाघ अप्राकृतिक कारणों से मारे गए और 16 के दांत, खाल, नाखून, हड्डियां आदि अवशेष मिले। जानकारी के मुताबिक 8 साल में मौतों के मामले में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा, जहां 125 बाघों की मौत हुई। इसके बाद कर्नाटक में 111, उत्तराखंड में 88, तमिलनाडु में 54, असम में 54 केरल और उप्र में 35-35, राजस्थान में 17, बिहार और प.बंगाल में 11 तथा छत्तीसगढ़ में 10 बाघों की मौतें हुई हैं। एनटीसीए के मुताबिक 8 साल की अवधि में ओडिशा और

कैसे रुकेगी बाघ की मौत



मौतों का बड़ा कारण सरकारी उदासीनता

मध्यप्रदेश में बाघों के संरक्षण के मकसद से 8 साल पहले स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की योजना बनी थी, जिसके तहत हथियार बंद सुरक्षा दस्तों को ट्रेनिंग देकर जंगल में उतारा जाना था, लेकिन इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद कुछ हुआ नहीं। पिछली कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में योजना की फाइलें कुछ आगे बढ़ी थीं, लेकिन इस साल मार्च के तीसरे हफ्ते में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के कांग्रेस मंत्री-विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर भाजपा से गठजोड़ कर सरकार गिरा दी। शिवराज सिंह के नेतृत्व में नई सरकार बनी, तो कोरोना की महामारी ने जकड़ लिया। मौजूदा दौर में बाघों की आबादी के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके प्राकृतिक निवास स्थान का नुकसान है। एक अनुमान के मुताबिक विश्वभर के बाघों ने अपने रहने के 93 फीसदी प्राकृतिक स्थान खो दिए हैं। मध्यप्रदेश में तो भोपाल के ही उदाहरण से उनके इलाके खोने का अनुमान लगाया जा सकता है। राज्य के वनविभाग के पास भोपाल का 1960 का एक नक्शा मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि बाघों का कहां-कहां डेरा था। नक्शे के मुताबिक नए भोपाल का लगभग पूरा इलाका बाघों का था। पुराने भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में पुलिस मुख्यालय के पास तक बाघों का आना-जाना और दिखना हुआ करता था। केरवा और कलियासोत क्षेत्र बाघों से भरा हुआ था।

आंध्र प्रदेश में 7-7, तेलंगाना में 5, दिल्ली, नागालैंड, हरियाणा और गुजरात में एक-एक बाघ की मौत हुई है। मीडिया में बाघों की मौतों की खबरें सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने 6 जून 2020 को अपने एक स्पष्टीकरण में यह तो माना कि वर्ष 2012 से 2019 के बीच 8 साल में 750 बाघों की मौत का आंकड़ा तो सही है, लेकिन इसमें 60 फीसदी मौतों के मामले में शिकार कारण नहीं रहा है। इस अवधि में जो भी बाघ मरे, उनमें 369 बाघों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी, 42 दुर्घटना या शिकार हुए, 101 बाघों के अंग तस्करी के प्रयास के दौरान पकड़े गए। शेष 70 मामलों की जांच की जा रही है।

कारण चाहे जो भी बताए जाएं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मप्र के भोपाल, होशंगाबाद, पन्ना, सिवनी, मंडला, बैतूल और छिंदवाड़ा के जंगल शिकारियों के पनाहागह बन गए हैं। वन विभाग के अधिकारी और दीगर जानकार बताते हैं कि बाघों की मौतों के पीछे दो प्रमुख वजह हैं, एक

तो इनका आबादी में जाना। दूसरा, अपनी बादशाहत के लिए क्षेत्राधिकार की लड़ाई। इसके अलावा शिकार भी मौतों की एक बड़ी वजह है, लेकिन वन अधिकारी इस तथ्य को ज्यादा नहीं मानते। वास्तविकता यह है कि देश के दूसरे राज्यों में टाइगर कॉरिडोर बड़े जंगलों में फैले हुए हैं, लेकिन मध्यप्रदेश में ऐसा नहीं है, इसलिए शिकारी घात लगा लेते हैं। बताते हैं कि सीधी जिले में संजय गांधी, मंडला जिले में कान्हा किसली, सिवनी जिले में पेंच, पन्ना में पन्ना नेशनल पार्क और उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यह सभी छोटे-छोटे टुकड़ों और वनक्षेत्रों में बंटे हैं, उनको कॉरिडोर से जोड़ते हुए नए अभ्यारण्य बनाने की योजना है, ताकि बाघों के बीच अपने-अपने इलाकों को लेकर संघर्ष न हो। एक बाघ के लिए कम से कम 60 से 80 किलोमीटर के दायरे वाला क्षेत्र चाहिए, वो नहीं चाहता कि उसके रहते कोई दूसरा यहाँ आए, इसलिए संघर्ष में बाघों के मरने की खबरें आती हैं।

● राकेश ग्रोवर

बुंदेलखंड में सूखे के डर के बीच 6 से 22 जुलाई तक दो सप्ताह बारिश थमी रहने के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। पर्याप्त पानी न मिलने से कई इलाकों में फसल का जमाव नहीं हो पाया है। जहां कुछ हद तक पानी गिरा है, वहां जमाव तो हो गया लेकिन फसल की बढ़त पर असर दिखाई दिया है। अब सारी निगाहें अगस्त के बचे हुए दिनों पर टिकी हुई हैं। आगे भी अच्छी वर्षा नहीं हुई तो फसल खराब हो सकती है।

जून और जुलाई के महीने में बुंदेलखंड में औसत से पचास फीसदी कम वर्षा हुई है। सामान्य बारिश नहीं होने से झांसी की पहूज व बेतवा, महोबा की धसान और बांदा की केन नदी का जलस्तर गर्मियों जैसा ही है। सावन निकलने के बाद भादौ शुरू हो चुका है। जबकि, इस समय तक तो पिछले वर्षों तक नदियां लबालब हो जाती थीं। नदियों से नहरों में पानी जाता है। फिर इनके जरिए खेतों में सिंचाई होती है। नहरें सूखी होने से फसलों की सिंचाई पर भी असर पड़ा है।

इन दिनों उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली, धान की बुवाई हो चुकी है। इनमें से सबसे ज्यादा पानी धान को चाहिए होता है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक एक किलो धान के लिए तीन हजार लीटर से ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में कम बारिश से इस फसल पर सीधा असर पड़ा है। वहीं, उड़द, मूंग, मूंगफली को हर सप्ताह एक बार तो पानी की आवश्यकता पड़ती ही है। ऐसे में बुंदेलखंड में कहीं पानी न गिरने से फसलों का जमाव नहीं हो पाया, तो कहीं कुछ हद तक पानी गिरा भी तो फसल की बढ़त नहीं हो पाई। चूंकि, बुंदेलखंड में 15 सितंबर तक बारिश का सीजन रहता है। ऐसे में आगे के दिनों में भी अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसलों को काफी नुकसान पहुंच सकता है।

झांसी समेत बुंदेलखंड में ज्यादातर लाल मिट्टी है। विशेषज्ञों के मुताबिक लाल मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होती है। ऐसे में रुकने के बजाय पानी निकल जाता है। कृषि वैज्ञानिक डॉ. मुकेश चंद्र कहते हैं कि 6 जुलाई से 22 जुलाई तक बुंदेलखंड के कई जगहों पर पानी नहीं गिरने से फसलों का जमाव नहीं हो पाया है। जहां कुछ पानी गिरा भी तो वहां फसल की वृद्धि पूरी तरह नहीं हो पाई। अब सितंबर के प्रथम सप्ताह तक फसलों को अच्छी बरसात की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते उम्मीद भी है कि फसलों को जरूरत के अनुसार

देश और दुनिया में बुंदेलखंड की पहचान सूखा, गरीबी, पलायन और बेरोजगारी के रूप में है, लेकिन अब यहां के लोग हालात बदलना चाहते हैं। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं।



धान को चाहिए होता है दोगुना पानी

बुंदेलखंड में अभी उड़द, मूंग, तिल और मूंगफली की फसलें लगाई गई हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी सिर्फ इतना पानी इन फसलों को मिल रहा है कि यह जिंदा रह सकें। अगर आगे पानी नहीं गिरता है तो दिक्कत होगी। उन्होंने बताया कि धान को तो दोगुना पानी चाहिए होता है। झांसी के चिरगांव, मोंट, बड़ागांव में किसानों ने धान की रोपाई की है। वहीं, नहरों में भी कम पानी होने से किसानों की समस्या बढ़ गई है। धान को सप्ताह में एक दिन पानी मिल जाना चाहिए। उड़द, मूंग, तिल और मूंगफली को सप्ताह में पानी मिलते रहना चाहिए। वरना फसल हो नुकसान पहुंच सकता है। बुंदेलखंड के किसी भी जिले में अब तक औसत वर्षा नहीं हुई है। सिर्फ बांदा में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। हफ्ते भर तक अभी हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है।

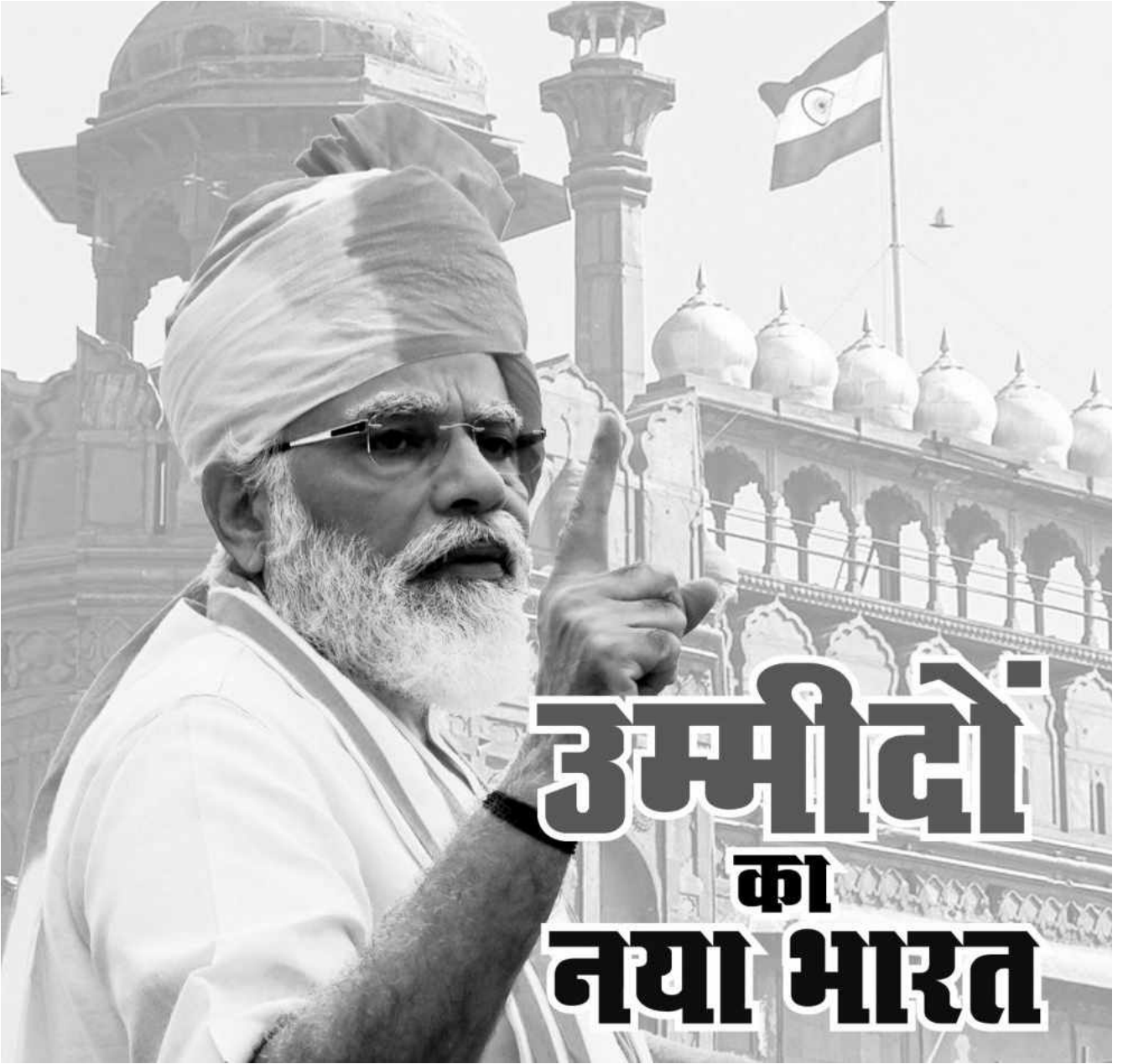
पानी मिल जाएगा।

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के कुलपति डॉ. अरविंद कुमार कहते हैं कि जितनी बरसात हुई है, उससे तिल को तो कोई समस्या नहीं हुई है। वहीं, जिन इलाकों में मूंगफली की बुवाई हुए 40 से 45 दिन हो गए हैं, वहां पानी की कमी होगी तो दाने छोटे रह जाएंगे। बुंदेलखंड में बारिश को लेकर अनिश्चितता रहती है। ऐसे में किसानों को मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आदि की तरफ भी ध्यान देना होगा। यह कम पानी में हो जाती है। क्षेत्र के लिए उपयुक्त भी हैं।

बुंदेलखंड में औसत वर्षा 800 से 900 मिलीमीटर है। जबकि, जून में 70 से 75 और जुलाई में 295 से 300 मिलीमीटर बारिश होती है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल झांसी में पिछले दो माह में 201 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। इसमें जून में 76 तो जुलाई में 125.5 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो कि सिर्फ 54 प्रतिशत है। सिर्फ बांदा में 300 मिलीमीटर के आसपास बरसात हुई है। बाकी हर जगह हालात झांसी जैसे ही हैं। बुंदेलखंड के किसी भी जिले में औसत बारिश नहीं हुई है। ऐसे में अगस्त में अच्छी बरसात नहीं हुई तो फसलों के लिहाज से हालात बिगड़ जाएंगे। हालांकि, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बाकी बचे मानसूनी सीजन में अच्छी बारिश हो सकती है।

बुंदेलखंड प्राकृतिक आपदाओं का शिकार रहता है। कभी यहां सूखा पड़ जाता है तो कभी ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होता है। इस बार समय से प्री-मानसूनी बारिश की शुरुआत हो जाने के बावजूद सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। जुलाई और अगस्त में 50 फीसदी बारिश ही हो पाई है। वहीं, जिलों की बात करें तो कुछ जगहों पर तीस फीसदी तक ही वर्षा हुई है। इस समय उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली और धान की बुवाई की जा चुकी है। इनमें से तिल की फसल तो ठीक है लेकिन बाकी पर पानी न गिरने से असर पड़ा है। सबसे खराब हालत तो धान की है। बुंदेलखंड में मानसूनी सीजन 15 सितंबर तक होता है। ऐसे में अब निगाहें अगस्त और सितंबर पर टिकी हुई हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक धान को छोड़कर बाकी फसलों की लागत काफी कम होती है मगर इनसे किसानों का भविष्य तय होता है। फसल से आमदनी होने पर किसान अक्टूबर में बोई जाने वाली अलसी, चना, मटर, मसूर, राई के लिए बीज, डीजल आदि का बंदोबस्त कर लेता है। इन फसलों से मुनाफा नहीं होने पर किसानों को उधार लेना पड़ता है।

● सिद्धार्थ पांडे



उम्मीदों का नया भारत

देश की आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीदों के नए भारत की तस्वीर दुनिया के सामने रखी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भारत कई मामलों में विश्व का सिरमौर बनेगा। साथ ही उन्होंने भविष्य की दिशा और दशा का भी खाका खींचा। इससे उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में हमारे देश में उम्मीदों का उदय होगा। जिससे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।

● राजेंद्र आगाल

15

अगस्त पर प्रधानमंत्री का भाषण ना सिर्फ हमारी देश की वर्तमान स्थिति को बतलाता है बल्कि भविष्य में हम किस दिशा की ओर बढ़ेंगे इसकी भी रूपरेखा तय करता है। हमारी विदेश नीति हो या कूटनीति या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो,

तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री देश के सामने अपनी बात रखते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास की तस्वीर प्रस्तुत की है। वैसे तो हर साल विकास का खाका प्रस्तुत किया जाता है लेकिन इस बार प्रधानमंत्री कुछ अलग ही अंदाज में दिखे। इसकी वजह यह रही कि मंदिर निर्माण की शुरुआत के साथ ही सरकार

का आत्मविश्वास बढ़ा है। यह आत्मविश्वास हमें नए भारत की ओर ले जाएगा। गौरतलब है कि आजादी के 73 बसंत बाद भी हमें कई समस्याओं पर विजय हासिल करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के मन में विश्वास जगाया है कि आने वाला समय समस्याओं पर विजय का होगा।



15 अगस्त, 1947 को मिली आजादी के बाद से ही भारत कई समस्याओं से जूझता रहा है। जब हम गुलामी में थे तब चीन जापान से युद्ध के बाद फिर से गृहयुद्ध में था और जापान, जर्मनी जैसे देश विश्वयुद्ध के ध्वंस के बाद हमारी जैसी स्थिति में थे। वे सब अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में लग गए और हम समाजवाद, विश्वशांति, जातीय-भाषाई जागरण, यूनियनबाजी आदि में व्यस्त रहे। हमने राष्ट्रनिर्माण का कोई ठोस अभियान नहीं चलाया। क्षेत्र-भाषावार राज्य बनाए। फिर कश्मीर में युद्धविराम, 370, 35-ए के साथ कश्मीर की समस्या खड़ी की। लेकिन 2014 के बाद कई समस्याओं का निराकरण सुनियोजित तरीके से हो रहा है। इसलिए 15 अगस्त को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के लिए उम्मीद की जो तस्वीर दिखाई है उसे देखकर लोग अहलादित हैं।

कई चुनौतियां सामने

कोरोनाकाल में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार लालकिले पर झंडा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। अपने 86 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, कोरोना संकट, आतंकवाद, विस्तारवाद, संप्रभुता, रिफॉर्म, मध्यमवर्ग, महिलाओं, किसानों, कामगारों और कश्मीर से लेकर लेह-लद्दाख तक का विशेष रूप से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पड़ोसी देशों की एक नई परिभाषा भी दी। उन्होंने कहा कि भौगोलिक सीमा से जुड़े देश ही पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि जिनसे हमारे दिल मिलते हैं, जो हमारी तरह समान विचारधारा रखते हैं, वह भी हमारे पड़ोसी हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी इतनी बड़ी विपत्ति नहीं कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रोक पाए। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के शुरू होने का ऐलान भी किया।

कई बदलाव किए गए

वैसे इसमें कोई शक नहीं कि आजादी के संघर्ष की कहानी उन असंख्य आजादी के दीवानों के उल्लेख के बिना हमेशा अधूरी मानी जाएगी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया, वे सब हमारे पूज्य हैं और इतिहास के अमर हस्ताक्षर हैं, उनको शत-शत बार प्रणाम है लेकिन आजादी के बाद के 73 सालों में बहुत कुछ बदला है और बीते 75 महीनों के मोदी कार्यकाल में तो इतना कुछ बदला है कि एक नया इतिहास बन गया। पिछले साल की स्वतंत्रता दिवस के आसपास जहां एक ओर जम्मू-कश्मीर से धारा-370 और 35ए का खात्मा हुआ तो वहीं तीन तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ। यही नहीं विगत वर्ष का अंत और इस वर्ष का प्रारंभ भी नागरिकता संशोधन कानून के लिए हमेशा याद किया जाएगा। यह सारे काम कमजोर इच्छाशक्ति वाली सरकार के वश के नहीं थे। ये सभी ऐसे निर्णय हैं जिनसे 70 सालों से चले आ रहे सामाजिक और सियासी असंतुलन को खत्म करने में मदद मिली है। आज कश्मीर की स्थिति में बदलाव ने वहां के लोगों की उन्नति के रास्ते खोल दिए हैं। सामाजिक-आर्थिक दशाओं में तो परिवर्तन हो ही रहे हैं, अधोसंरचना का विकास तीव्र गति से हो रहा है। वहां 70 सालों से राज्य के कई नागरिक अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे उन क्षेत्रों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया गया है। दुर्गम स्थानों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। निम्नतम स्थिति वाले वाल्मीकि समाज को सम्मानित नागरिक बनाने का काम किया गया है। यहां ऐसे कई वर्ग थे जिनके कोई संवैधानिक अधिकार नहीं थे उन्हें नई नीति बनाकर ना केवल नागरिकता प्रदान की गई बल्कि जीविकोपार्जन तथा चुनावों में भाग लेने के अधिकार दिए गए हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देकर अनेक परियोजनाओं के साथ विश्वविद्यालय की स्थापना तथा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की दिशा में द्रुत गति से काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को वैश्विक पटल पर लाने की तमाम योजनाओं, संकल्पों और कार्यों के बारे में भी बताया।

वस्तुतः यह स्वतंत्रता दिवस कोरोना की भयावहता और राम मंदिर निर्माण के भूमिपूजन के लिए इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। गौरतलब है कि आखें खुलीं तो हमारे सामने 1947 से चले आ रहे असंभव से सपनों की एक शृंखला थी। सवाल थे कि अनुच्छेद-370, धारा 35-ए का खात्मा और पीओके की वापसी कभी हो पाएगी? हमारी अर्थव्यवस्था जैसे चीन की पूरक अर्थव्यवस्था होती जा रही थी। सरकारी खर्च बढ़ाकर जीडीपी बढ़ाई जा रही थी। बैंकों को बड़े ऋण देने के लिए बाध्य किया जा रहा था। परिवर्तन की व्यग्र प्रतीक्षा के बीच बदलाव का दूसरा दौर 2014 से प्रारंभ हुआ। कर्मठता, जनसरोकार और समावेशी राष्ट्रवाद इस परिवर्तन की पहचान बने। समानांतर अर्थव्यवस्था और आर्थिक अपराध पर लगातार हमले जारी हैं। अनुच्छेद-370 और धारा 35-ए इतिहास हो गईं। जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। नागरिकता विवाद समाप्त हुआ। वहां आतंकवाद अंतिम सांसों गिन रहा है और जनप्रतिनिधियों की नई पौध आ रही है। पीओके का जो लक्ष्य कभी दूर था वह दिखना प्रारंभ हो गया है।

नई उम्मीदें

प्रधानमंत्री ने जो बातें कहीं उनमें नई शिक्षा नीति, आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोरोना से भारत की लड़ाई, जम्मू-कश्मीर में चुनाव, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन और राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास, चीन-पाकिस्तान पर परोक्ष निशाना और सीमावर्ती इलाकों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या बढ़ाना और उनका प्रशिक्षण मुख्य है। राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में तो प्रधानमंत्री 5 अगस्त को ही बहुत विस्तार से बोले थे। शिलान्यास के बाद उन्होंने अयोध्या में ही लंबा भाषण दिया था, इसलिए इस बारे में उनके पास बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं था। हां, यह पहली बार हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का जिक्र लाल किले से किया।

जहां तक नई शिक्षा नीति की बात है तो प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त को अयोध्या से लौटने के एक दिन बाद ही शिक्षा पर हुए एक सम्मेलन में बहुत विस्तार से शिक्षा नीति के बारे में बोला था। पिछले दो हफ्ते में वे दो बार विस्तार से इस बारे में बोल चुके हैं। सो, इस बारे में भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसके बारे में लगभग सारी बातें प्रधानमंत्री खुद देश के लोगों को बता चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 11 अगस्त को देश के सबसे ज्यादा संक्रमण वाले दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस की

रोकथाम को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। इससे पहले भी कई बार वे कोरोना के मसले पर मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके हैं। 11 अगस्त की बातचीत में उन्होंने दावा किया कि कोरोना से भारत की लड़ाई सही दिशा में जा रही है। हालांकि हकीकत यह है कि भारत में अब हर दिन 60 हजार से ज्यादा मामले आ रहे हैं और एक हजार लोगों की रोज मौत हो रही है। फिर भी उनका दावा है कि लड़ाई सही दिशा में जा रही है। बहरहाल, 11 अगस्त को मुख्यमंत्रियों से बातचीत में उन्होंने जो कुछ कहा वहीं लाल किले से भी कहा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

जहां तक आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात है तो मई के महीने से लेकर अभी तक इस मुद्दे का ऐसा तेल निकाला जा चुका है कि अब इसमें निचोड़ने के लिए एक बूंद तेल नहीं बचा है। पहले तो प्रधानमंत्री ने खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में इसका ऐलान किया था। उसके बाद 5 दिन लगातार प्रेस कांफ्रेंस करके वित्त मंत्री ने इस अभियान के बारे में एक-एक बात बताई। इसके बाद तीन महीने में इसके हर पहलू की व्याख्या की जा चुकी है। खुद प्रधानमंत्री अनगिनत बार इसके बारे में बता चुके हैं। फिर भी लाल किले से 87 मिनट के भाषण में उन्होंने 30 बार आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया।

एलएसी और एलओसी

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से होने वाले भाषण से पहले हर बार भारत के लोगों को यह जिज्ञासा रहती है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बारे में क्या बोलते हैं। इस बार यह भी जिज्ञासा थी कि प्रधानमंत्री चीन के बारे में क्या बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों के बारे में परोक्ष रूप से अपनी बात कही। उन्होंने आतंकवाद और विस्तारवाद दोनों के दिन खत्म होने की बात कही, जिसमें पाकिस्तान और चीन का जिक्र छिपा था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एलएसी से लेकर एलओसी तक जिसने भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत की उसे सुरक्षा बलों ने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। वैसे भी प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण करते हुए किसी दूसरे देश का नाम लेकर उस पर हमला नहीं कर सकते। तभी यह भी कोई नई बात नहीं थी। पिछले अनेक वर्षों से देश के प्रधानमंत्री लाल किले से आतंकवाद, पाकिस्तान आदि को परोक्ष रूप से निशाना बनाते रहे हैं। सो, नया कुछ नहीं था प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए। उन्होंने पुरानी सारी बातें दोहराईं। वे जिन बातों पर चुप रहे वो बातें ज्यादा अहम हैं। जैसे उन्होंने देश के आर्थिक मंदी के दुष्क्रम में फंसने का जिक्र नहीं किया। उन्होंने देश के करोड़ों लोगों के फिर से गरीबी रेखा के नीचे



लाल किले पर बहुत कुछ पहली बार

इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से होने वाला सालाना आयोजन और प्रधानमंत्री के भाषण में बहुत कुछ पहली बार हुआ। पहले, कोरोना वायरस की वजह से आयोजन की रूप-रेखा में बदलाव हुआ था और दूसरे, प्रधानमंत्री का भाषण भी पहले से अलग था। लाल किले से मोदी के सात बार के भाषण में यह पहली बार हुआ कि वे कागज देख कर भाषण दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा भाषण लिखा हुआ था और तभी वे हर लाइन के बाद नीचे कागज देख रहे थे। इससे पहले भी वे कागज लाते थे पर वे नोट्स की शकल में होते थे और प्रधानमंत्री धाराप्रवाह ही बोलते थे। इस बार इस बार लाइन के बाद वे नीचे देख रहे थे। भारत में राम जन्मभूमि का विवाद सदियों से चल रहा था। पर इससे पहले संभवतः किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र लाल किले से अपने भाषण में नहीं किया था। बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छह बार लाल किले से भाषण दिया और उनके समय भी अयोध्या का मुद्दा भाजपा के घोषणापत्र में था पर उन्होंने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इसका जिक्र नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने भी अपने पहले छह भाषणों में इसका जिक्र नहीं किया। अपने सातवें भाषण में मोदी ने लाल किले से इस विवादित मुद्दे का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में लाल किले से स्वच्छता और शौचालय का जिक्र किया था। तब भी यह हैरान करने वाली बात थी। इस बार उन्होंने गांव की और गरीब महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का जिक्र किया। पहली बार किसी ने लाल किले की प्राचीर से इस जरूरी मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने एक रुपए की कीमत पर 5 करोड़ सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए हैं। इस तरह गांव और गरीब महिलाओं की सेहत की चिंता उन्होंने जताई। आयोजन में भी कई चीजें पहली बार हुईं। पहली बार इतनी कम संख्या में लोगों को बुलाया गया। बहुत चुनिंदा मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों की मौजूदगी लाल किले की प्राचीर पर रही। इस बार बच्चे भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए नहीं बुलाए गए थे। सामने मैदान में सिर्फ एनसीसी के कैडेट्स थे। हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी उतर कर उनसे मिलने नहीं गए। उन्होंने गाड़ी से ही हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया।

पहुंचने का जिक्र नहीं किया। देश की बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में है और कोरोना से लड़ने की हकीकत यह है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में आज भी लोग जांच और इलाज के लिए अस्पताल-अस्पताल भटक रहे हैं। अगर इन बातों का जिक्र करके प्रधानमंत्री देश के लोगों को भरोसे में लेते तो बेहतर होता।

नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक नए हेल्थ मिशन की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। यही नहीं देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को विश्वास

दिलाया कि देश के वैज्ञानिक दिन-रात एक कर कोरोना महामारी को परास्त करने में जुटे हैं। इसके लिए वह दिन-रात वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज भारत में कोरोना की एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन वैक्सीन्स टेस्टिंग के चरण में हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, वैसे ही देश की तैयारी उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की भी है।' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन-सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थीं, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ आईडी में समाहित होगी।



नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा, 'कोरोना के समय में हमने देख लिया है कि डिजिटल भारत अभियान की क्या भूमिका रही है। अभी पिछले महीने ही करीब-करीब 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन अकेले भीम यूपीआई से हुआ है। साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं। बीते पांच साल में देश में डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'आने वाले एक हजार दिन में इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। आने वाले एक हजार दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा।' देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि भारत इस संदर्भ में सचेत है, सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है और नई-नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित कर रहा है। देश में नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है।

सरकारी दखलअंदाजी से मुक्ति चाहिए

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मध्यम वर्ग से निकले प्रोफेशनल्स भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाते हैं। मध्यम वर्ग को अवसर चाहिए, मध्यम वर्ग को सरकारी दखलअंदाजी से मुक्ति चाहिए। ये भी पहली बार हुआ है जब अपने घर के लिए होम लोन की ईएमआई पर भुगतान अवधि के दौरान 6 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है।' 'अभी पिछले वर्ष ही हजारों अधूरे घरों को पूरा करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए के फंड की स्थापना हुई है। एक आम भारतीय की शक्ति, उसकी ऊर्जा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा आधार है। इस ताकत को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर, निरंतर काम हो रहा है।' 'आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक

भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में, देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है।'

110 जिलों में विशेष प्रयास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा- 'विकास के मामले में देश के कई क्षेत्र भी पीछे रह गए हैं। ऐसे 110 से ज्यादा आकांक्षी जिलों को चुनकर, वहां पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, रोजगार के बेहतर अवसर मिलें। आत्मनिर्भर भारत की एक अहम प्राथमिकता है- आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान। देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही एक लाख करोड़ रुपए का 'एग्रीकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फंड' बनाया गया है। इसी लाल किले से पिछले वर्ष में जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। आज इस मिशन के तहत अब हर रोज एक लाख से ज्यादा घरों को पानी के कनेक्शन जोड़ने में सफलता मिल रही है।

प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा- 'आज दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ-साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। भारत को आधुनिकता की तरफ, तेज गति से ले जाने के लिए, देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा देने की जरूरत है। ये जरूरत पूरी होगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट से। इस पर देश 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलग-अलग सेक्टरों के लगभग 7 हजार प्रोजेक्ट्स को आईडेंटिफाई भी किया जा चुका है। ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई क्रांति की तरह होगा।

प्रधानमंत्री की प्रमुख घोषणाएं

15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भविष्य के भारत का जो खाका प्रस्तुत किया उसमें कई घोषणाएं की गईं। जिनमें प्रमुख घोषणाएं हैं...

फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के द्वीपों को लेकर कहा, अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाएगा।

दक्षिण एशिया में विकास महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वो हमसे जमीन से जुड़े हों या समंदर से, अपने संबंधों को हम सुरक्षा, विकास और विश्वास की साझेदारी के साथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, दक्षिण एशिया में दुनिया की एक चौथाई जनसंख्या रहती है। हम सहयोग और सहभागिता से इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास और समृद्धि की अनगिनत संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। इस क्षेत्र के देशों के सभी नेताओं की इस विशाल जन समूह के विकास और प्रगति की ओर एक अहम जिम्मेदारी है।

प्रोजेक्ट लॉयन की होगी शुरुआत

प्रधानमंत्री मोदी ने देश में जैव विविधता को लेकर कहा, अपनी जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। बीते कुछ समय में देश में शेरों की, बाघों की आबादी तेज गति से बढ़ी है। अब देश में हमारे एशियाई शेरों के लिए एक प्रोजेक्ट लॉयन की भी शुरुआत होने जा रही है।

लददाख जल्द बनेगा कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र

प्रधानमंत्री मोदी ने लददाख के विकास को लेकर कहा, जिस प्रकार से सिक्किम ने ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में अपनी पहचान बनाई है, वैसे ही आने वाले दिनों में लददाख, अपनी पहचान एक कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र के तौर पर बनाए, इस दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है।

लोगों की बनेगी हेल्थ आईडी

नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर प्रधानमंत्री ने बताया, आपको हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थीं, ये सारी जानकारी एक हेल्थ आईडी में समाहित होगी।

जनधन खातों का आधा हिस्सा महिलाओं का

प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के खाते को लेकर कहा, देश के जो 40 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, उसमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। कोरोना के समय में अप्रैल-मई-जून, इन तीन महीनों में महिलाओं के खातों में करीब-करीब 30 हजार करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई विकासात्मक योजनाओं की घोषणा की है। जिससे नए भारत की आधारशिला मजबूत होगी।

अब इंफ्रास्ट्रक्चर में सिलोस को खत्म करने का युग आ गया है। इसके लिए पूरे देश को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है।'

क्रिएटिविटी और स्किल्स को बढ़ाना

अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दिया। उन्होंने कहा- 'आखिर कब तक हमारे ही देश से गया कच्चा माल, फिनिश प्रोडक्ट बनकर भारत में लौटता रहेगा। एक समय था, जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। तब सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरे। आज हम सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों का पेट भर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना ही नहीं, हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी हमारी स्किल्स को बढ़ाना भी है। सिर्फ कुछ महीने पहले तक एन-95 मास्क, पीपीई किट, वेंटिलेटर ये सब हम विदेशों से मंगाते थे। आज इन सभी में भारत, न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया है। वोकल फॉर लोकल, रि-स्किल और अप स्किल का अभियान, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों के जीवनस्तर में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का संचार करेगा।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के इस असाधारण समय में, सेवा परमो धर्म: की भावना के साथ, अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सेवाकर्मी, अनेकों लोग, चौबीसों घंटे लगातार काम कर रहे हैं। इन सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूँ।

एनसीसी का होगा विस्तार

प्रधानमंत्री ने कहा- 'अब एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर का विस्तार देश के 173 बार्डर और तटीय जिले तक सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान के तहत करीब 1 लाख नए एनसीसी कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें भी करीब एक तिहाई बेटियों को ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी।' प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमने अपनी बेटियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद हम उचित निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा- 'भारत में महिलाशक्ति को जब-जब भी अवसर मिले,



उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। देश के जो 40 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, उसमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। कोरोना के समय में अप्रैल-मई-जून, इन तीन महीनों में महिलाओं के खातों में करीब-करीब 30 हजार करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं।'

ये साल विकास यात्रा का है

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये एक साल जम्मू-कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का साल है। ये एक साल जम्मू-कश्मीर में महिलाओं, दलितों को मिले अधिकारों का साल है। ये जम्मू-कश्मीर में शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल है। लोकतंत्र की सच्ची ताकत स्थानीय इकाइयों में है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जम्मू-कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते वर्ष लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर, वहां के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख आज विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से सिक्किम ने ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में अपनी पहचान बनाई है, वैसे ही आने वाले दिनों में लद्दाख, अपनी पहचान एक कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र के तौर पर बनाए, इस दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है।

राम मंदिर निर्माण मील का पथर

गुटनिरपेक्षता, राष्ट्रीय राजनीति में तुष्टीकरण, राज्यों में भाषा-जातिवादी आग्रह हमारा बेड़ा गर्क कर रहे थे। 2014 और फिर 2019 ने इसे बदल दिया है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति सभ्यता का देश अपनी संस्कृति को लेकर एक अपराधी के समान क्षमाप्रार्थी हो रहा था। राष्ट्र, संस्कृति की बात करने वाले नए अछूत बन गए थे। राम मंदिर का पुनर्निर्माण शताब्दियों की व्यग्रता की परिणीति है। बात-बात पर अपने को एटॉमिक पावर बताने वाले पाकिस्तान की सर्जिकल और बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद जो हैसियत है वह अब किसी से छिपी नहीं है।

अभी चीन के साथ डोकलाम के बाद लद्दाख में बराबरी का मोर्चा लगा हुआ है। सेनाओं की जरूरतें बड़ी तेजी से पूरी की जा रही हैं। पहली बार सैन्य रणनीति की महत्ता को स्वीकार करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसा पद सृजित किया गया है। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी है। हमें अब कॉमन सिविल कोड की दिशा में चलना है। राजनीति का जाति-संप्रदायवाद एक बड़ी समस्या है। राज्यों तक सीमित राष्ट्रीय सरोकारविहीन भाषा-जाति आधारित परिवारवादी दल दूसरी बड़ी समस्या हैं। समग्र राष्ट्र की सोच जब उनके संविधान में ही नहीं है तो गठबंधन के केंद्रीय दायित्वों में वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के अतिरिक्त और क्या करेंगे? ये क्षत्रप राष्ट्रीय राजनीति को स्वहित के रिमोट से चलाते हैं। इनसे मुक्ति राष्ट्रपतीय लोकतंत्र के माध्यम से ही संभव है।

भारत ने असाधारण समय में असंभव को संभव किया

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत ने असाधारण समय में असंभव को संभव किया है। इसी इच्छाशक्ति के साथ प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ना है। वर्ष 2022, हमारी आजादी के 75 वर्ष का पर्व, अब बस आ ही गया है। उन्होंने कहा, 21वीं सदी के इस दशक में अब भारत को नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अब साधारण से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीते वर्ष मैंने यहीं लाल किले से कहा था कि पिछले 5 साल देश की अपेक्षाओं के लिए थे, और आने वाले 5 साल देश की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होंगे। बीते एक साल में ही देश ने ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण फैसले लिए, अनेकों महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए।

साल 1968 में घोषित पहली शिक्षा नीति हर आदमी के जीवन को समृद्ध करने, राष्ट्र की प्रगति और सुरक्षा में उन्हें योगदान देने की शक्ति देने, साझी नागरिकता और संस्कृति को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की परिकल्पना पर आधारित थी। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इसकी घोषणा की थी। हर स्तर पर गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा के अवसर के निरंतर विस्तार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर फोकस के साथ 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और नैतिक मूल्यों के विकास की इस नीति में शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव की जरूरत बताई गई थी।

पहली शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) (जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना गया) की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई थी। राज्यों के ज्यादा रुचि न दिखाने के कारण उसके ज्यादातर प्रस्ताव कागजों पर ही रह गए। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि इसमें 10+2+3 पैटर्न को पूरे देश में एक समान लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन तब तक संविधान के तहत शिक्षा पूर्ण रूप से राज्य का विषय था।

42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया और इसके अगले साल 10+2+3 पैटर्न भी लागू किया गया। हालांकि बाद के वर्षों में शैक्षिक सुविधाओं में व्यापक विस्तार दिखा, लेकिन 1968 की नीति की अनेक बातों पर अमल न हो सका। नतीजा यह हुआ कि शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता, उपयोगिता और खर्च जैसी समस्याएं साल दर साल बढ़ती गईं।

समस्या के समाधान के लिए मई 1986 में राजीव गांधी सरकार दूसरी शिक्षा नीति लेकर आई। 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में इसमें कुछ अतिरिक्त बातें जोड़ी गईं। इनमें शिक्षा की पहुंच के नए लक्ष्य तय करने के साथ परीक्षा प्रणाली में सुधार करना शामिल था। 1986 की नीति में सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने, ऐसी व्यवस्था करने जिससे 14 वर्ष तक के बच्चे स्कूल न छोड़ें और शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सबको शिक्षा का समान



नीति के साथ नियत भी बदलनी होगी

अवसर उपलब्ध कराने के साथ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों में सुधार पर भी जोर दिया गया।

इसके अलावा, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक स्तर से पहले के बच्चों की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई), रोजगारपरक शिक्षा, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा और मूल्यपरक शिक्षा दूसरी नीति के मुख्य आधार थे। इसमें शोध को बढ़ावा देने के अलावा छात्रों को कैरियर के विकल्प के रूप में स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1986 की नीति लागू होने के बाद शिक्षण सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ। हालांकि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू करने में 41 साल लग गए। इसे अंततः 2009 में लागू किया जा सका। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार देश में 993 विश्वविद्यालय, 39,931 महाविद्यालय और 10,725 स्टैंडअलोन संस्थान हैं। इनकी बढ़ौतल अमेरिका और चीन के बाद भारत उच्च शिक्षा संस्थानों का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। स्कूलों की संख्या भी 15.50 लाख हो गई, जिनमें 24.78 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। फिर भी, पहली और दूसरी नीति के कई एजेंडे अभी अधूरे हैं।

इसे आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार हाल ही नई शिक्षा नीति लेकर आई है। इसमें

स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए बड़े 'परिवर्तनकारी सुधार' प्रस्तावित हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई शिक्षा नीति-2020 में 10+2 पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 में बदलने का प्रस्ताव है, ताकि तीन से 18 वर्ष के छात्रों के लिए ईसीसीई को औपचारिक स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जा सके और 2030 तक स्कूली शिक्षा सर्वसुलभ हो।

स्कूली शिक्षा के शुरुआती चरण में ही कंप्यूटर साक्षरता की बात कही गई है ताकि छात्रों को 21वीं सदी के कौशल से लैस किया जा सके। छठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि 2025 तक कम से कम 50 फीसदी छात्रों को रोजगारमुखी शिक्षा मिल सके। बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकें, इसके लिए एनईपी-2020 में कम से कम पांचवीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा, घरेलू भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया है। इसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कक्षा तीन उत्तीर्ण होने तक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर लें।

● धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया

परीक्षा का तनाव कम करने पर जोर

छात्रों में परीक्षा का तनाव कम करने और रटने की व्यवस्था समाप्त करने के लिए, नीति में पाठ्यक्रम को फिर से डिजाइन करने का प्रस्ताव है ताकि कोर्स घटाया जा सके। इसमें मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव और बोर्ड परीक्षाओं को 'आसान' बनाने का भी प्रस्ताव है, ताकि इसे छात्रों की याद करने की क्षमता की परीक्षा के बजाय ज्ञान की परीक्षा बनाया जा सके। इस नीति में सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और अन्य प्रवेश परीक्षाओं में बदलाव का प्रस्ताव है। छात्रों के पास 10वीं के बाद पढ़ाई कुछ समय के लिए रोकने और बाद में फिर 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने का विकल्प होगा। एनईपी-2020 में अंडर-ग्रेजुएट की पढ़ाई चार साल करने और इसे बहुविषयक बनाने का प्रस्ताव है। छात्रों के पास किसी भी वर्ष पढ़ाई छोड़ने और बाद में फिर दाखिला लेने का विकल्प होगा। यह सुविधा तीन साल के अंडर-ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने वालों को भी मिलेगी।

कांग्रेस ऊहापोह में है। देश की सबसे पुरानी इस राजनीतिक पार्टी में पुराने और नए नेताओं के बीच गहरी खाई बन गई है। युवा तुर्क विद्रोह के मूड में हैं और उन्हें संभालने तथा राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है। या ये युवा नेता जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। आज के माहौल में, जबकि कांग्रेस की एक विपक्ष के रूप में देश में सबसे ज्यादा जरूरत है; यह पार्टी व्यापक जनाधार होते हुए भी एक तरह से अजीब-सी शून्यता की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस के भीतर मंथन का यह दौर क्या देश के सामने एक नई और ऊर्जावान कांग्रेस ला पाएगा? या यह पार्टी एक इतिहास बनकर रह जाएगी? क्या कांग्रेस की ओवरहॉलिंग की जबरदस्त जरूरत है?

यह 1998 की बात है, युवा नेता (तब) ममता बनर्जी कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री थीं। वह इस बात से बहुत खफा थीं कि कांग्रेस उनके गृह राज्य पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों की बी टीम जैसी हालत में है और नेतृत्व कुछ नहीं कर रहा। विद्रोही ममता चाहती थीं कि कांग्रेस एक पार्टी के रूप में वामपंथियों से लड़े और अपना मजबूत वजूद बनाए रखे। जब ऐसा नहीं हुआ, तो उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर अपनी अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना ली और वामपंथियों का मजबूत राजनीतिक विरोध करते हुए आज सत्ता में हैं। ममता की इस कहानी में ही कांग्रेस की वर्तमान हालत की दास्तां छिपी है। कांग्रेस ने राज्यों में खुद को बहुत कमजोर कर लिया है। जो राज्य कांग्रेस के हाथ में हैं, वो भी राजनीतिक षड्यंत्रों में उसके हाथ से निकल रहे हैं। मध्यप्रदेश और राजस्थान की घटनाएं वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच बनी गहरी खाई का इशारा करती हैं। ऐसे में सहज ही यह सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को एक और कामराज योजना की जरूरत है?

बता दें करीब 57 साल पहले दिग्गज कांग्रेस नेता कुमारस्वामी कामराज ने सरकार के पद त्यागकर संगठन को तरजीह देने का फार्मूला (जिसे कामराज योजना के नाम से जाना जाता है) सामने लाए; जिसने कांग्रेस को एक संगठन के रूप में मजबूत किया था। आज परिस्थितियां उसके विपरीत हैं और कांग्रेस न तो केंद्र की सत्ता में है, न उसके सामने की प्रतिद्वंद्वी पार्टी कमजोर है। लेकिन एक संगठन के रूप में कांग्रेस को

कांग्रेस को चाहिए एक और कामराज

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इस समय जिस समस्या से जूझ रही है उससे उबरने के लिए पार्टी को कामराज योजना अपनाना चाहिए। यह तभी हो पाएगा, जब पार्टी में के कामराज जैसा कोई दमदार नेता होगा।



आलाकमान का सरख रुख

यदि हाल के वर्षों की घटनाएं देखें, तो पहली बार कांग्रेस आलाकमान का रुख बदला हुआ दिखा है। पायलट वाले मामले में कार्रवाई को लेकर कांग्रेस इंदिरा गांधी के जमाने वाली सख्त कांग्रेस दिखी है। प्रदेशों में जब कांग्रेस को अपनी सरकारों की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसने सख्त रुख दिखाते हुए और राजस्थान में गहलोट सरकार की परवाह किए बगैर पायलट के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की थी, जबकि महज तीन महीने पहले ही मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले मामले में कांग्रेस आलाकमान निष्क्रिय-सी दिखी थी। निश्चित की आलाकमान के इस सख्त रुख से देशभर के कांग्रेस नेताओं में साफ संदेश गया है। यही कि अब नरमी नहीं बरती जाएगी और इस तरह की अनुशासनहीनता को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। एआईसीसी में पदाधिकारी एक कांग्रेस नेता ने बताया कि पार्टी नेतृत्व को गारंटी मान लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

जिंदा रखने के लिए निश्चित ही एक और कामराज योजना की आज सख्त जरूरत है, जिसमें नेता कमजोर संगठन को मजबूत करें। निश्चित ही कुर्सियों का लालच छोड़ नेताओं को संगठन की मजबूती के लिए काम करना होगा।

कामराज ने उस समय एक और अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कठिनाइयों का सामना करो, इससे भागो मत, समाधान खोजिए, भले ही वह छोटा हो, यदि आप कुछ करते हैं, तो लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन आज कांग्रेस में यही सब नहीं हो रहा है। और इसका कारण कांग्रेस के भीतर ही है। वरिष्ठ और युवा नेता विपरीत ध्रुवों पर खड़े दिख रहे हैं। वर्चस्व की यह जंग पार्टी में जमीनी स्तर की इकाइयों तक पहुंच गई है।

राजस्थान में सचिन पायलट और उससे पहले मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैसा संकट कांग्रेस के सामने पैदा किया, वह बताता है कि युवा नेताओं का पार्टी से मोहभंग हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस से चार दशक तक जुड़े रहे एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि निश्चित ही कांग्रेस की ओवरहॉलिंग (पुनर्गठन) का वक्त आ गया है और **युवाओं की एक मजबूत टीम** बनाने की जरूरत है, जिसमें कुछ ऐसे वरिष्ठ नेताओं की भी भागीदारी हो; जो संगठन के लिहाज से सक्रिय हैं।

हालत यह है कि केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियों को भी जनता के सामने लाने के लिए पार्टी नेता उत्सुक नहीं हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भले मुखर हों, वरिष्ठ नेता उनके इस मोदी विरोध को ताकत देने के लिए कहीं भी साथ खड़े नहीं दिखते। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आसपास बुजुर्ग नेताओं का ऐसा गठजोड़ बन गया है, जो भले ही राजनीति में निपुण हों, लेकिन वे इसका इस्तेमाल विरोधी भाजपा से टक्कर लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर युवा नेतृत्व के उभरने में रोड़े अटकाने के लिए कर रहे हैं। इस नीति ने कांग्रेस को खोखला करना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद इस आरोप से सहमत नहीं हैं कि वरिष्ठ नेताओं ने कोई कोठरी बना रखी है। एक इंटरव्यू में आजाद ने कहा कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। संगठन में युवाओं की भरमार है और वे कई जगह पार्टी को नेतृत्व भी दे रहे हैं। क्योंकि हम लगातार दो बार से सत्ता में नहीं हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है; लेकिन



कामराज योजना की जरूरत

कांग्रेस जिस दौर में है, उसे आज एक और कामराज योजना की सख्त जरूरत है। दिग्गज कांग्रेस नेता कुमारस्वामी कामराज ने तीन बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर, 1963 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही। उनका कहना था कि कांग्रेस के सब बुजुर्ग नेताओं में सत्ता लोभ घर कर रहा है और उन्हें वापस संगठन में लौटना चाहिए और लोगों से जुड़ना चाहिए। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को कामराज की यह योजना इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी में लागू करने का मन बनाया। भारतीय राजनीति में यह योजना कामराज प्लान के नाम से मशहूर हुई। कामराज योजना लागू करने के नेहरू के फैसले का नतीजा यह निकला कि उनके मंत्रिमंडल के 6 मंत्रियों और 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को त्याग-पत्र देना पड़ा। कैबिनेट मंत्रियों में भी तमाम दिग्गज शामिल थे। इनमें मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम और एसके पाटिल शामिल थे। मुख्यमंत्रियों में चंद्रभानु गुप्त, मंडलोई और बीजू पटनायक जैसे दिग्गज शामिल थे। इस सफल प्रयोग के बाद कामराज को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इस योजना को देखें, तो 2014 में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद भाजपा ने भी कमोबेश इसी तर्ज पर मार्गदर्शक मंडल बनाया और लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को इसमें डाल दिया। हां, कामराज योजना के विपरीत भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं को सरकार ही नहीं, एक तरह संगठन से भी बाहर कर दिया, जबकि कांग्रेस ने अपने नेताओं को तब संगठन और जनता से संपर्क का जिम्मा दिया था। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस की कामराज योजना कहीं बेहतर और सम्मानजनक थी।

यह सच्चाई नहीं है। कांग्रेस ही देश में एक ऐसा राजनीतिक दल है, जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है।

आजाद कहते हैं कि मोदी सरकार कोरोना से लेकर चीन तक के मुद्दे पर एक्सपोज हुई है। अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। महामारी को ठीक से नहीं संभाल पाने के कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और जनता में मोदी नीत केंद्र सरकार के प्रति गहरी निराशा और नाराजगी है। लेकिन भाजपा चुनी हुई सरकारें गिराने में लगी है। हाल के कई विधानसभा चुनावों में जनता ने उसे बुरी तरह नकार दिया है। जनता से समर्थन नहीं मिलने के बावजूद वह पैसे के जोर पर कांग्रेस की राज्य सरकारें तोड़कर अपनी सरकारें बना रही है।

नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस नेता ने कहा कि निश्चित ही पार्टी में युवाओं के मन में नाराजगी है। राहुल गांधी को जब अध्यक्ष बनाया गया, तब उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने तीन राज्यों में सरकारें बनाईं। राफेल,

अर्थव्यवस्था, रोजगार, युवाओं और किसानों से लेकर तमाम मुद्दों पर राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी से अकेले लोहा लिया। लेकिन लोकसभा के चुनाव में वरिष्ठ नेताओं ने निष्क्रियता दिखाई। वे कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देते; क्योंकि इससे उन्हें अपने अप्रासंगिक होने का डर सताने लगता है।

इस युवा नेता की यह बात कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं और वरिष्ठों के बीच बन चुकी गहरी खाई की तरफ इशारा करती है। यदि हाल की घटनाओं की तरफ देखें, तो जाहिर हो जाता है कि पार्टी के भीतर युवा नेता इन बुजुर्ग हो चुके नेताओं से मुक्ति चाहते हैं।

सचिन पायलट के भाजपा से साठगांठ करने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोप के बाद पार्टी के बीच युवा नेताओं ने एक के बाद एक जिस तरह पायलट के समर्थन में सुर मिलाए, वह इस बात का संकेत है कि वरिष्ठ नेताओं और उनके बीच कितनी दूरी बन चुकी है। हालांकि यह भी सच है कि आवाज उठाने वाले इन

नेताओं में ज्यादातर राजनीतिक परिवारों की ही पीढ़ी के नेता हैं, जिन्हें काफी कम उम्र में ही सत्ता में हिस्सा मिला है। आम युवा नेता तो खामोशी से हालात पर नजर जमाए हैं, जो यह तो मानते हैं कि युवाओं को ज्यादा अवसर मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर देते हैं कि वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व भी साथ में ही चलना चाहिए। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव युवा नेता नीरज गुप्ता ने कहा कि यदि हाल की घटनाओं को देखें, तो पता चलेगा कि कथित विद्रोह वे युवा नेता कर रहे हैं, जिन्हें छोटी उम्र में ही पार्टी ने सब कुछ दे दिया। यह नेता जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं; जिनमें ज्योतिरादित्य और पायलट भी शामिल हैं। जमीन पर हम जैसे युवा नेता वैसा नहीं सोचते, जैसा पायलट आदि कर रहे थे। खैर अभी राजस्थान में पायलट वापस कांग्रेस में लौट आए हैं।

गुप्ता ने कहा कि यह ठीक है कि वरिष्ठ नेताओं को चाहिए कि वे युवाओं को प्रोत्साहित करें। युवाओं को अवसर भी मिलने चाहिए; लेकिन साथ ही यदि हम जैसे युवा नेता वरिष्ठों का अन्याय करने लगें, तो यह भी गलत है। आखिर इन वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के लिए अपना सब कुछ खपा दिया है। कांग्रेस में राजनीतिक परिवारों के लोग बहुतायत में हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इन युवा नेताओं को ही सत्ता में दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा हिस्सा मिला है और विरोध के तेवर भी इन नेताओं ने ही दिखाए हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या यह युवा नेता जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें पाल बैठे हैं? वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस मामलों के जानकार एसपी शर्मा ने कहा कि पायलट के उदाहरण से तो यही लगता है कि उन्हें सब कुछ सही मिल रहा था और कुछ साल में मुख्यमंत्री भी बन जाते। लेकिन उन्होंने अति महत्वाकांक्षा या बहकावे में आकर एक पल के लिए सब कुछ गंवा दिया था।

राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस को अब ऐसे युवाओं की एक टीम तैयार करनी चाहिए, जिसे राजनीतिक समझ होने के साथ-साथ विरोधी पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखकर जवाब देने की क्षमता हो। विरोधी पार्टी के हर हमले का जवाब दे सके। उसकी गलत नीतियों पर घेर सके और जनता को सच्चाई से रू-ब-रू करा सके। कांग्रेस ऐसी टीम में चुने हुए विद्वान और हर क्षेत्र की समझ रखने वाले युवाओं को मौदान में उतारकर हर राज्य में रैलियां आयोजित करे, सत्ताधारी दल की जन-विरोधी नीतियों पर खुले मंच पर बहस का निमंत्रण दें और लोगों को उनके हित-अहित की सही जानकारी दें। अगर कांग्रेस ऐसा करती है, तो वह दिन दूर नहीं, जब लोगों को अपने हितों की फिक्र होने लगेगी और वे जागरूक होकर सत्ताधारी सरकारों से हिसाब मांगने लगेंगे।

● इन्द्र कुमार

राम बनाम बाकी सब

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना साकार होने जा रहा है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि अन्य पार्टियां भी नरम हिंदुत्व की ओर आकृष्ट हो रही हैं। कांग्रेस का 'नरम-हिंदुत्व' की ओर आकृष्ट होना अब और भी मुखर और जाहिर हो गया है, जब इसके शीर्ष नेताओं में बाबरी मस्जिद को चुपचाप भुलाकर मंदिर बनने का स्वागत करने और राम में आस्था जताने की होड़ लगी है।



राम मंदिर के भूमिपूजन के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि राम मंदिर का मुद्दा राजनीति से गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि भाजपा अभी इसे अपना एजेंडा बताने से लगातार बच रही है, जबकि हकीकत ये है कि राम मंदिर पर सियासत रोकनी नहीं जा सकती। राम मंदिर निर्माण के साथ ही सियासत का नया अध्याय शुरू होगा, जो लंबे दौर तक असरकारक रह सकता है। ये अलग बात है कि खुद उत्तर प्रदेश में ये फिलहाल उतना प्रभाव नहीं दिखा सकेगा। वजह है कि यहां सियासत के केंद्र में जो 18 से 35 साल तक के युवा हैं, उनमें से किसी ने इसके लिए हुए आंदोलन को देखा ही नहीं है। इस आयु वर्ग का समर्थन कामकाज के आधार पर ही मिलना है। ये युवा शायद ही मंदिर मुद्दे के सियासी प्रभाव से इत्तेफाक रखते हों।

कहा तो ये भी जा रहा है कि मंदिर निर्माण का प्रभाव देश के शेष राज्यों पर भी नहीं पड़ना है। इसे एक विवादित अध्याय का सुखांत माना जा रहा है। तभी तो भाजपा इसे प्रचारित कर रही है, लेकिन सियासत से परे जाकर, इसका श्रेय लेने-देने या छिन्ने जैसे बयानों से दूरी बनाते हुए। चातुर्मास, मुहूर्त और निर्मात्रण पर हुई बयानबाजी में भी भाजपा ने प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद को मौन ही रखा। सियासत के जानकारों का एक धड़ा ऐसा भी है, जो मंदिर निर्माण के दूरगामी प्रभाव को नकारता नहीं है।

वे सवाल करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना अहम मुद्दा, जिसने भाजपा को सत्ता तक पहुंचा दिया हो, वो कैसे प्रभावहीन हो सकता है। ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है।

मंदिर निर्माण लगभग साढ़े तीन साल में पूरा होगा यानी 2023, तब तक कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे, तो कई में होने होंगे, लेकिन भाजपा मंदिर निर्माण के बजाय उन राज्यों के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी। जैसे इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विस चुनाव होने हैं, जहां भाजपा एनडीए में दूसरे नंबर पर है। जेडीयू से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो मंदिर मुद्दा शायद ही काम करे। 2021 में अप्रैल-मई में पश्चिम बंगाल में विस चुनाव होंगे, जहां भाजपा पहले से ही ममता पर कुशासन के आरोप लगाकर संघर्षरत है, ऐसे में वहां भी

मंदिर मुद्दा काम नहीं आएगा। इसी साल तमिलनाडु में चुनाव हैं, जहां राम मंदिर मुद्दा नहीं बन सकता। 2022 में कर्नाटक भी मंदिर के प्रभाव से दूर माना जा सकता है। 2023 में राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव पर राम मंदिर का कोई प्रभाव शायद ही पड़े। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, जिसमें एनडीए मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को भुनाते हुए मोदी 2.0 की सभी उपलब्धियों को सामने रखेगी। भाजपा मंदिर पर हिंदुओं के मतों के धुवीकरण के बजाय तीन तलाक जैसे मुद्दों पर मुसलमानों को आकर्षित करना चाहेगी।

राम मंदिर के लिए भूमिपूजन से ठीक पहले अचानक कई कांग्रेस नेताओं में श्रीराम को लेकर प्रेम उमड़ पड़ा है। कांग्रेस वही पार्टी है, जिसने श्रीराम के अस्तित्व को ही सुप्रीम कोर्ट में

कांग्रेस आस्था की राह पर

कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं, जिनमें शीर्ष नेतृत्व के लोग भी शामिल हैं, ने ना सिर्फ सोशल मीडिया पर भूमिपूजन के स्वागत में संदेश डाले हैं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोले जाने का श्रेय भी लिया जा रहा है। ये कदम 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2007 की अपनी गलती सुधारने के लिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समर्थन में उनके द्वारा सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित कराने जैसा ही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2007 में राम सेतु मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा था कि 'भगवान राम में वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सत्यता का अभाव है।' मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था, 'वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस निश्चय ही प्राचीन भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन उन्हें उनमें वर्णित पात्रों और घटनाओं के अस्तित्व को निर्विवाद रूप से साबित करने वाला ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं माना जा सकता है।'

नकारने के लिए ताल ठोक दी थी। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी तक राम मंदिर के पक्ष में देखे जा रहे हैं। नाथ ने तो हनुमान चालीसा का पाठ तक आयोजित कर दिया। कांग्रेस का यह दांव भाजपा को उकसा सकता है कि वह राम मंदिर की सफलता को अपना बताए। हालांकि अब तक भाजपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भाजपा यदि दावा जताती है, तो कांग्रेस जनता के बीच यह मुद्दा ले जाएगी कि मंदिर निर्माण को भाजपा ने सियासी हित के लिए हाईजैक कर लिया है। यदि भाजपा चुप रह जाती है, तो हिंदुओं को आकर्षित करने का लोभ कांग्रेस पहले से ही कर रही है। ऐसे में राम को लेकर सियासत का नया अध्याय शुरू हो सकता है।

उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत जाकर भाजपा राम मंदिर निर्माण को सियासी रंग बिल्कुल नहीं दे रही है। वह राम मंदिर को राष्ट्र की पहचान के रूप में स्थापित करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रवाद के एजेंडे को मजबूत कर रही है। संघ राष्ट्रवाद के अगले अध्याय के रूप में हिंदू राष्ट्र को लक्ष्य मानकर चल रही है। संघ भारत को एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है जहां सभी धर्मों का बराबर से सम्मान हो। ऐसे में लंबा सफर तय करने के लिए भाजपा तात्कालिक रूप से ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती, जिससे भविष्य में कोई अनचाही बाधा खड़ी हो। ज्यादातर क्षेत्रीय दल जातीय आधारित राजनीति करते रहे हैं। अब चूंकि भाजपा ने राष्ट्रवाद की राजनीति को मजबूती से स्थापित कर दिया है, तो इसमें जातिगत राजनीति के लिए जगह नहीं बचती। ऐसे में क्षेत्रीय दलों को अपनी जमीन बनाए रखने के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। जातीय समीकरणों से दूर होने पर क्षेत्रीय दलों के पास युवाओं को मौका देने और रोजगार की बात करने जैसे मुद्दों के विकल्प होंगे। उन्हें बस जरूरत इसे ईमानदारी से उठाने की होगी। यदि वह सफल हो जाते हैं, तो युवा उनसे जुड़ेंगे भी और देश में रोजगार भी मिलना आसान हो जाएगा।

अयोध्या में एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के साथ ही एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है- ये एक लंबे संघर्ष का अंत है या एक नए संघर्ष की शुरुआत? यह शानदार समारोह अपने-आप में कई तरह से अनूठा था। शिलान्यास, शुभारंभ समारोहों का चुनावी हथकंडों के रूप में प्रयोग भारतीय राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये शायद पहला अवसर है जब

अदालती लड़ाई के जरिए एक सदियों पुराने विवाद का अंत हुआ है। भूमिपूजन समारोह के दो प्रमुख प्रतिभागी थे प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत। ये स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा जन आकांक्षाओं को समझते हुए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें हिंदुओं की जनभावना की बेहतर समझ है। अयोध्या फैसले में हिंदुओं के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं जुड़ी है- जैसे पूजा, धर्म या पहचान से जुड़े अन्य पवित्र स्थलों पर दावेदारी छोड़ने की अनिवार्यता। काशी और मथुरा के प्राचीन मंदिरों की यात्रा करने वाले भक्तों को मुगल शासन के दौरान मंदिर के ढांचे का हिस्सा बनी मस्जिद की



गैर एनडीए सरकारों को सबक

मोदी सरकार ने जिस तरह सरदार पटेल की विश्वविख्यात मूर्ति स्थापित की, राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर विकसित करने के अलावा अन्य प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों के व्यापक स्वरूप के लिए रोडमैप तैयार हो रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में भाजपा इन्हें अपने विकास के प्रतिमान के रूप में बताएगी। ऐसी कोशिश मायावती ने उप्र में बसपा सरकार के दौरान अंबेडकर पार्क विकसित करके की थी, लेकिन उसका लाभ उन वर्गों को नहीं मिला जिनके प्रतिनिधित्व का वह दावा करती रही हैं। यह पार्क पर्यटन को आकर्षित न कर सके। ऐसे में देश के जिन राज्यों में गैर एनडीए सरकारें हैं, उन्हें भी अभी से जवाब तैयार करने के लिए कुछ प्रतिमान स्थापित करने ही होंगे, वह भी बीएसपी से सबक लेकर यानी उन्हें ऐसे निर्माण कराने होंगे, जो किसी वर्ग को खुश करने के अलावा कम से कम पर्यटन को तो जरूर बढ़ावा दें। ऐसा न करके गैर एनडीए दल भविष्य में भाजपा के सामने टिक पाने में सक्षम नहीं रह जाएंगे।

उपस्थिति का सामना करना पड़ता है। हिंदुओं के प्राचीन पवित्र स्थलों के साथ इन मस्जिदों की मौजूदगी न सिर्फ 'राजनीतिक हिंदुओं' बल्कि उन धार्मिक हिंदुओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है जिनका कि राजनीति से दूर-दूर का नाता नहीं है।

काशी और मथुरा के मंदिरों के पुनरोद्धार, वहां अतिक्रमण हटाए जाने और इन स्थलों को हिंदुओं के लिए अधिक सुलभ बनाए जाने, ताकि उन्हें बुतपरस्ती के विरोधियों के साथ इन्हें साझा नहीं करना पड़े की मांग बहुत पुरानी है। अयोध्या पर अदालती फैसले और केंद्र एवं राज्य में मजबूत सरकारों की मौजूदगी ने इस संबंध में पहले से ही मुखर हिंदुओं की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। अयोध्या में बिना किसी अड़चन के शिलान्यास समारोह संपन्न होने के साथ ही, हिंदुओं के लिए अहम तीन स्थलों पर दावेदारी के भाजपा और आरएसएस की मूल एजेंडे का एक तिहाई हिस्सा पूरा हो गया है। काशी और मथुरा की 'मुक्ति' के लिए शायद किसी आंदोलन की भी आवश्यकता नहीं पड़े।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के अलावा भाजपा की प्रतिबद्धता समान नागरिक संहिता लागू करने की भी है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के गौरव की पुनर्बहाली ही नहीं बल्कि अनुच्छेद-370 या समान नागरिक संहिता जैसे गैर-धार्मिक मुद्दे भी अन्य दलों के बिल्कुल राजनीतिक रवैए के कारण बुरी तरह विवादित हो गए हैं, जो कि इन विषयों को हिंदू बनाम मुस्लिम के नजरिए से देखते हैं। मोदी के नेतृत्व में भाजपा की राजनीतिक पकड़ मजबूत होने और कई राज्यों में पार्टी का प्रभाव बढ़ने के साथ ही हिंदू एकजुटता उत्तरोत्तर प्रबल होती जा रही है। इसलिए, भाजपा-आरएसएस का एजेंडा अब बहुत कम समय में आसानी से पूरा होने लायक दिखता है।

दरअसल, भाजपा ऐसे विकल्पों को तैयार करती है जिसे चुनावी तमाम मतदाताओं के लिए आसान नजर आता है। आखिरकार कौन पाकिस्तान का समर्थन करता है? या 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' किसे पसंद आएगा? कौन नामदारों का समर्थन कर सकता है? और अब कौन-सा पक्का हिंदू या इस वातावरण में रहने वाला- राम के खिलाफ जा सकता है? बहरहाल, तब तक मंदिर बन पाए या नहीं, राम ने 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा का स्टार प्रचारक बनने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया है।

● दिल्ली से रेणु आगाल

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सलियों की घर वापसी 'लोन वर्गटू' अभियान के तहत 26 जून से अब तक 71 माओवादियों ने सरेंडर किया है जिसमें कई ईनामी भी हैं। लगातार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की बढ़ती संख्या के बीच माओवादी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस जिनको सरेंडर करने वाले नक्सली बता रही है वे सभी आम नागरिक हैं। यही नहीं अपने आपको सही साबित करने के लिए माओवादियों ने पुलिस से मांग की है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा विधायक भीमा मंडावी के मौत के मुख्य आरोपी आत्मसमर्पित माओवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो।

नक्सलियों की घर वापसी



भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के दरभा डिविजनल कमेट्री (डीवीसी) ने गत दिनों एक पर्चा जारी कर राज्य पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस जिन लोगों को सरेंडर करने वाले माओवादी बता रही है वे आम ग्रामीण हैं। माओवादियों का आरोप है कि पुलिस ने पहले इन्हें गिरफ्तार किया और अब इनको ही सरेंडर करने वाले माओवादी बता रही है। कमेट्री के सचिव साईनाथ द्वारा जारी इस पर्चे में लिखा है, 'आम जनता को नक्सली के नाम से अरेस्ट करके जबरन सरेंडर करवाया जा रहा है। सरेंडर का एक धंधा है। पैसा कमाने के लिए एसपी सरेंडर पॉलिसी को दिखा रहे हैं।' यही नहीं माओवादियों ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस अपने लिए मुखबिरी का एक तंत्र तैयार करने के उद्देश्य से ग्रामीणों को सुविधा के नाम पर मोबाइल फोन भी दे रही है।

माओवादियों के पर्चे में लिखा है, 'दंतेवाड़ा एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव और स्थानीय पुलिस आम जनता, पढ़ाई करने वाले बच्चों, गुरुजियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिन को मोबाइल बांट रहे हैं। इसके साथ ही फोन नंबर के लिए सिम भी दे रहे हैं।' ऐसा करके वे आम लोगों को लालच दिखाकर 'सुकली-नेटवर्क' (मुखबिरी का तंत्र) तैयार करने का काम कर रहे हैं। वे ग्रामीणों को उनकी अपनी ही उंगलियों से स्वयं की आंखे फोड़वाने के लिए यह काम सौंप रहे हैं।' डीवीसी सचिव ने कहा- '9 अप्रैल 2019 को भीमा मंडावी को बम विस्फोट कर उड़ा दिया गया था। ये विस्फोट माओवादियों ने ही कराया था लेकिन इसका मुख्य जिम्मेदार गद्दार बादल है। इसको तुरंत सजा देनी चाहिए।' पर्चे पर लिखी बातों पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि माओवादी जिस बादल को गद्दार कह रहे हैं उसने अपनी पत्नी के साथ पिछले साल आत्मसमर्पण किया था।

माओवादियों ने दी सफाई

माओवादियों ने दंतेवाड़ा के पोटाळी गांव में 22 जुलाई को गला रेतकर दो ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। इस घटना पर पुलिस ने बताया था कि मरने वाले दोनों ग्रामीण नक्सली कमांडर देवा के साथी माओवादी मिलिशिया के सदस्य भी थे। कमेट्री ने पर्चे में पुलिस के दावे का खंडन करते हुए कहा- 'डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि सड़क काटने से इन लोग ने विरोध किया इसलिए इनकी हत्या की गई। ये लोग मिलिशिया में नहीं थे लेकिन दुश्मन के मुखबिर थे। एसपी ने इस घटना को तुम्हारे साथी को तुमने ही मारा बताया है। ये सरासर झूठ है। दोनों पुलिस के मुखबिर थे।' माओवादियों के अनुसार पोटाळी दुर्वापारा निवासी वेदटी भीमा और मंडावी भीमा को पीएलजीए ने मारा था। पर्चे के में साईनाथ के कहा, 'पुलिस द्वारा किए जा रहे सर्चिंग अभियानों में ये दोनों आगे रहते थे और स्थानीय निर्माणों को पकड़वाने के लिए हमेशा जांच करते थे। नक्सलियों का कहना है कि दोनों ग्रामीण उनकी उपस्थिति के बारे में दिन-रात थानेदार को खबर देते थे और अपनी मुखबिरी के जाल में गांव के बाकी युवकों को भी फंसाने की कोशिश करते रहे।'

बादल ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहन से भी सरेंडर करने का आग्रह किया है। ज्ञात हो कि भाजपा विधायक की मौत की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। पुलिस का कहना है कि जांच एजेंसी द्वारा 6 आरोपियों को बादल के खुलासे पर ही गिरफ्तार किया गया था। ये सभी आरोपी नक्सलियों के सप्लायर्स थे।

माओवादियों के आरोप पर दंतेवाड़ा के एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने कहा- 'माओवादियों का यह पर्चा उनकी बौखलाहट का नतीजा है। पुलिस द्वारा हाल ही में उनके कई सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया है जिससे उनको रसद और विस्फोटक बनाने के सामानों की पूर्ति नहीं हो रही है। माओवादी अपने सप्लायर्स को बचाना चाहते हैं।' बादल के संबंध में पल्लव का कहना है- 'इसमें कोई शक नहीं है कि वह मुख्य आरोपी है लेकिन सरेंडर पॉलिसी ऐसी है कि आत्मसमर्पण करने वाले के खिलाफ केस वापस हो जाता है।' माओवादियों द्वारा पुलिस के खिलाफ आम नागरिकों को गिरफ्तार करने के आरोप पर पल्लव कहते हैं- 'सरेंडर करने वाले सभी माओवादी हैं। नक्सली अपने फ्रंटल घटकों के सदस्यों को भी आम नागरिक ही बताते हैं। ऐसा बोलकर वे आम जनता को गुमराह करते हैं।'

पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सलियों की घर वापसी 'लोन वर्गटू' अभियान के तहत 26 जून से अब तक 71 माओवादियों ने सरेंडर किया है जिसमें कई ईनामी भी हैं।' पुलिस का कहना है इससे पहले माओवादियों ने जो पर्चे जारी किए उनमें पुलिस पर लोगों पर अत्याचार करने, महिलाओं के साथ बलात्कार करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिन, बच्चों और ग्रामीणों को मारने के आरोप लगाते थे। लेकिन इस पर्चे में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है।

पल्लव आगे कहते हैं- 'इसका सकारात्मक पक्ष है। इससे साबित हो रहा है कि माओवादियों को सुरक्षाबलों के खिलाफ मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। वे कह रहे हैं पुलिस ग्रामीणों को मोबाइल फोन और सिमकार्ड मुहैया करा रही है। नक्सलियों ने माना है कि उनके विकास कार्यों को रोकने की साजिश का साथ नहीं देने पर अपने ही साथियों को मार दिया। अब अपने कृत्यों पर ग्रामीणों को सफाई दे रहे हैं। उन्होंने सरेंडर किए हुए माओवादियों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने के लिए बोलना शुरू कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि ग्रामीणों के बीच उनकी पकड़ कम हो रही है।'

● राघपुर से टीपी सिंह

45 दिन का लोकतंत्र बचाओ अभियान हुआ 45 मिनट में समाप्त, इतने दिनों तक जनता और लोकतंत्र खुद बना रहा तमाशबीन, क्या गहलोट क्या पायलट, वसुंधरा, भाजपा और क्या पूनिया राठौड़ सबने ताकत झोंक दी लोकतंत्र को बचाने में, आखिरकार राजस्थान में लोकतंत्र बच ही गया। इस लोकतंत्र को बचाने में कई लोग दिन रात जुटे रहे। लोकतंत्र किसी एक की नहीं बल्कि सबकी मेहनत से बचा है। लोकतंत्र तो बचना ही था, सो बच गया। अच्छा हुआ कि विधानसभा के बाहर ही बच गया, अंदर नहीं बचता। कई बार तो राजनेताओं के मुंह से लोकतंत्र के लिए निकली बातें बेमानी सी लगती हैं। ऐसा लगता है कि किसी को लोकतंत्र की चिंता नहीं लेकिन अपने को लगना भी कोई लगना है, गलत साबित हो गया। आखिरकार नेताओं ने ही अपना राजनीति कौशल दिखाते हुए लोकतंत्र को बचा लिया।

कभी-कभी लगता था कि अन्ना हजारे की कही हुई एक बात सारे नेताओं की बातों पर भारी है। अन्ना हजारे कहते हैं कि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता ही राजनीति का उद्देश्य हो गया है। लेकिन यह भी गलत ही साबित हो गया। भले ही विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में मुकदमें दर्ज हुए, भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोट ने होर्स ट्रेडिंग की रेट 15 से 35 करोड़ बताई हो लेकिन अब लोकतंत्र के बचने के बाद यह सारी बात गौण हो जाती है। यह भी लगता था कि राजनीति में नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन गलत फहमी ही दूर हो गई। अब नई बात समझ में आने लगी है कि राजनीति ही नैतिकता को तय करने लग गई है। नैतिकता क्या होगी, कब होगी, किन स्थितियों में उसे कैसे समझा जाएगा। यह सब राजनीति ने तय करना शुरू कर दिया है। इसलिए राजनीति के अनैतिक होने की बात स्वतः ही खारिज हो जाती है।

राजस्थान में सियासत के नाम पर जो खेल चला, या दूसरे शब्दों में नंगा नाच चला, वो बात भी गलत ही साबित हुई। असल में वो तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ईमानदार प्रयास था। जरा सोचिए किसके लिए चला? इसका जवाब



बच ही गया लोकतंत्र

है, सिर्फ और सिर्फ भोली, नासमझ और कमजोर जनता के हितों की रक्षा के लिए। लोकतंत्र बचाने के इस महा समर में पांच खेमे साफ-साफ नजर आए। खास बात यह है कि यह सारे खेमे बिना किसी स्वार्थ के लिए लोकतंत्र की रक्षा करने में दिन रात लगे रहे। लोकतंत्र को बचाने के लिए इन नेताओं के प्रयासों की तुलना आपदा के समय सेना के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से नहीं की जानी चाहिए। यह कहना भी सही नहीं होगा कि इन नेताओं में सेवा का वैसा संकल्प कहीं नजर नहीं आता, जैसा बर्फ में बंदूक लिए कई दिनों तक देश की सीमा पर खड़े सैनिक के संकल्प और जज्बे में होता है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन नेताओं ने क्या-क्या नहीं किया। जब-जब भी लोकतंत्र खतरे में आता है तो नजारा ही कुछ और होता है।

लोकतंत्र को बचाने की स्क्रिप्ट में फाइव स्टार होटल, गीत-गजल, चार्टर प्लेन और सांठ-गांठ, जनता की चुनी सरकार को गिराने की योजना, योजना को पूरा करने के लिए धन-बल का इस्तेमाल और ना जाने क्या-क्या होता है। लेकिन राजस्थान में बचाए गए लोकतंत्र में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्योंकि सबने अपने-अपने फाइव स्टार होटलों में रहने के बिल भरे हैं। लोकतंत्र को बचाने और संविधान की

मर्यादाओं की पूरी पालना में राज्यपाल और स्पीकर भी नजर आए। सरकार भी दिन-रात कभी होटल से, तो कभी सीएमआर तो कभी सचिवालय से लोकतंत्र को मजबूत बनाने और बचाने में दिन-रात जुटी रही।

लोकतंत्र को मजबूत करने का पहला जिम्मा सचिन पायलट ने अपने कंधों पर उठाया। अभिव्यक्ति की अजादी के नाम पर 18 कांग्रेस विधायकों के साथ मानेसर जाकर बैठ गए। गए तो ऐसे कि जब तक लोकतंत्र बच नहीं गया तब तक नजर ही नहीं आए। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए पायलट ने उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद को भी दांव पर लगा दिया। आज लोकतंत्र नहीं बचता तो दो दिन बाद पायलट और उसके खेमे के 18 विधायकों की विधायकी भी जा सकती थी और 6 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित हो सकते थे। लेकिन शुक्र है भगवान का ऐसा होने से पहले लोकतंत्र बच गया। लोकतंत्र को बचाने का दूसरा जिम्मा, भाजपा ने उठाया। भाजपा पिछले कुछ समय में कई राज्यों में लोकतंत्र को बचाकर दिखा चुकी है। पायलट खेमे की गणित पूरी होती तो लोकतंत्र बचाओ अभियान की फिल्म ही कुछ और होती। लेकिन इस बार भाजपा को पूरा मौका नहीं मिला।

● जयपुर से आर.के. विन्नानी



स्वतंत्रता दिवस



की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, नीमच

सचिव • भार साधक अधिकारी



स्वतंत्रता दिवस



की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, जावरा, जिला-रतलाम

सचिव • भार साधक अधिकारी

26 जुलाई को यानी अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए। शिवसेना के

आत्मविश्वास या डर?



मुखपत्र 'सामना' को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा- 'जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी हो वो आज ही गिराए, अभी इसी दौरान ही गिराए फिर मैं देखता हूं।' जानकारों ने उनके इस बयान को भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौती के तौर पर देखा। अपने इस साक्षात्कार में ठाकरे ने यह भी कहा कि 'मेरी सरकार का भविष्य विपक्ष के हाथों में नहीं। मेरी सरकार गरीबों का तीन पहिए का रिक्शा है, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, लेकिन पीछे दो और लोग बैठे हैं। गठबंधन में हमारे सहयोगी एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) और कांग्रेस 'सकारात्मक' हैं और महाविकास अघाड़ी सरकार को उनके अनुभव का फायदा मिल रहा है। अगर मेरी सरकार तीन पहिए वाली है, ये सही दिशा में आगे बढ़ रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है?'

मुख्यमंत्री ठाकरे का यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बड़े संकट से जूझ रही है। जबकि कर्नाटक और मध्यप्रदेश की सत्ता पहले ही कांग्रेस के हाथ से फिसल चुकी है। गुजरात में भी बीते कुछ सप्ताह में कांग्रेस के पांच विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है जबकि तीन अन्य विधायक पहले ही पार्टी की सदस्यता छोड़ चुके हैं। ऐसे में ठाकरे के बयान के बाद राजनैतिक गलियारों में इस सवाल की गूंज सुनाई देने लगी है कि क्या महाराष्ट्र में भी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के महागठबंधन वाली सरकार पर कोई खतरा मंडरा रहा है? अधिकतर जानकार इस सवाल का जवाब 'हां' में देते हैं। उनका मानना है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के आपसी मनमुटाव के चलते महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर तभी

से तलवार लटक रही है जब से वह अस्तित्व में आई है। इसकी बानगी के तौर पर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लिया जा सकता है। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे ने बीते साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन तब उनके साथ तीनों दलों से केवल दो-दो विधायकों ने ही मंत्री पद ग्रहण किया था। बाकी मंत्रियों का चयन करीब तीन सप्ताह बाद ही किया जा सका था। उस समय महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों पहियों यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर गहमागहमी की खबरें सूबे में आम थीं। इसके मद्देनजर कयास लगाए जाने लगे कि जो गठबंधन शुरुआती दिनों में ही बड़ी खींचतान में उलझ गया हो उसके लिए अपना कार्यकाल पूरा कर पाना आसान काम नहीं होगा!

महाराष्ट्र में बीते 6 महीने में ऐसी कई राजनीतिक घटनाएं देखने को मिली हैं जो इन कयासों को बल देती हैं। गौरतलब है कि गठबंधन सरकार बनने के तुरंत बाद से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि मुख्यमंत्री पद पर उद्धव ठाकरे बैठे जरूर हैं, लेकिन सरकार की कमान पूरी तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हाथ में है। चर्चाएं कुछ ऐसी भी हैं कि मुख्यमंत्री ठाकरे अपने निवास (मातोश्री) से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते जबकि उम्रदराज होने के बावजूद शरद पवार जमीन पर कहीं ज्यादा सक्रिय रहते हैं। जाहिर तौर पर ये बातें शिवसैनिकों को कम ही सुहाती हैं।

जानकारों की मानें तो इन चर्चाओं की शुरुआत भी एनसीपी नेताओं की तरफ से हुई और इन्हें हवा देने का काम भी उन्होंने किया। हालांकि कुछ का दावा है कि ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उछाली गई हैं ताकि गठबंधन में दरार डाली जा सके।

जानकारी के अनुसार इस सबके जवाब में कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री ठाकरे ने एक पीआर एजेंसी से संपर्क साधा और उसे अच्छा-खासा भुगतान कर अपनी छवि सुधारने का काम सौंपा। इसमें कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता रह चुकी प्रियंका चतुर्वेदी की बड़ी भूमिका बताई जाती है। वे बीते साल ही शिवसेना में शामिल हुई थीं। इसके बाद से उद्धव ठाकरे चमत्कारी ढंग से एक प्रभावशाली मुख्यमंत्री के तौर पर उभरते दिखे हैं। कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र में पैदा हुए तमाम विपरीत हालात के बावजूद एक आम बैंकर से लेकर फिल्मी सितारे तक सभी एक स्वर में इस बीमारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ठाकरे की तारीफ करने लगे। लिहाजा इस बार कुढ़ने की बारी एनसीपी की थी। जानकार बताते हैं कि मुंबई जैसे महाराष्ट्र के शहरी इलाकों पर जितना शिवसेना का कब्जा है, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उतना ही प्रभाव एनसीपी का माना जाता है। दोनों ही दलों की राजनीति का भी तौर-तरीका कुछ-कुछ एक ही सा रहा है। नतीजतन दोनों ही दलों के बीच प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा की भावना भी बराबर ही महसूस की जा सकती है।

● बिन्दु माथुर



स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, खातेगांव, जिला-देवास

सचिव ● भार साधक अधिकारी



स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, रतलाम

सचिव ● भार साधक अधिकारी

उत्तर प्रदेश में इन दिनों हर राजनीतिक दल को ब्राह्मणों की चिंता खूब सता रही है। खासतौर से विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस आए दिन ब्राह्मणों को लेकर कई तरह के वादे करते दिख रहे हैं तो वहीं सत्तादल भाजपा भी अपने इस कोर वोट बैंक को खोना नहीं चाहती। ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक उग्र में एक नए 'हॉट

केक' की तरह हो गया है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के तीन अहम ब्राह्मण नेता - अभिषेक मिश्र, मनोज पांडे व माता प्रसाद पांडे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही अभिषेक मिश्र की ओर से लखनऊ में 108 फीट की परशुराम की प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद

ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर वह 2022 में सत्ता में आएंगी तो परशुराम की इससे भी ऊंची प्रतिमा लगाएंगी।

इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता मायावती के खिलाफ मुखर हो गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्र ने कहा- 'बहन जी चार बार उग्र की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तब उन्होंने परशुरामजी की मूर्ति क्यों नहीं लगाई। परशुरामजी की जयंती पर छुट्टी की घोषणा सपा सरकार में ही हुई थी जिसे भाजपा सरकार ने बाद में कैंसिल कर दिया।' वहीं समाजवादी पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता पवन पांडे ने कहा- 'तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार' का नारा देने वाली पार्टी की बहनजी को आज ब्राह्मणों की याद आ रही है, वो ब्राह्मणों के सम्मान की बात कर रही हैं, लेकिन परशुराम के वंशजों ने मन बना लिया है कि अब कृष्ण के वंशजों के साथ रहेंगे। कांग्रेस ने तो इस मुद्दे पर सपा-बसपा दोनों को घेरा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद कहते हैं कि सबसे उन्होंने 'ब्राह्मण चेतना संवाद' की घोषणा की है उसके बाद से ही सपा-बसपा को ब्राह्मणों की चिंता सताने लगी है। इससे पहले जब ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार हो रहे थे तब दोनों दल चुप थे। जितिन के मुताबिक, 'प्रतिमा लगाने से बेहतर ब्राह्मणों के असल मुद्दों की लड़ाई लड़ना है। इस सरकार में ब्राह्मणों पर खूब अत्याचार हुआ है। आए दिन हत्याओं की सूचनाएं आती हैं। ऐसे में समाज को एकजुट करने का समय है।'

कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र के माध्यम से परशुराम जयंती पर रद्द अवकाश को फिर से बहाल करने की मांग की है। अपने पत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने लिखा है, 'भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार कहे जाते हैं। इसी कारण वह ब्राह्मण सामज की आस्था का प्रतीक हैं। प्रदेश में भगवान परशुराम जयंती का अवकाश रद्द होने से ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश है।' वहीं कांग्रेस के ही पूर्व सांसद राजेश मिश्रा भी लगातार ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए पीड़ित ब्राह्मण परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी तरह लखनऊ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम, उग्र कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट अंशू अवस्थी मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को धार दिए हुए हैं। उग्र में विपक्षी दलों का ब्राह्मणों के समर्थन में उतरने की अहम वजह ब्राह्मणों की सरकार से नाराजगी है। उग्र में पिछले तीन साल में जितने भी बड़े हत्याकांड हुए वे ब्राह्मण समाज से आने

परशुराम पर राजनीति



वाले लोगों के ही हैं। बीते दिनों कुख्यात अपराधी विकास दुबे और फिर मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर राकेश पांडे के एनकाउंटर ने आग में घी का काम किया है। दोनों ही एनकाउंटर्स के तरीकों पर सवाल उठे जिससे उग्र पुलिस घिरती दिखी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्रनाथ त्रिपाठी का कहना है कि उग्र में बीते दो

साल में 500 से अधिक ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। उनके मुताबिक, उग्र की भाजपा सरकार ब्राह्मण विरोधी है। खासतौर से वह मुख्यमंत्री योगी पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि इस सरकार में ब्राह्मणों का दमन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

उग्र की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। आबादी के

लिहाज से सूबे में लगभग 12 प्रतिशत ब्राह्मण हैं। कई विधानसभा सीटों पर तो ब्राह्मण 20 फीसदी से भी अधिक हैं। ऐसे में हर पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर टिकी है क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मण नाराज हैं उनके भाजपा से छिटकने की संभावनाएं काफी अधिक हैं। उग्र के राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है 2017 में भाजपा को ब्राह्मणों का जमकर वोट मिला लेकिन सरकार में उतनी हक नहीं दिखी। 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 8 ब्राह्मणों को जगह दी गई, लेकिन दिनेश शर्मा व श्रीकांत शर्मा को छोड़ किसी को अहम विभाग नहीं दिए गए। वहीं श्रीकांत शर्मा के बारे में कहा जाता है कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व की ओर से दिल्ली से उग्र भेजा गया है। वहीं 8 क्षत्रियों को भी मंत्री बनाया गया उनके विभाग ब्राह्मणों से बेहतर दिए गए।

2007 में जब मायावती के नेतृत्व में बीएसपी ने ब्राह्मण+दलित+मुस्लिम समीकरण पर चुनाव लड़ा तो उनकी सरकार बन गई। बसपा ने इस चुनाव में 86 टिकट ब्राह्मणों को दिए थे। हालांकि बाद में ब्राह्मण छिटककर भाजपा की ओर आ गए लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हर दल इसी तरह के समीकरण बनाने की तैयारी कर रहा है। सपा की नजर यादव+कुर्मी+मुस्लिम+ब्राह्मण समीकरण पर है तो कांग्रेस ब्राह्मण+दलित+मुस्लिम व ओबीसी का वो तबका जो भाजपा, सपा के साथ नहीं उसे अपनी ओर खींचने में जुटा है।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, मंदसौर

सचिव
भार साथक अधिकारी

पि छले 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहारी राजनीति का केंद्र बने सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। 2015 के समय के चुनावी समीकरण अब पूरी तरह पलट चुके हैं। 2015 में लालू प्रसाद यादव की राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार को इस बार उसके खिलाफ चुनावी मैदान में दो-दो हाथ करने हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा को छोड़कर बाकी सब किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार की छवि पर राजनीतिक हमला करने में जुटे हैं। जहां एक ओर नीतीश जनता के बीच अपनी सरकार के कामों को गिनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं सारे विपक्षी उन्हें जन विरोधी सरकार के मुखिया के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

लोजपा के चिराग पासवान अपने नए समीकरण के साथ चुनावी मैदान में जाने को इच्छुक नजर आ रहे हैं, तो औवेसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सभी मुस्लिम बहुल्य सीटों पर बिसात बिछा दी है। 2014 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित करने वाले तेजस्वी यादव अब सुशासन बाबू को मुख्यमंत्री पद पर भी नहीं देखना चाहते हैं। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार अनुभवी राजनीतिक योद्धा के रूप में मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। लालू यादव के बाद केवल नीतीश कुमार ही ऐसा नाम हैं जो बिहार की राजनीति में सबसे अनुभवी हैं।

जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार ने 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा था और 1985 में बिहार विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे। इसके बाद नीतीश साल दर साल आगे बढ़ते चले गए। 1987 में बिहार लोक दल युवा के अध्यक्ष बने और 1989 में जनता दल बिहार के महासचिव पद पर पहुंचे। अगले ही साल लोकसभा सांसद बने। 1990 में पहली बार केंद्रीय राज्यमंत्री बने और 1991 में जनता दल से संसद में उपनेता बने। 2004 तक 6 बार सांसद रहे। इस दौरान वो भारत सरकार



‘सुशासन बाबू’ का जलवा

की कई कमेटियों के प्रमुख और विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे। नीतीश भारत के रेल मंत्री के रूप में कई कारणों से चर्चा में रहे। उन्होंने टिकट विंडो को डिजिटलाइज कराया, साथ ही रेलवे के कार्यों को कम्प्यूटरीकृत कराने में नीतीश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 3 मार्च, 2000 को नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने लेकिन केवल 7 दिन ही इस पद पर रह सके। भले ही यह 7 दिनों का समय रहा लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रस्तावना तैयार हो गई। 2005 के बाद से अब तक नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान 2014 में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनवाया लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते 2015 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। मांझी अब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश के खिलाफ राजनीतिक अभियान चला रहे हैं।

साल 2000 में केवल 7 दिन मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नीतीश कुमार 2001 में प्रधानमंत्री अटल

बिहारी वाजपेई के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बने। इसके बाद 2005 और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को हराकर मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। 2015 में नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच नीतीश ने राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और फिर से मुख्यमंत्री बने। 2017 में सीबीआई की ओर से तेजस्वी यादव के खिलाफ की गई एफआईआर के बाद दोनों के बीच रिश्तों में खटास आ गई। उस समय तेजस्वी यादव बिहार के उपमुख्यमंत्री थे। रिश्तों में आई खटास के कारण गठबंधन टूट गया। उस समय नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ लेकर नया समीकरण बनाया और मुख्यमंत्री बने रहे। इस तरह नीतीश कुमार अपने लंबे राजनीतिक अनुभवों का लाभ लेकर हर बार अपने पक्ष में समीकरण बनाने में सफल रहे। लेकिन इस बार भाजपा को छोड़कर बिहार के सभी प्रमुख राजनीतिक दल उनकी घेराबंदी में जुटे हैं। देखना होगा कि आने वाले विधानसभा में नीतीश कुमार अपनी रणनीति से ऐसा कौन-सा चमत्कार करते हैं कि वो फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज हो सकें।

● विनोद बक्सरी

15 स्वतंत्रता दिवस
अगस्त
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, बड़नगर, जिला-उज्जैन

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, महिदपुर, जिला-उज्जैन

सचिव ● भार साधक अधिकारी

श्रीलंका पीपुल्स पार्टी (एसएलपीपी) के 74 वर्षीय नेता महिंदा राजपक्षे चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। एसएलपीपी ने 5 अगस्त को हुए संसदीय चुनाव में दो तिहाई बहुमत से जीत दर्ज की। एसएलपीपी को देश की कुल 225 सीटों में से 145 पर जीत हासिल हुई, जबकि उसके नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 150 सीटें मिली हैं। श्रीलंका में बीते साल हुए ईस्टर बम धमाकों के बाद वहां के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, इसमें सिंहली समुदाय ने मुस्लिम समुदाय को काफी निशाना बनाया था। जानकारों की मानें तो बीते नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब यहां के संसदीय चुनाव में भी सिंहली और तमिल-मुस्लिम समुदायों के बीच राजनीतिक धुवीकरण साफ दिखा है। इसका फायदा सीधे तौर पर सिंहली समुदाय से आने वाले महिंदा राजपक्षे और उनके छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे को मिला है। श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके गोटबाया राजपक्षे इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 2019 में अपना पद संभालते ही महिंदा राजपक्षे को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था।

श्रीलंका में 70 फीसदी सिंहली-बौद्ध आबादी है, चुनाव नतीजों को देखें तो सिंहली बहुल क्षेत्रों में राजपक्षे की पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीते हैं। खुद महिंदा राजपक्षे ने वोटों के मामले में नया इतिहास रचा है। उन्हें पांच लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। श्रीलंका के इतिहास में इतने वोट किसी नेता को इससे पहले नहीं मिले। विदेश मामलों के ज्यादातर विशेषज्ञ महिंदा राजपक्षे का सत्ता में आना, भारत के लिए बड़े झटके जैसा बताते हैं। इसकी वजह राजपक्षे परिवार का चीन के करीब होना है। महिंदा

श्रीलंका से बढ़ेंगे खतरे



राजपक्षे ने ही पहली बार चीनी निवेश को श्रीलंका में हरी झंडी दिखाई थी। चीन से भारी भरकम कर्ज के बदले उन्होंने श्रीलंका में उसे अपने मन मुताबिक प्रोजेक्ट चुनने और निवेश करने की खुली छूट दे दी थी। इसी कर्ज के दबाव में कुछ साल बाद श्रीलंकाई सरकार को अपना बेहद महत्वपूर्ण हंबनटोटा बंदरगाह चीनी सरकार को 100 साल की लीज पर देना पड़ा था। गोटबाया राजपक्षे देश के रक्षा सचिव की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। बतौर रक्षा सचिव उन्होंने चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियां श्रीलंका के समुद्री तटों के पास लंबे समय तक रुकने की इजाजत दी थी।

पूर्व राजनयिक राजीव भाटिया भारत सरकार को श्रीलंका के मामले में बहुत सोच-समझकर

कदम बढ़ाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं- 'अब ये बात सबको स्पष्ट हो गई है कि श्रीलंका के पास एक बहुत स्थाई सरकार है। राजपक्षे बंधु वहां फिर से सबसे शक्तिशाली बन गए हैं और वो चीन समर्थक के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन उन्हें अब भारत के साथ भी डील करनी पड़ेगी। भारत को अब अपने रिश्तों को अच्छे से संभालना होगा क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारे मतभेद भी हैं और झुकाव भी है। हमें इस खेल में दिखने की जरूरत है।' विदेश मामलों के जानकार ऐसी भी कुछ वजहें बताते हैं जिनके चलते श्रीलंका के नवनियुक्त प्रधानमंत्री और उनके भाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के चीन के करीब रहने की संभावना काफी ज्यादा नजर आती है।

● ऋतेन्द्र माथुर

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, बैतूल

सचिव • भारत सायक अधिकारी

15 स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, इटारसी, जिला-होशंगाबाद

सचिव • भारत सायक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, टिमरनी, जिला-हरदा

सचिव • भारत सायक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, हरदा

सचिव • भारत सायक अधिकारी

15 स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, पिपरिया, जिला-होशंगाबाद

सचिव • भारत सायक अधिकारी

15 स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, बानापुरा, जिला-होशंगाबाद

सचिव • भारत सायक अधिकारी

लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ चीनी घुसपैठ से चिंतित भारत कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र के बीच सालभर की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 6.5 किलोमीटर लंबी जेड-मोड़ सुरंग के निर्माण में तेजी ला रहा है। सभी महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा जून, 2021 तक बढ़ा दी गई है। सुरंग के कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बीबीआर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) की 22 जुलाई को हुई एक बैठक में साझा की गई थी। इसके साथ ही करीब 13 किलोमीटर की जोजिला सुरंग को पूरा करने के लिए भी सरकार काम कर रही है।

जेड-मोड़ सुरंग परियोजना में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग, 6 किलोमीटर की संपर्क सड़क, दो प्रमुख पुल और एक छोटा पुल शामिल हैं। इस परियोजना की लागत 2,379 करोड़ रुपए है। परियोजना में एकीकृत पैकेज के रूप में 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग, जेड-मोड़ और जोजिला सुरंग के बीच में 18 किलोमीटर की संपर्क सड़क के अलावा कैरिज-वे, दो स्नो गैलरीज, चार



शांति चीन की बाड़बंदी

प्रमुख पुल और 18 हिमस्खलन-सुरक्षा बांध शामिल हैं। करीब 4,430 करोड़ रुपए की लागत वाली इस पूरी परियोजना के जून, 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। जैसे तो जेड-मोड़ सुरंग पर काम कई साल से चल रहा था, लेकिन यह सितंबर, 2018 में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी

आईएल एंड एफएस के टूटने के बाद अचानक बंद हो गया, जिसने इसे वित्तपोषित किया था। आईएल एंड एफएस ने श्रीनगर-सोनमर्ग सुरंग मार्ग के साथ रणनीतिक परियोजना को सबसे कम बोली के माध्यम से जीता था।

● कुमार विनोद

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, भोपाल

सचिव • भार साधक अधिकारी

15 स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, विदिशा

सचिव • भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, सीहोर

सचिव • भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, गंजबासौदा, जिला विदिशा

सचिव • भार साधक अधिकारी

15 स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, आष्टा, जिला-सीहोर

सचिव • भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, मनासा, जिला-नीमच

सचिव • भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, शुजालपुर, जिला-शाजापुर

सचिव • भार साधक अधिकारी

15 स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, आगर, जिला शाजापुर

सचिव • भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, तराना, जिला-उज्जैन

सचिव • भार साधक अधिकारी

जमीन, मिट्टी का केवल एक कतरा भर नहीं बल्कि महिला समाज के अपने पहचान, सम्मान और गौरव का पैमाना भी है। महिला समाज को उनके भूमि, संपत्ति के अधिकार से वंचित रखना वास्तव में उस आधी आबादी अथवा आधी दुनिया की अवमानना है- जो एक मां, बहन और पत्नी अथवा महिला किसान के रूप में दो गज जमीन और मुट्ठीभर संपत्ति की वाजिब हकदार है। भारत में महिलाओं के भूमि तथा संपत्ति पर अधिकार, केवल वैधानिक अवमानना के उलझे सवाल भर नहीं हैं बल्कि उसका मूल, उस सामाजिक जड़ता में है जिसे आज आधुनिक भारत में नैतिकता के आधार पर चुनौती दिया ही जाना चाहिए। भारत, दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां संवैधानिक प्रतिबद्धता और वैधानिक प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की आधी आबादी आज भी जमीन में कहीं अपनी जड़ों की सतत् तलाश और तराश में है।

11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून 2005 की पुनर्व्याख्या करते हुए एक बार फिर समाज के उस जनमानस को जगाने का प्रयास किया है जो ऐतिहासिक कानून के बाद भी जड़हीन हो चुके (अ) सामाजिक मान्यताओं के मुगालते में जी रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पैतृक संपत्तियों पर बेटी का समान अधिकार है। उत्तराधिकार के वैधानिक प्रावधानों के परिधि में बेटी, जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में कानूनन बराबर की हकदार हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून 2005 लागू होने के पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों का माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार रहेगा। अदालत ने तो यहां तक कहा कि बेटियां, आजीवन हमवारिस ही रहेंगी, उनका यह अधिकार कभी छीना नहीं जा सकता।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में संपत्ति के अधिकारों के जो लाखों



क्या संपत्ति में बेटियों को मिलेगा अधिकार ?

विवाद बरसों से लंबित हैं और जिसकी वजह से लाखों महिलाएं अब भी अपने हकों से मरहूम हैं, वह समाज के जनमानस में बैठे उस सामाजिक जड़ता का प्रतीक है जिसे सदियों से समाज अपने अहंकार में ढो रहा है। इसका परिणाम ही है कि संपत्ति पर अधिकारों के लिए महिलाओं के वैधानिक दावों और नैतिक अनुनयों के बावजूद अब तक मात्र 12 फीसदी महिलाओं को उनका स्थापित अधिकार मिल पाया है। अदालतों में बरसों से लंबित तथाकथित विवादित प्रकरण, उस संकुचित मानसिकता का प्रमाण है जिसे आधी आबादी के अधिकार संपन्न होने से भय और असुरक्षा की आशंका होती है।

भारत के विभिन्न अदालतों में बरसों से लंबित लगभग दो-तिहाई मामले, संपत्ति और भूमि के विवादों से जुड़े हुए हैं। यह वैधानिक जटिलता के साथ-साथ उस सामाजिक मानसिकता और उसके अनिश्चित परिणामों को भी दर्शाता है जो आज भी संपत्ति को अपने सम्मान और अधिकार का विषय तो मानता है लेकिन उसे अपने ही मां, बहन और पत्नी (अर्थात महिलाओं) के साथ साझा नहीं करना चाहता। समाज का यह दोहरा रवैया ही लाखों महिलाओं के अधिकारों को भय और कानून के जटिलताओं में उलझाकर उन्हें वंचित बनाए रखने के लिए जवाबदेह है। भारतीय

प्रशासनिक सेवा संस्थान (भारत सरकार, 2016) द्वारा संपत्ति और भूमि पर महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अध्ययन यह बताता है कि- विभिन्न राज्यों में पूरी भूमि राजस्व व्यवस्था को अब तक महिला भूमि-संपत्ति अधिकारों के अनुरूप ढाला ही नहीं जा सका है। अर्थात् भूमि अधिकारों के लिए जवाबदेह राज्यतंत्रों की प्रशासनिक इकाइयां अब तक, संपत्ति और भूमि के अधिकारों को महिलाओं के लिए सार्थक बनाने की दिशा में आगे बढ़े ही नहीं हैं।

वर्ष 2011 में जब तत्कालीन संसद सदस्य डॉ. एमएस स्वामीनाथन के द्वारा 'महिला कृषक हकदारी कानून' का मसौदा संसद में प्राइवेट मेंबर बिल के बतौर सबके सामने रखा गया, तब भी राजनीतिक बिरादरी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तब से लेकर महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों के तमाम अभियानों के बाद भी अब तक यह, राज्यों के राजनीतिक एजेंडा में शामिल नहीं हो पाया है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर योजनाओं की दुगडुगी बजाने वाले सरकारों के लिए वैधानिक अधिकारों के बजाय, राजनीतिक योजनाओं को वरीयता देने का तार्किक अर्थ है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए अभी लंबा संघर्ष शेष है।

● ज्योत्सना अनूप यादव

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, बैरसिया, जिला-भोपाल

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, रायसेन

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, बेगमगंज, जिला-रायसेन

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, बरेली, जिला-रायसेन

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, गैरतगंज, जिला-रायसेन

सचिव ● भार साधक अधिकारी

रामचरितमानस मात्र साढ़े चार शताब्दी में युगों से जनमानस में स्थापित वाल्मीकि रामायण से अधिक लोकप्रिय हो गई। रामचरितमानस को रामायण कहा गया और समझा जाने लगा। वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने श्रीराम महोत्सव समारोह में इंग्लैंड में कहा था- 'अगर मैं इस देश का अंग्रेज डिक्टेटर होता तो सबसे पहले यह काम करता कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण को जस करने का आदेश जारी करता।' क्या यह बात रामचरितमानस पर लागू नहीं होती? तुलसीदासजी का मानस कलियुग के दोषों को नष्ट कर सबका मंगल करने वाला ही नहीं है, यह तो निरंतर बहने वाली वह निर्मल एवं पवित्र नदी है जिसमें मांसाहारी रावण जैसे मगरमच्छ और शूपर्नखा जैसी मछलियां भी हैं परंतु फिर भी ब्रह्मानंद के आकांक्षी उसमें उतरते हैं, गोता लगाते हैं और अपने हृदय-पात्रों में

भरकर जय-जय सुरनायक जन सुखदायक या नमामि भक्त वत्सलं अथवा भए प्रकट कृपाला दीन दयाला का गायन तन्मय होकर करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी तो पिंजरे के तोता-मैना भी गाते हैं। इससे ज्यादा तुलसीदास और मानस की प्रासंगिकता का सबूत और क्या हो सकता है?

आज मानस और तुलसीदास पर नारी विमर्शवादियों के तीखे आक्रमण होते हैं कि उन्होंने नारी के प्रति न्यायपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं किया। तुलसी ने रामचरितमानस के नारीपात्रों सुनयना, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, अनुसुइया, शबरी आदि के चरित्र में ऋषि चेतना द्वारा प्रदत्त मूल्य, मान, मर्यादा को देखा और प्रशंसनीय भावों को उनसे जोड़ा तथा कामरूपी शूपर्नखा, क्रोधरूपी ताड़कास लोभरूपी मन्थरा और अहंकाररूपी लंकिनी को उचित दण्ड दिलवाया जबकि मोह रूपी त्रिजटा को जगतजननी सीताजी की सेविका के रूप में परिवर्तित होने के कारण छोड़ा क्योंकि जगत में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तो त्यागने ही हैं, पर सात्विक मोह तो प्रभु के साथ जोड़ता है।

रामचरितमानस पर आरोप लगाने वाले अक्सर एक दोहे- ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, को लेकर विवाद खड़ा

आज भी प्रासंगिक है रामचरितमानस



किया करते हैं। इस दोहे को पढ़कर ही उप विधानसभा में रामायण सिंह नामधारी एक विधायक ने रामचरितमानस के पन्ने फाड़ दिए थे। तुलसीदासजी के द्वारा पशु नारी को लेकर जो चिल्ल पाँ हुई वह चिल्ल पाँ गंवार शब्द को लेकर नहीं मचाई। सूकरक्षेत्र शोध संस्थान के अध्यक्ष एवं निदेशक डॉ. नरेश चंद्र बंसल कहते हैं कि - मानस में वर्णित पशु नारी में पशु विशेषण है, जो विशेष्य नारी (नारी जाति) में से पाशवी नारियों अर्थात् पशु प्रवृत्ति की दुश्चरिणी नारियों को फटकार की बात करता है। साहित्य में पशुनारी का ही नहीं पशु नर का भी उल्लेख मिलता है - गिरि ते ऊंचे रसिक मन बूढ़े बहे हजारू। वहै सदा पशु नरन कों, प्रेम पयोधि पगारू (बिहारी सतसई)। इसी प्रकार गंवार शब्द के लिए डॉ. बंसल का कहना है कि गंवार शब्द किसी गांव निवासी या धरतीपुत्र-किसान को प्रयोग नहीं किया गया है, यह ग्रामीण जीवन से भ्रष्ट, अशिक्षित, भोंदू/मूर्ख जैसे नागरिकों के लिए है। तुलसी की भाषा के ज्ञाता स्व. प्रेमनारायण गुप्त ने तुलसीदास जी की भाषा को सौकरवीय भाषा कहा है। सूकरक्षेत्र के तीर्थ पुरोहित गंगागुरुओं के पास सुरक्षित तीर्थ यात्रियों की वहियों में गांव शब्द को गांव व शहर दोनों के लिए प्रयुक्त किया

गया है। इसलिए गंवार गांव का निवासी नहीं है। शूद्र शब्द का भी अर्थ आज की शूद्र जातियां नहीं बल्कि असंस्कारित पुरुष है। हमारे शास्त्रों ने भी संस्कारों से हीन व्यक्ति को ही शूद्र संज्ञा दी है। इस प्रकार देखा जाए तो इन शब्दों में से कहीं भी किसी समुदाय के प्रति कोई बात कही ही नहीं गई है। महाकवि तुलसीदास ने मानस में दुर्गुणों को समाप्त करने के अनेक उपाय बतलाए हैं। वे अपने साहित्य से सभी के लिए कल्याणकारक सन्तप्रवृत्ति के समाज की रचना करने में सफल हुए हैं। उनका संपूर्ण सृजन विशेषतः रामचरितमानस आज ही नहीं, भविष्य में भी उसी प्रकार सदुपयोगी तथा प्रासंगिक रहेगा। जो लोग सत्य और प्रेम सामीप्य का रसानंद पान करना चाहते हैं, शबरी और अहिल्या की भाव विव्धलता उनके विश्वास को दृढ़ करती है- कबहु तो दीनदयाल के भनक परेगी कान। सत्य और प्रेम का निवास पर्णकुटी में हो या निषादराज के यहां; कोल, भील, किरात, वानर, रीछों के साथ हो अथवा ऋषि-मुनियों के आश्रमों में चित्रकूट व पंचवटी में, वहां सभी जीव अपने वैर भाव को नष्ट कर देते हैं।

अवध के सत्ताधीश राम का सामीप्य राम के अनुजों व सीता के अतिरिक्त जिन अन्यो को प्राप्त हुआ वे थे- जामवन्त, अंगद, नल-नील, सुग्रीव व हनुमान आदि। इन सभी ने राम को अपनी कार्यकुशलता से प्रभावित किया था। तभी तो राम ने सभी को सम्मानित किया। उन्होंने अनुजों व सीता को सिंहासन पर स्थान दिया हनुमानजी ने सम्मान में मांगा था- बसहु राम सिय मानस मोरे, इसलिए राम जी ने उन्हें अपने राजसिंहासन के समीप में स्थान दिया। जो सत्ताधीश के मानस में बसते हैं और योग्य हैं, वही सर्वोच्च स्थान पाते हैं। राम ने चयन में नर, रीछ और वानर नहीं देखा, समर्पण देखा। हनुमान के चयन में वशिष्ठ की कोई भूमिका नहीं थी। रामचरितमानस में व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन मिलता है। जो जिस योग्य है, उसे वैसा ही काम दिया गया। जो योग्य नहीं, वह पीछे बैठा दिखता है। इसलिए मानस में जहां वशिष्ठ की आवश्यकता है, वहां सुमंत व हनुमंत भी पीछे हैं।

● ओम

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
कृषि उपज मंडी समिति,
पिपल्या, जिला-मंडसौर
सचिव ● भारत साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
कृषि उपज मंडी समिति,
सैलाना, जिला-रतलाम
सचिव ● भारत साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
कृषि उपज मंडी समिति, ओबेदुल्लागंज, जिला-रायसेन
सचिव ● भारत साधक अधिकारी

भाई



भाई को पता चला कि छोटे की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और वह जीवन और मौत से जूझ रहा है, उसे रहा न गया। अस्पताल जाकर अपनी एक किडनी छोटे भाई को देकर उसकी जान बचाई। होश में आने पर भीगे आंसुओं से छोटे भाई ने कहा, भैया आप।

कि सी बात पर बच्चों की लड़ाई में पहले उनकी मां फिर पिता भी क्रोध पड़े। मामला थाने तक पहुंच गया। थानेदार ने समझा बुझाकर दोनों भाइयों में सुलह करा दी। पर इस घटना के बाद दोनों भाई एक-दूसरे के पक्के दुश्मन बन गए।

घटना के सालों बाद जब बड़े

‘चुप रह छोटे। अभी तू आराम कर। इतनी जल्दी मां से मिलने तुझे अकेले कैसे जाने देता। तुम्हें याद है मां हर रोटी के बराबर दो-दो टुकड़े कर हमें खाने को देती थी, ताकि हमें याद रहे कि हम एक ही डाल के दो पात हैं।’

पीछे खड़े उनके परिवार के सबकी आंखें गीली थीं।

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

15

अगस्त



कृषि उपज मंडी समिति, इंदौर

सचिव

भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, धार

सचिव

भार साधक अधिकारी

15 स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

अगस्त

कृषि उपज मंडी समिति,
बदनावर, जिला-धार

सचिव

भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, खरगौन

सचिव

भार साधक अधिकारी

15 स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

अगस्त

कृषि उपज मंडी समिति,
सैंधवा, जिला-बड़वानी

सचिव

भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, खंडवा

सचिव

भार साधक अधिकारी



स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, भीकनगांव, जिला-खरगौन

सचिव

भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, सांवेर, जिला-इंदौर

सचिव

भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, महू, जिला-इंदौर

सचिव

भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, कुक्षी, जिला-धार

सचिव

भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, मनावर, जिला-धार

सचिव

भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, सनावद, जिला-खरगौन

सचिव

भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, बुरहानपुर

सचिव

भार साधक अधिकारी

PRISM[®]
CEMENT

प्रिज़्म[®] चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.



दूर की सोच[®]

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं जिन्हें तोड़ने के लिए दुनियाभर के बल्लेबाज मैदान पर पसीना बहाते हैं। हालांकि कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त भी हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम इनिंग्स ने 60 शतक जड़ने का

ये रिकॉर्ड कब टूटेंगे ?

अपने 60 अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरे करने के लिए टेस्ट और वनडे मिलकर 426 पारियां खेली थीं। लेकिन 3 ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं जिनका टूटना मुश्किल है।

विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने टेस्ट और वन-डे मिलाकर 386 पारियों में 60 शतक जड़े हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर ने

जिम लेकर के 19 विकेट



पूर्व भारतीय स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले के नाम एक टेस्ट में सभी 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन इंग्लैंड के जिम लेकर ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट में 19 विकेट झटके थे। उन्होंने पहली पारी में 9 और दूसरी पारी में 10 विकेट झटके थे। इस रिकॉर्ड का टूटना असंभव है।

सर जैक होब्स के 199 शतक

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड इंग्लैंड के सर जैक होब्स के नाम दर्ज है। इस महान खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 834 मैच खेलकर 199 शतक लगाए हैं। साथ ही होब्स ने फर्स्ट क्लास मैचों में 61,760 रन भी बनाए हैं, जो कि एक और रिकॉर्ड है। उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। अगर कोई खिलाड़ी इनके इस रिकॉर्ड के पास भी पहुंच जाए तो उसके लिए वह बड़ी उपलब्धि होगी।



ब्रैडमैन की जादुई औसत

क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाज माने जाने वाले सर डॉन ब्रैडमैन को अपनी आखिरी टेस्ट पारी में 100 की औसत पाने के लिए सिर्फ 4 रन की जरूरत थी लेकिन वह जीरो पर आउट हो गए थे। लेकिन टेस्ट में ब्रैडमैन की औसत इसके बावजूद भी 99.94 है। कोई भी बल्लेबाज अब तक इतनी औसत से रन नहीं बना सका है। ब्रैडमैन ने 52 टेस्ट मैचों में 29 शतक और 12 दोहरे शतक की बदौलत 99.94 की जादुई औसत से 6996 रन बनाए हैं।



● आशीष नेमा

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति,
उदयपुरा, जिला-रायसेन

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति,
कुरवाई, जिला-विदिशा

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति,
ब्यावरा, जिला-राजगढ़

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, पचौर, जिला-राजगढ़

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, दलौदा, जिला-मंडसौर

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, सोचकछ, जिला-देवास

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति,
रिवरकिया, जिला-हरदा

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति,
कुरावर, जिला-राजगढ़

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति,
नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति,
बनखेड़ी, जिला-होशंगाबाद

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति,
सेमरीहरवंद, जिला-होशंगाबाद

सचिव ● भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, होशंगाबाद

सचिव ● भार साधक अधिकारी

चुनाव की ऋतु थी, वैसे ही जैसे प्रेम करने की ऋतु होती है, गोलमाल करने की ऋतु होती है, रिश्तव लेने की ऋतु होती है और घी में डालडा और डालडा में चूना मिलाकर बेचने की ऋतु होती है। इसे आप मौसम भी कह सकते हैं। क्षेत्र के सर्वमान्य और सर्वव्यापी नेताजी कुमार केसरी के साथ मैं टहल रहा था और उनके जादुई करतब तथा व्यावहारिक पांडित्य पर मुग्ध हो रहा था। चतुर्दिक मोटरगाड़ियां ध्वनि विस्तारक यंत्रों से सज्जित हो दौड़ रही थीं। चारों ओर चुनावी चर्चा की जायकेदार चटनी से भोजन को सुस्वादु बनाया जा रहा था। मौसम की भविष्यवाणी की भांति चुनाव परिणामों की भविष्यवाणियों की जा रही थीं। कुछ नारे तथा कुछ सुनहरे शब्द हवा में तैर रहे थे। ऐसा लगता था कि चुनाव के उपरांत भारत की गरीबी सात समुंदर पार भाग जाएगी, न कोई भूखा होगा, न ही नंगा। सर्वत्र शांति और सद्भाव का वातावरण व्याप्त हो जाएगा। दूध की नदियां बहेंगी और सोने-चांदी की सड़कें बनेंगी। सचमुच रामराज्य आ जाएगा। पार्टियों के चुनाव कार्यालयों के आगे गांधीजी की तस्वीर टंगी थी तथा कार्यालय के पीछे बम बनाने एवं रुपयों के आदान-प्रदान का अहिंसक कार्यक्रम पूर्ण मनोयोग के साथ संपन्न किया जा रहा था। मोटरगाड़ियों पर तरह-तरह के बैनर और चुनाव चिन्ह टंगे थे। किसी पर 'पीपल छाप' सुशोभित हो रहा था तो किसी मोटरगाड़ी पर 'लालटेन' चमक

रहा था। कहीं 'शेर छाप' बहादुरी की जगह बेचारगी का आभास दे रहा था तो कहीं 'गाय' का प्रतीक सभी समस्याओं का समाधान लेकर प्रस्तुत था। केसरी जी मुझे जीवन रहस्य का बोध करा रहे थे तथा आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर लंबा-सा व्याख्यान दे रहे थे। उसी समय एक शेर ब्रांड गाड़ी आती हुई दिखाई दी। केसरीजी ने जल्दी-जल्दी अपनी कमीज में शेर ब्रांड टांका और जिंदाबाद-जिंदाबाद करने लगे। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि कुछ ही क्षण पूर्व केसरी महोदय 'लालटेन' के समर्थन में नारे बुलंद कर रहे थे और उस दल को अंधकार पर प्रकाश की विजय बता रहे थे। शेर ब्रांड गाड़ी ठहरी और उसमें से गांधी छाप नेताजी ने धरती पर पांव रखा। वे गांधी त्रय (गांधी टोपी, गांधी धोती, गांधी कुर्ता) से सुसज्जित और इत्र में सराबोर थे। जनता की समस्याओं से करुणार्द होकर वे धरती की धूल फांकने आए थे। उन्होंने केसरी जी को हंसी और प्रणाम से उपकृत किया तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। केसरी जी ने नेता का

जनता की समस्याओं से करुणार्द होकर वे धरती की धूल फांकने आए थे। उन्होंने केसरी जी को हंसी और प्रणाम से उपकृत किया तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। केसरी जी ने नेता का पहला गुण प्रकट किया- हां, तबीयत तो ठीक है। अब मेरी तबीयत का क्या ठिकाना? आज हूं, कल नहीं परंतु जाते-जाते जनप्रिय पार्टी और देश के लिए कुछ कर जाना चाहता हूं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी।

तरल पदार्थ



पहला गुण प्रकट किया- हां, तबीयत तो ठीक है। अब मेरी तबीयत का क्या ठिकाना? आज हूं, कल नहीं परंतु जाते-जाते जनप्रिय पार्टी और देश के लिए कुछ कर जाना चाहता हूं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी।

आपके इलाके में मेरी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। नेताजी ने अत्यधिक विनम्रता दिखाते हुए अपना मुंह इस प्रकार बनाया जैसे उनका बाप मर गया हो।

'हां, और सब तो ठीक है परंतु...' केसरी जी ने जानबूझकर वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। 'परंतु-वरंतु क्या?' जहां आप जैसे सक्रिय कार्यकर्ता हों वहां के लिए हम लोगों को चिंता नहीं होती।' नेता जी ने गोली की भांति बात दागी।

'वो तो ठीक है लेकिन भारतीय सर्वहारा पार्टी के लोगों ने जनता को कुछ बहका दिया है। वे दोनों हाथों से पैसे बांट रहे हैं। लोग भी तो कितने स्वार्थी और लालची हो चुके हैं। नैतिकता पाताल में जा रही है, दो-चार पैसों के लिए लोग अपना

ईमान बेच रहे हैं।' केसरी जी की कातरता से ऐसा लग रहा था मानों अखिल विश्व में नैतिकता के वे इकलौते ध्वजधरी हों।

'तो हम लोग भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। आलाकमान का अलिखित आदेश है कि किसी भी कीमत पर विजयश्री हमें मिलनी चाहिए। इस क्षेत्र में हम पैसे बिखेर देंगे। पैसे की आप चिंता न करें। प्रशासन में भी हमारे हैं।' नेताजी ने केसरी जी को आश्चस्त करते हुए रुपए का बंडल थमा दिया।

धूल और भाषण उछालते हुए गाड़ी जब आगे चली गई तो मैंने केसरीजी से पूछा- 'आप तो कुछ देर पहले लालटेन छाप के समर्थन में नारे लगा रहे थे और अब जनप्रिय पार्टी के प्रत्याशी से रुपए...?'

मेरी बात पूर्ण होने से पहले ही उन्होंने गीता के निष्काम कर्मयोग की कलियुगी व्याख्या आरंभ कर दी- 'तुम लोग केवल एमए, बीए कर लेते हो, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का यही तो दुर्गुण है। मुझे किसी पार्टी से क्या लेना-देना! कोई विजयी हो, मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं तो केसरी का केसरी ही रहूंगा। किसी का विरोध करने से मुझे क्या मिलता? मैं तो सर्वदलीय नेता हूं। सभी दलों और खेमों में मेरी पैठ है, कोई भी दल सत्तासीन हो मेरा काम नहीं रुकेगा। किसी सिद्धांत-विद्धांत से मेरा विश्वास नहीं है। सच बात तो यह है कि किसी भी दल का कोई सिद्धांत नहीं है।

जनप्रिय पार्टी भी मेरी अपनी है और सर्वहारा पार्टी से भी मेरी सहानुभूति है। अरे मैं तो तरल पदार्थ हूं तरल... जिस बर्तन में रख दो, मैं उसी का आकार ग्रहण कर लूंगा। मैं निराकार हूँ-निरानंद और निष्काम भी।' केसरी जी के व्याख्यान में उनका आत्मानुभव झलक रहा था।

'लेकिन देशहित में तो यह उचित नहीं है।' मैंने अपना अंतिम तर्क प्रस्तुत किया।

केसरी जी कुछ देर तक मौन रहे, फिर शुरू हो गए- 'देशहित की चिंता किसे है? जो सत्ता में है उसे अपनी तिजोरी भरने से फुसंत नहीं है और जो किसी कारणवश सत्ता से बाहर है, उन्हें हल्ला करने से ही अवकाश नहीं है। वे तब तक शोर मचाते हैं जब तक किसी निगम या आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद पर विराजमान नहीं हो जाते। शीर्ष नेताओं का यह हाल है तो हम लोगों का क्या पूछना?' इतना कह केसरी जी आगे बढ़ गए और मैं खड़ा सोचता रहा कि उनका तरलवाद कितना व्यावहारिक है?...!!!

● वीरेन्द्र परमार

स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...



अपील

- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपनी ढेर पर उपस्थित रहें।

कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन

सचिव

भार साधक अधिकारी

स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...



अपील

- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपनी ढेर पर उपस्थित रहें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- हम्माल तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।

कृषि उपज मंडी समिति, देवास

सचिव

भार साधक अधिकारी

कार्यालय नगर परिषद, जीरापुर, जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) मण्डल

स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...



अपील

- कोरोना के इस संक्रमणकाल के दौरान अपने आसपास साफ-सफाई बनाकर रखें।
- समय पर टैक्स जमा करें।
- सूखा कपड़ा नीले रंग के कपड़ा पात्र तथा गीला कपड़ा हरे रंग के कपड़ा पात्र में ही डालें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद जीरापुर,
जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) मण्डल

कार्यालय नगर पालिका परिषद, सारंगपुर, जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) मण्डल



स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- खुले में शौच न करें, घर और सार्वजनिक स्थानों पर बने शौचालय का उपयोग करें।
- जल कर का भुगतान समय पर करें।
- नगर को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता नियमों का पालन करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सारंगपुर,
जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) मण्डल

कार्यालय नगर पालिका परिषद, नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) मण्डल

अपील

- सूखा कपड़ा नीले रंग के कपड़ा पात्र तथा गीला कपड़ा हरे रंग के कपड़ा पात्र में ही डालें।
- कोरोना के इस संक्रमणकाल के दौरान अपने आसपास साफ-सफाई बनाकर रखें।
- जल कर का भुगतान समय पर करें।

स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...



15
अगस्त

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, नरसिंहगढ़,
जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) मण्डल

कार्यालय नगर पालिका परिषद, ब्यावरा, जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) मण्डल

अपील

- कोरोना के इस संक्रमणकाल के दौरान अपने आसपास साफ-सफाई बनाकर रखें।
- समय पर टैक्स जमा करें।
- सूखा कपड़ा नीले रंग के कपड़ा पात्र तथा गीला कपड़ा हरे रंग के कपड़ा पात्र में ही डालें।



स्वतंत्रता दिवस

की शुभकामनाओं सहित...

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, ब्यावरा,
जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) मण्डल



Science House Medicals Pvt.Ltd.



***For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us***

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023 GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5

Email : shbpl@rediffmail.com PH. : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687